Daily
THE PHOTON NEWS
सच के हक में...
द फोटोन न्यूज Published from Ranchi
Ranchi ● Thursday, 17 April 2025 ● Year : 03 ● Issue : 92 ● Ranchi Edition ● Page : 12 ● Price : ₹3 ● www.thephotonnews.com
E-Paper : epaper.thephotonnews.com

12
Shilpa Shetty's Red Carpet...

SHARE

संसेक्स	:	77,044.29
निफ्टी	:	23,437.20

SARAFA

सोना	:	8,995
चांदी	:	110.00

(नोट : सोना 22 कैरेट प्रति ग्राम)

BRIEF NEWS

सोने ने बनाया नया रिकॉर्ड पहली बार 94 हजार पार

NEW DELHI : बुधवार को सोने के दाम ने नया ऑल टाइम हाई बनाया। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम ₹1,387 बढ़कर ₹94,489 पर पहुंच गया। इससे पहले 10 ग्राम सोने की कीमत ₹93,102 थी। एक किलो चांदी की कीमत ₹373 बढ़कर ₹95,403 प्रति किलो हो गई है। इससे पहले चांदी का भाव ₹95,030 प्रति किलो था। वहीं 28 मार्च को चांदी ने ₹1,00,934 और 11 अप्रैल को सोने ने ₹93,353 का हाई बनाया था। अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी के कारण ट्रेड वॉर का खतरा बढ़ गया है। इससे इकोनॉमी के बढ़ने की रफ्तार धीमी हो सकती है। ग्लोबल मंदी की आशंका भी बढ गई है। ऐसे में लोग सोने में अपना निवेश बढ़ा रहे हैं। मंदी के समय सोने को सुरक्षित निवेश माना जाता है। डॉलर के मुकाबले रुपये के कमजोर होने से सोने की कीमतों में तेजी आई है।

मुर्शिदाबाद के दंगे पूर्व नियोजित : ममता बनर्जी

KOLKATA : बुधवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद में हाल में हुई सांप्रदायिक हिंसा को पूर्व नियोजित करार दिया और साथ ही सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), गृह मंत्रालय के तहत आने वाली केंद्रीय एजेंसियों के एक वर्ग तथा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर कथित तौर पर बांग्लादेश से सीमा पार घुसपैठ कराकर तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने मुस्लिम धार्मिक नेताओं के साथ एक बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दमनकारी वक्फ (संशोधन) अधिनियम को लागू नहीं करने का आग्रह किया और चेतावनी दी कि यह कानून देश को विभाजित करेगा। ममता ने प्रधानमंत्री मोदी से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को नियंत्रण में रखने का अनुरोध किया और उन पर अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए देश को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया।

महादेव सट्टेबाजी एप से जुड़े मामले में कई राज्यों में रेड

NEW DELHI : बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी एप से जुड़े धनशोधन मामले में ईजमाईट्रिप के संस्थापक निशांत पिट्टी के कई राज्यों में स्थित ठिकानों पर फिर से छापेमारी की। ईडी की यह छापेमारी दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, अहमदाबाद, इंदौर, जयपुर, चेन्नई और ओडिशा के संबलपुर स्थित ठिकानों पर हुई। आधिकारिक ने बताया कि ईडी ने महादेव सट्टेबाजी एप से जुड़े धनशोधन मामले में निशांत पिट्टी के ठिकानों सहित कई राज्यों में नए सिरे से छापेमारी की। ईडी इसके पहले भी इस मामले में छापेमारी कर चुकी है। यह मामला तब सामने आया था जब ईडी ने कुछ साल पहले दावा किया था कि छत्तीसगढ़ के कई राजनेता और नौकरशाह एप से जुड़े अवैध संचालन और उसके बाद हुए मौद्रिक लेनदेन में कथित रूप से शामिल हैं।

सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ में वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा-

क्या मुस्लिम लोग हिंदू ट्रस्ट का होंगे हिस्सा

NEW DELHI @ PTI : बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान केंद्र से पूछा कि क्या मुसलमानों को हिंदू धार्मिक ट्रस्टों का हिस्सा बनने की अनुमति दी जाएगी। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ को कैसे अस्वीकृत किया जा सकता है, क्योंकि कई लोगों के पास ऐसे वक्फों को पंजीकृत कराने के लिए अपेक्षित दस्तावेज नहीं होंगे। उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ से तात्पर्य ऐसी प्रथा से है, जिसमें किसी संपत्ति को धार्मिक या धर्मार्थ बंदोबस्ती (वक्फ) के रूप में मान्यता उसके ऐसे प्रयोजनों के लिए दीर्घकालिक, निर्बाध उपयोग के आधार पर दी जाती है, भले ही मालिक द्वारा वक्फ की कोई औपचारिक, लिखित घोषणा न की गई हो। पीठ ने कहा, आप उपयोगकर्ता द्वारा ऐसे वक्फ को कैसे पंजीकृत करेंगे। उनके पास कौन से दस्तावेज होंगे। इससे कुछ पूर्ववत हो जाएगा। हां, कुछ दुरुपयोग है। लेकिन, वास्तविक भी हैं। मैंने प्रिवी काउंसिल के फैसलों को भी पढ़ा है। उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ को मान्यता दी गई है। यदि आप इसे पूर्ववत करते हैं तो यह एक समस्या होगी। विधायिका किसी निर्णय, आदेश या डिक्री को शून्य घोषित नहीं कर सकती। आप केवल आधार ले सकते हैं।

कोर्ट ने जोर देकर कहा- विधायिका किसी निर्णय, आदेश या डिक्री को नहीं घोषित कर सकती शून्य

आप अतीत को दोबारा नहीं लिख सकते : पीठ

कोर्ट में मेहता ने कहा कि मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग वक्फ अधिनियम के तहत शासित नहीं होना चाहता। पीठ ने इसके बाद मेहता से पूछा, क्या आप यह कह रहे हैं कि अब से आप मुसलमानों को हिंदू बंदोबस्ती बोर्ड का हिस्सा बनने की अनुमति देंगे। इसे खुलकर कहें। पीठ ने कहा, आप अतीत को दोबारा नहीं लिख सकते। मेहता ने कहा कि संयुक्त संसदीय समिति ने 38 बैठकें की और संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके पारित होने से पहले 98.2 लाख ज्ञापनों की पड़ताल की।

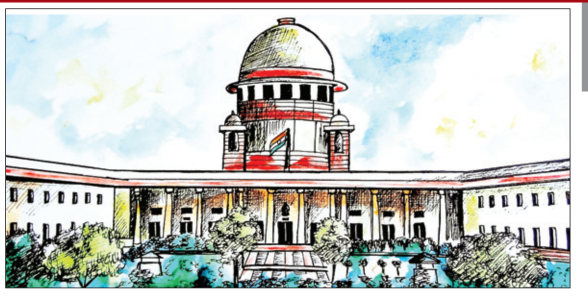

हम दोनों पक्षों से करना चाहते हैं बात : प्रधान न्यायाधीश

प्रधान न्यायाधीश खन्ना ने यह भी कहा कि एक उच्च न्यायालय को इन याचिकाओं पर विचार करने के लिए कहा जा सकता है। उन्होंने कहा, दो पहलू हैं जिन पर हम दोनों पक्षों से बात करना चाहते हैं। सबसे पहले, क्या हमें इस पर विचार करना चाहिए या इसे उच्च न्यायालय को सौंप देना चाहिए। दूसरा, संक्षेप में बताएं कि आप वास्तव में क्या आग्रह कर रहे हैं और क्या तर्क देना चाहते हैं। हम यह नहीं कह रहे हैं कि कानून के खिलाफ

दोनों सदनों से कानून पारित होने से पहले की गई 98.2 लाख ज्ञापनों की पड़ताल : एसजी

5 वर्षों से इस्लाम का पालन करने का मुद्दा

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने वक्फ संशोधन अधिनियम का हवाला दिया और कहा कि वह उस प्रावधान को चुनौती दे रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि केवल मुसलमान ही वक्फ कर सकते हैं। सिब्बल ने पूछा, सरकार कैसे तय कर सकती है कि मैं मुसलमान हूं या नहीं और इसलिए वक्फ करने का पात्र हूं या नहीं। उन्होंने कहा, सरकार यह कैसे कह सकती है कि केवल वे लोग ही वक्फ कर सकते हैं, जो पिछले पांच वर्षों से इस्लाम का पालन कर रहे हैं। कुछ याचिकाकताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि वक्फ अधिनियम का प्रभाव पूरे भारत में होगा और याचिकाओं को उच्च न्यायालय को नहीं भेजा जाना चाहिए। वक्फ अधिनियम का विरोध करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने कहा कि उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ करना इस्लाम की एक स्थापित प्रथा है और इसे छीना नहीं जा सकता। बता दें कि केंद्र ने हाल ही में वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 को अधिसूचित किया, जिसे दोनों सदनों में तीखी बहस के बाद संसद से पारित होने के बाद पांच अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई।

अगले सीजेआई के रूप में न्यायमूर्ति बीआर गवई की नियुक्ति की सिफारिश

सीजेआई संजीव खन्ना ने केंद्रीय कानून मंत्रालय से उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई को अगला सीजेआई नियुक्त करने की सिफारिश की।

न्यायमूर्ति गवई मौजूदा सीजेआई के बाद उच्चतम न्यायालय में वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं। वह 14 मई को 52वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे।

जेएमएम का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद सीएम ने जाहिर की भावना

राज्य के हर गरीब, वंचित व युवा की आवाज बनने की ली है शपथ : हेमंत

PHOTON NEWS RANCHI : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का अध्यक्ष बनाए जाने पर इसे गर्व का क्षण बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि आज जब मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष पद का दायित्व संभाल रहा हूं, तो मेरे मन में अनेक भावनाएं उमड़ रही हैं। यह कोई साधारण पद नहीं, बल्कि झारखंड की जनता के सपनों, संघर्षों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व है। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) का अध्यक्ष चुने जाने के एक दिन बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के हर गरीब, वंचित और युवा की आवाज बनने की शपथ ली। झामुमो अध्यक्ष का पद पहले उनके पिता शिबू सोरेन के पास था। सोरेन ने लिखा है कि एक पोस्ट में कहा कि आदरणीय बाबा, हमारे संरक्षक आदरणीय शिबू सोरेन जी ने जिन विचारधाराओं की छांव तले झामुमो की नींव रखी थी, आज उसे आगे बढ़ाने का अवसर मिलना मेरे लिए गर्व का क्षण है। मैं विनम्रतापूर्वक इस जिम्मेदारी को स्वीकार करता हूं। साथ ही प्रण लेता हूं कि झारखंड के हर गांव, हर गरीब, हर वंचित और हर युवा की आवाज बनूंगा। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का इतिहास संघर्षों से भरा है, लेकिन हमारा संकल्प अडिग है। आज फिर से हमें एकजुट होकर झारखंड की अस्मिता, विकास और न्याय के लिए संघर्ष करना है। मैं सभी कार्यकताओं, नेताओं और राज्यवासियों से वादा करता हूं कि आपका विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगा।

झारखंड की जनता के सपनों-संघर्षों का प्रतिनिधित्व है झामुमो का अध्यक्ष बनना

फरियादी की समस्यां सुनते सीएम हेमंत सोरेन।

राज्य का शोषण करने की अनुमति नहीं

बता दें कि मंगलवार को संपन्न हुए दो दिवसीय केंद्रीय सम्मेलन के दौरान हेमंत सोरेन ने झामुमो के लिए एक मजबूत सामाजिक न्याय एजेंडा पेश किया, जिससे पार्टी के राज्य से बाहर अपने प्रभाव का विस्तार करने के इरादे का संकेत मिलता है। उन्होंने घोषणा की कि सामंती ताकतों को अब राज्य का शोषण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हेमंत सोरेन ने संकेत दिया कि पार्टी राज्य में 2024 के विधानसभा चुनाव में अपने मजबूत प्रदर्शन से उत्साहित होकर अपनी राष्ट्रीय भूमिका को फिर से परिभाषित करने के लिए तैयार है।

सामंती ताकतों को जनता के हाथों मिली करारी हार

हेमंत सोरेन ने कहा कि यह सरकार जनता की है। सामंती ताकतों को यहां की जनता के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा। झामुमो एक शक्तिशाली ताकत के रूप में उभरा है, झामुमो उन्हें झारखंड को और लूटने नहीं देगा। उन्होंने कहा कि उनके पिछले शासन के दौरान भाजपा ने उनकी लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कई षड्यंत्र रचे, लेकिन झामुमो सरकार ने लगातार राजनीतिक दबाव का सामना किया और यह अपने लोगों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अंत में लिखा, जय जोहार! जय झारखंड।

आम लोगों से मिले मुख्यमंत्री, सुनी समस्याएं

मंगलवार को झारखंड मृत्यु मोर्चा का केंद्रीय अध्यक्ष बनने के बाद बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने कांके रोड स्थित आवास पर पहली बार आम लोगों से मिले। उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनीं और उनकी परेशानियों को समझा। इस दौरान उन्होंने लोगों से आवेदन भी प्राप्त किए और संबंधित

अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए।

चीन के 125% के जवाब में ट्रंप का 245% टैरिफ

NEW DELHI : अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वॉर और आगे बढ़ गई है। अमेरिका ने अब चीन पर 100 प्रतिशत और टैरिफ लगा दिया है। इसके साथ अमेरिका इम्पोर्ट होने वाले चीनी सामान पर कुल टैरिफ 245 प्रतिशत हो गया है। चीन ने 11 अप्रैल को अमेरिकी सामान पर 125 प्रतिशत टैरिफ लगाया था, जिसके जवाब में ट्रंप ने नया टैरिफ लगाया है। इससे पहले चीन ने कहा था कि अब वह अमेरिका की तरफ से लगाए जाने वाले किसी भी अतिरिक्त टैरिफ का जवाब नहीं देगा। अमेरिका की तरफ से नए टैरिफ के ऐलान के बाद चीन ने कहा कि हम अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर करने से नहीं डरते। चीन ने दोबारा कहा कि अमेरिका को बातचीत करनी चाहिए। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि चीन को बातचीत की शुरूआत करनी होगी।

चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली बेंच में सुनवाई

बड़ा तालाब व हरमू नदी की सफाई पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

PHOTON NEWS RANCHI : बुधवार को हाइकोर्ट में जल स्त्रोतों, नदी, रांची के बड़ा तालाब के साफ-सफाई एवं संरक्षण के संबंध में कोर्ट के स्वतः संज्ञान की सुनवाई हुई। मामले में चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार से रांची के बड़ा तालाब एवं हरमू नदी की साफ-सफाई पर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 9 जून को होगी। कोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ा तालाब से गाद निकालने और हरमू नदी की सफाई के संबंध में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। सरकार की ओर से बताया गया कि सभी जिलों से जल स्त्रोतों से अतिक्रमण हटाने के संबंध में गठित टास्क फोर्स की रिपोर्ट अभी नहीं आई है, कुछ जिलों से रिपोर्ट आना बाकी है।

9 जून को होगी इस मामले की अगली हियरिंग

सफाई से संबंधित फोटोग्राफ किया गया प्रस्तुत

इससे पूर्व रांची नगर निगम की ओर से अधिवक्ता एलसीएन शाहदेव ने कोर्ट को बताया कि बीते 10-11 अप्रैल को निगम की ओर से हरमू नदी की सफाई कराई गई है, निगम की ओर से समय-समय पर हरमू नदी की सफाई का कार्य किया जा रहा है। इस संदर्भ में उनकी ओर से हरमू नदी की सफाई से संबंधित फोटोग्राफ प्रस्तुत किया। कोर्ट ने निगम को मौखिक रूप से कही गई इन बातों को शपथ पत्र के माध्यम से दाखिल करने का निर्देश दिया। हस्तक्षेपकर्ता झारखंड सिविल सोसाइटी की ओर से अधिवक्ता खुशबू कटारुका ने कोर्ट को बताया गया कि बड़ा तालाब में जब तक इसकी गहराई में जमे गाद को नहीं हटाया जाएगा, तब तक पूरी तरह से बड़ा तालाब की सफाई नहीं हो सकेगी।

शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण हादसा : तेजी से झुग्गी इलाके में फैल गई आग

आग की चपेट में आकर 4 बच्चों समेत 5 की मौत

AGENCY MUJAFFARPUR : बिहार के मुजफ्फरपुर में दर्दनाक हादसा हो गया। बुधवार को एक दलित बस्ती में भीषण आग लग गई। इस अगलगी में 50 से अधिक घर जल गए। हादसे में 4 बच्चों समेत 5 लोगों की झुलसकर मौत हो गई है। घटना बरियारपुर थाना क्षेत्र के रामपुर मनी पंचायत की है। बताया जा रहा है कि गोलक पासवान के घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और देखते ही देखते पूरे झुग्गी के इलाके में फैल गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि राजू पासवान नामक व्यक्ति के 3 बच्चों की झुलसकर मौत हो गई है। इन बच्चों की उम्र 12 साल, आठ साल और नौ साल है। घटना के बाद अफरा-तफरी मच गई है।

अगलगी में जल गए 50 से अधिक घर, एक ही परिवार के हैं सभी मृतक बच्चे

परिवार को दी जाएगी 4-4 लाख मुआवजा राशि

ग्रामीणों ने पुलिस और अग्निशमन को आग लगने की सूचना दी। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि यह दुखद घटना है, अगलगी की घटना में चार बच्चों की मौत हुई है, सभी एक ही परिवार के हैं। कानून प्रक्रिया के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा सभी मृतकों के परिवार को 4-4 लाख मुआवजा राशि दी जाएगी। जिनका घर जला है, उनके लिए भोजन की व्यवस्था की जाएगी।

घटना के बाद गमगीन हो गया पूरा गांव

आग लगी की घटना के बाद पूरा गांव गमगीन हो गया। स्थानीय शिवप्रसाद पासवान ने बताया कि घटना के समय गांव के ज्यादातर लोग खेत में मजदूरी करने के लिए गए थे। बिजली का तार टूट कर घर पर गिर गया। इस वजह से आग लगी। जब तक लोग दौड़कर आते, तब आग काफी तेजी से फैल चुकी थी।

लापरवाही केंद्र सरकार की ओर से नाराजगी जताने के बावजूद कोई असर नहीं

देश में अंग प्रत्यारोपण को लेकर पारदर्शिता नहीं बरत रहे अस्पताल

PHOTON NEWS @ RESEARCH DESK : अनेक स्वास्थ्य संबंधी विसंगतियां और बीमारियों की वजह से शरीर के अंगों को बदलने की जरूरत पड़ती है। मेडिकल साइंस में यह सर्जरी की जटिल प्रक्रिया मानी जाती है। इसके साथ ही यह भी आवश्यक होता है कि अगर किसी मरीज का कोई अंग काम नहीं करता है, तो किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा अंगदान के बाद ही अंग प्रत्यारोपण की प्रक्रिया संभव है। अंग प्रत्यारोपण संबंधी कानून का पालन और इस संबंध में अस्पतालों द्वारा पूरी पारदर्शिता बरतने की आवश्यकता होती है। ब्रेनडेड की स्थिति में बहुत से लोग अंगदान करते हैं और इससे दूसरे लोगों को नया जीवन मिलता है। यही कारण है कि केंद्र सरकार की ओर से अंगदान को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है। बता दें कि देश में अंग प्रत्यारोपण को लेकर पारदर्शिता बरतने के लिए अस्पतालों के व्यवहार पर केंद्र सरकार ने नाराजगी जताई है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए यह दुखद पहलू है कि बीते 15 महीनों में तीन बार आदेश देने के बाद भी ज्यादातर अस्पतालों ने अंग प्रत्यारोपण से जुड़ी अहम जानकारियां साझा नहीं की।

बीते 15 महीनों में तीन बार आदेश जारी होने पर भी नहीं दी गई जानकारी

राष्ट्रीय अंग व ऊतक प्रत्यारोपण संगठन की ओर से व्यक्त की गई है गंभीर चिंता

- 48 घंटे में दाता और अंग ग्राही के बारे में जरूरी जानकारियां देना अनिवार्य
- राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों को पत्र लिखकर जानकारी नहीं देने की कही गई है बात
- अस्पतालों का रवैया अंगदान को बढ़ावा देने के व्यापक उद्देश्य को कर रहा बाधित

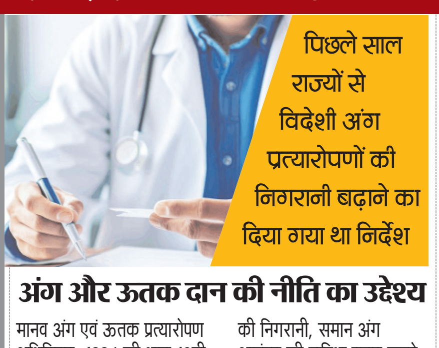

पिछले साल राज्यों से विदेशी अंग प्रत्यारोपणों की निगरानी बढ़ाने का दिया गया था निर्देश

अंग और ऊतक दान की नीति का उद्देश्य

मानव अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 की धारा 13डी के तहत नोटो को राष्ट्रीय प्रत्यारोपण रजिस्ट्री की जिम्मेदारी सौंपी है, जो अंग और ऊतक प्रत्यारोपण गतिविधियों की निगरानी, समान अंग आवंटन की सुविधा प्रदान करने के साथ-साथ देश में अंग और ऊतक दान को बढ़ाने के लिए नीति निर्माण का समर्थन करने के लिए आवश्यक है।

दैनिक और मासिक जानकारी

जानकारी के अनुसार, नोटो ने अपने ताजा आदेश में दिसंबर 2023 से अब तक जारी आदेशों का हवाला देते हुए कहा, प्रत्यारोपण करने वाले अस्पतालों को 48 घंटे में दाता और अंग ग्राही के बारे में जरूरी जानकारियां देना अनिवार्य है। इस संबंध में सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों को भेजे चौथे पत्र में कहा है कि कई अस्पताल अंग प्रत्यारोपण गतिविधियों की दैनिक और मासिक जानकारी नहीं दे रहे हैं। यह राष्ट्रीय प्रत्यारोपण रजिस्ट्री पर प्रत्यारोपण को रजिस्टर्ड करने में भी विफल रहे हैं। ऐसी लापरवाही पूरे सिस्टम को को कमजोर कर रही है। इससे देशभर में अंगदान को बढ़ावा देने के व्यापक उद्देश्य पर भी प्रभाव पड़ रहा है। बता दें कि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक डॉ. अतुल गोयल ने 2024 में एक आदेश जारी कर भारत में बढ़ते विदेशियों के अंग प्रत्यारोपण पर चिंता जताते हुए राज्यों से ऐसे प्रत्यारोपणों की निगरानी बढ़ाने को कहा था।

पाप पर पर्दा डालने के लिए कांग्रेस को निशाना बना रही सरकार : खड़गे

NEW DELHI : बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडधगे ने नेशनल हेराल्ड मामले का परोक्ष रूप से हवाला देते आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली निरंकुश सरकार अपने पाप पर पर्दा डालने के लिए उनकी पार्टी को निशाना बनाने पर तुली हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस डरने वाली नहीं है और वह सरकार की नाकामियों को उजागर करती रहेगी। खरगे ने एक्स पर पोस्ट किया, नरेन्द्र मोदी जी, आपकी निरंकुश सरकार अपने पाप पर पर्दा डालने के लिए कांग्रेस को निशाना बनाने पर तुली हुई है। भाजपा का आर्थिक कुप्रबंधन नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है। हताशा बढ़ती जा रही है, कोई दृष्टि नहीं, कोई समाधान नहीं, केवल ध्यान भटकाना। उन्होंने दावा किया कि व्यापार घाटा तीन साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है और टैरिफ एवं व्यापार युद्ध पर कोई स्पष्टता नहीं दिख रही है।

सुरक्षाबलों की अलग-अलग जगहों पर कार्रवाई

मणिपुर में विभिन्न स्थानों से अरेस्ट किए गए 11 उग्रवादी

AGENCY IMPHAL : बुधवार को मणिपुर पुलिस और केंद्रीय सुरक्षाबलों ने अलग-अलग स्थानों से प्रतिबंधित संगठनों के 11 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से हथियार, मोबाइल फोन, वाहन व अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई है। मणिपुर पुलिस ने बुधवार को बताया कि थौबल जिले के हिरोक थाना क्षेत्र के सलुंगफम ममांग लाईकाई बाजार के पास से केसीपी (अपुनबा सिटी मैतेई) के चार उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार उग्रवादियों की पहचान मो. सारुक खान (34, थौबल वांगखेम), संगोमसंबम अख्तर अहमद (29, थौबल वांगखेम), कोंजेंगबम कुमारजीत सिंह (41, नंबोल लैमैपोकपम अवांग लाईकाई, बिष्णुपुर) तथा लैश्रम जयमंगल सिंह (47, कैरेम्बिखोक ममांग लाईकाई) थौबल के रूप में हुई है।

● हथियार, मोबाइल फोन, वाहन व अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद

BRIEF NEWS

महिला क्रिकेट में बोकारो ने जमशेदपुर को हराया

CHAIBASA : खब्बू स्पिनर रिन्नी बर्मन की घातक गेंदबाजी (15/5) एवं शशि माथुर की शानदार अर्द्धशतकीय पारी (55 रन) की बदौलत बोकारो ने जमशेदपुर को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही बोकारो के 4 अंक हो गए और अंक तालिका में अपने दोनों सुपर डिवीजन के मैच खेलकर एक जीत तथा एक हार के साथ पहले स्थान पर है। हालांकि पश्चिमी सिंहभूम के भी चार अंक हैं, पर बेहतर नेट रनरेट के कारण बोकारो शीर्ष स्थान पर है। चाईबासा के बिरसा मुंडा क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में टॉस बोकारो के कप्तान ने जीता तथा विपक्षी टीम जमशेदपुर को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उनका यह निर्णय सही साबित हुआ, जब जमशेदपुर की पूरी टीम 47.5 ओवर में मात्र 99 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। निर्धारित लक्ष्य का पीछा करने उतरी बोकारो की टीम ने 15.4 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 100 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। अब गुरुवार को पश्चिमी सिंहभूम और जमशेदपुर के बीच खेले जाने वाले सुपर डिवीजन के अंतिम मैच में यह निर्णय होगा कि इस ग्रुप से कौन सी टीम फाइनल मुकाबले में पहूंचेगी। कल अगर पश्चिमी सिंहभूम की टीम जमशेदपुर को पराजित कर देती है तो आठ अंकों के साथ उसका फाइनल खेलना पक्का हो जाएगा, परंतु अगर पश्चिमी सिंहभूम की टीम हारती है तो तीनों टीमों (क्रमशः बोकारो, पश्चिमी सिंहभूम एवं जमशेदपुर) के बराबर अंक हो जाएंगे और बेहतर रन रेट रखने वाली टीम फाइनल में क्वालीफाई करेगी।

ईडी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन

KHUNTI : अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर केंद्र सरकार के खिलाफ खूंटी जिला कांग्रेस कमेटी कें अध्यक्ष रवि मिश्रा के नेतृत्व में बुधवार को समाहरणालय के पास धरना दिया गया और प्रदर्शन किया गया। मौके पर जिला अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र की सरकार संपूर्ण विपक्ष से घबराकर ऐसी हरकत कर रही। सरकार विपक्ष के नेता राहुल गांधी से घबराकर ऐसा काम कर करने को मजबूर हैं। मिश्रा ने कहा कि केंद्र सरकार केवल और केवल अपने लोगों को फायदा पहुंचा रही है, भले ही देश गर्त में चला जाये। इन्हें केवल अपने लोगों से मतलब है, देश की जनता से कोई मतलब नहीं। मौके पर प्रदेश सचिव पीटर मुंडू, सहकारिता प्रकोष्ठ के महासचिव नईमुद्दीन खां, प्रदेश आदिवासी कांग्रेस के उपाध्यक्ष विलसन तोपनो, जिला प्रवक्ता रविकांत मिश्रा, फिरोज आलम, अरुण सांगा, सोहेल अंसारी, जेम्स तोपनो, जुलियस कंडुलना, फुलचंद टूटी, राम तिड़ू, ऐलेक्सियूस भेंगरा, मगरीता खेस, जुनैद खान, सुचित सांगा, ऐलेक्सियूस परधिया, सुषमा भेंगरा, शांता खाखा, हेलेन तिड़ू, इंदुआन्ना हस्सा, अनिता नाग, सुंदरमनी हंस, विक्रम नाग सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे।

आदित्यपुर से 137 यात्रियों को लेकर खुली टाटा-हटिया मेमू

JAMSHEDPUR : आदित्यपुर रेलवे स्टेशन से बुधवार को टाटा-हटिया मेमू का परिचालन शुरू हो गया। बुधवार सुबह 4.37 बजे ट्रेन नंबर- 68036 टाटा-हटिया मेमू खुली। पहले दिन 137 यात्री आदित्यपुर से ट्रेन में सवार हुए, 3790 रुपसे की टिकट बिक्री हुई। आमतौर पर इस ट्रेन में टाटानगर और आदित्यपुर मिलाकर औसतन 65-70 यात्री ही यात्रा करते हैं। पहले ही दिन लगभग दोगुने यात्रियों के जाने से रेलवे प्रशासन भी उत्साहित है। टाटानगर स्टेशन से कमर्शियल विभाग के कर्मचारियों ने टाटानगर पहुंचे लगभग 20 यात्रियों को आदित्यपुर स्टेशन भेजा, ताकि वे ट्रेन पकड़ सकें। वर्षों से आदित्यपुर से ट्रेनों के परिचालन की मांग कर रहे झारखंड चेतना मंच और स्थानीय लोगों ने ट्रेन के चालक और गार्ड को माला पहनाकर सम्मानित किया। झारखंड चेतना मंच के अध्यक्ष सुरेश धारी ने रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों से अपील की कि आदित्यपुर स्टेशन से और भी प्रमुख ट्रेनों का परिचालन जल्द शुरू किया जाए।

सांसद ने किया हंटरगंज प्रखंड का दौरा

CHATRA : सांसद कालीचरण सिंह ने बुधवार को हंटरगंज प्रखंड के कई गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ शोकाकुल परिवारों से मुलाकात की बल्कि ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनीं और समाधान का भरोसा दिलाया। दौरे की शुरूआत सिंह ने कल्याणपुर गांव से की। वे स्वर्गीय अमरेश सिंह के घर पहुंचे। उन्होंने परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया और आर्थिक सहयोग भी दिया। गांव में बिजली और सड़क की समस्या पर ग्रामीणों से बातचीत कर मौके पर ही अधिकारियों से समाधान को लेकर बात की।

रील बनाने के दौरान 30 फीट की ऊंचाई से गिरा किशोर, हुई मौत, मचा कोहराम

बेरमो के कारीपानी स्थित बंद पड़े कोल हैंडलिंग प्लांट के सेलो एरिया में हुई घटना

PHOTON NEWS BOKARO : इंटरनेट मीडिया में वायरल होने की चाहत में बेरमो के कारीपानी निवासी एक किशोर की जान चली गई। चंद्रपुरा थाना अंतर्गत मकोली ओपी थाना क्षेत्र के कारीपनी स्थित बंद कोल हैंडलिंग प्लांट (सीएचपी) के सेलो एरिया में लगभग 30 फीट ऊपर चढ़कर रील बनाने के दौरान कारीपानी निवासी अंबिका चौहान का 17 वर्षीय पुत्र पंकज चौहान गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पंकज को घायल अवस्था में उपचार के लिए अनुमंडल अस्पताल फुसरो पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। स्वजनों के अनुसार घटना में पंकज के हाथ,

अस्पताल पहुंचे परिजन

पैर सहित पसली भी टूट गई थी। घटना के संबंध में बताया जाता है कि बंद कोल हैंडलिंग प्लांट के सेलो एरिया में आए दिन कॉलोनी के बच्चे खेलने व रील बनाने के लिए जाते हैं। बुधवार को भी पंकज चौहान अपने दोस्तों के साथ रील बनाने के लिए प्लांट के सेलो एरिया में ऊपर चढ़ा हुआ था। तभी उसका संतुलन बिगड़ गया और वह 30 फीट की ऊंचाई से गिर गया। नीचे पेड़ से टकराने से उसके सिर पर गंभीर चोटें आईं और वह लहूलुहान हो गया। आनन-फानन में लोगों ने उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। मृतक के पिता अंबिका चौहान ने बताया कि पंकज खेलने के लिए घर से बाहर निकला था। बाद में उसके दोस्तों से दुर्घटना में घायल होने की जानकारी मिली। अस्पताल आने पर उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पूरी कॉलोनी में मातम पसरा हुआ है। मृतक पंकज चौहान चार भाई व एक बहन में सबसे छोटा था। मृतक के पिता अंबिका चौहान रोड सेल में मजदूरी करते हैं। मामले की जानकारी स्थानीय थाना को दे दी गई है।

चोरों ने डेली मार्केट की चार दुकानों का तोड़ा ताला

दुकान में चोरी के बाद बिखरे सामान

RAMGARH : रामगढ़ शहर में चोरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। इस बार चोरों ने पुराने बस स्टैंड के डेली मार्केट में चार दुकानों का ताला तोड़ दिया। चारों दुकान से लगभग 50 हजार रुपए की संपत्ति के चोरी होने का अनुमान है। घटना की सूचना मिलते ही बुधवार को रामगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की तफ़्तीश शुरू कर दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि चोरों ने इस घटना को अंजाम देने के लिए वहां लगे सीसीटीवी कैमरे को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। रामगढ़ थाना के सब इंस्पेक्टर बीरबल हेंब्रम इस पूरे मामले की तस्वीर कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार चोरों ने कॉस्मेटिक और मोबाइल दुकान से कीमती सामान उड़ा लिया। सुनील कुमार के मोबाइल दुकान से लगभग 30 हजार रुपए की संपत्ति चोरी हुई है। यहां से नए और पुराने मोबाइल, ब्लूटूथ, स्पीकर और इयरबड की चोरी की गई इसके अलावा मो सोहेल और मो फिरोज के कॉस्मेटिक दुकान से लगभग 10 से 15 हजार की संपत्ति के चोरी होने का अनुमान है। मोहम्मद जावेद की दुकान का भी ताला चोरों ने तोड़ दिया। दुकानदारों ने पुलिस को बताया कि चोरी के लिए छावनी परिषद के कर्मचारी जिम्मेदार हैं। उन्होंने बताया कि पुराने बस स्टैंड में लगने वाले डेली मार्केट में छावनी परिषद के जरिये दुकान बनाया गया था। दुकान में लगाया गया शटर बेहद कमजोर है। यहां तक कि उसका लॉक भी बेहद ऑर्डिनरी है। इस लॉक को लेकर पहले भी शिकायत छावनी परिषद के अधिकारियों से की गई थी। बैंक का लोन लेकर दुकान तो व्यापारियों ने ले लिया, लेकिन सुरक्षा मानकों पर दुकान खरा नहीं उतर रहा। अब छावनी परिषद के अधिकारियों के लापरवाही का खामियाजा दुकानदारों को भुगतना पड़ रहा है। बेहद आराम से चोर लॉक तोड़ रहे हैं और उनका कीमती सामान चोरी कर ले रहे हैं।

कोडरमा में मिला विवाहिता का शव, हत्या का आरोप

AGENCY KODERMA : जिले के डोमचांच प्रखंड अंतर्गत फुलवरिया पंचायत के ग्राम बिगहा मे बुधवार सुबह एक घर से संदिग्ध अवस्था में विवाहित महिला का शव बरामद हुआ है। मृतका की पहचान ललिता देवी (30) के रूप मे हुई है। महिला के ससुराल वालों के अनुसार महिला का शव दुपट्टा के सहारे ऊपर लटका हुआ था, उसने खुदकुशी कर ली। वहीं दूसरी ओर मायके वालों ने हत्या का आरोप लगाते हुए बताया कि ललिता देवी की विवाह 2011 में प्रेम विवाह हुआ था। इसके बाद से ही दोनों के बीच आए दिन विवाद होते रहता था। साथ ही बताया कि 2016 मे भी अपेंडिक्स की दवा के साथ मिलाकर जहर खिला दिया गया था। लेकिन मायके वालों की ओर से सदर अस्पताल ले जाया

घटना के बाद जुटे लोग व इनसेट में मृतक की फाइल फोटो • फोटोन न्यूज

गया था जहां स्वस्थ हुई थी। जिसके कुछ साल बाद फिर एक बार जहर देकर मारने का प्रयास किया गया था परंतु उस समय भी सदर अस्पताल में ही ठीक हुई थी। मायके वालों ने बताया कि इस बार रस्सी के सहारे गला दबाकर हत्या कर दिया गया और उसे खुदकुशी का रूप दिया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि मृतका को नौ वर्ष का पुत्र और 12 वर्ष की एक पुत्री है। घटना की सूचना मिलते ही नवलशाही पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल कोडरमा भेज दिया है। दूसरी ओर पुलिस घटना की जांच पड़ताल कर रही है।

आपस में भिड़े कांग्रेसी पत्रकार भी हुए जख्मी

DHANBAD : रणधीर वर्मा चौक स्थित प्रेस क्लब के पास बुधवार शाम 4 बजे कांग्रेसी आपस में भिड़ गए। कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष राशीद रजा अंसारी के पुत्र सैफ अंसारी की एक अन्य कांग्रेसी नेता के साथ मारपीट हो गई। मारपीट इतनी बढ़ गई कि रॉड से हमला कर दिया गया। हमले में कुछ कांग्रेसी भी घायल हुए। मारपीट के दौरान एक पत्रकार पर भी हमला कर दिया गया। पत्रकार जख्मी हो गया है। यह घटना तब हुई, जब कांग्रेस कार्यकर्ता ईडी के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन में शामिल थे। बताया जाता है कि उसी दौरान दो गुट में किसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई थी। फिलहाल घटना का कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। मामले की जानकारी मिलते ही प्रेस क्लब के पास काफी भीड़ जुट गई। सूचना पाकर काफी संख्या में पुलिस बल भी पहुंच गए। उन्होंने स्थिति को नियंत्रित किया।

फूलो-झानो मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने ओपीडी सेवा कर दी ठप

धरना पर बैठीं मेडिकल कॉलेज की छात्राएं • फोटोन न्यूज

DUMKA : फूलो झानो मेडिकल कॉलेज के छात्र-छात्राओं ने कॉलेज में मूलभूत सुविधाओं के अभाव में बुधवार को फुलो-झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल की ओपीडी सेवा को ठप कर धरना प्रदर्शन किया। इस कारण अस्पताल की व्यवस्था चरमरा गई। इस दौरान छात्रों ने कॉलेज के छात्रावास में पानी और बिजली को सुचारु रूप से व्यवस्थित करने की मांग की। इधर, मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ओपीडी सेवा ठप रहने से इलाज के लिए आए मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि अस्पताल में इमरजेंसी सेवा चालू रही। छात्रों ने अस्पताल परिसर में धरना दिया। इस दौरान उन्होंने कॉलेज प्रबंधन, स्वास्थ्य विभाग और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों ने कहा कि छात्रावास में पानी और बिजली की व्यवस्था का घोर अभाव है। पिछले कुछ दिनों से तो स्थिति और चरमरा गई है।

धनबाद के ग्रामीण एसपी ने पदाधिकारियों को दिए निर्देश

शहर के कला भवन समेत छह जगहों पर सुनी गई जनसमस्या

PHOTON NEWS DHANBAD : पुलिस व्यवस्था में नीतिगत सुधार और पुलिस कर्मियों एवं पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत मिलने पर कार्रवाई के भरोसे के साथ बुधवार को जिले भर में पुलिस का जन शिकायत समाधान शिविर शुरू हुआ। छह जगहों पर लगे इस शिविर का निरीक्षण करने पुलिस अधीक्षक-ग्रामीण कपिल चौधरी पहुंचे। यहां पुलिस उपाधीक्षक विधि-व्यवस्था क्षेत्र अंतर्गत आने वाले सभी थाना क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए शिविर आयोजित किया गया है। यहां महिला थाना धनबाद, धनबाद थाना, केंदुआडीह थाना, जोगता, लोयाबाद, मुनिडीह ओपी, भागाबांध ओपी, धनसार थाना, बैंकमोड़ और सरायढेला थाना इलाके के लोगों की शिकायतें सुनी जा रही हैं। एसपी-ग्रामीण ने कहा कि लोगों की समस्याओं का त्वरित निष्पादन करने का प्रयास इस शिविर के माध्यम से किया जा रहा है। इसके पहले तीन बार शिविर आयोजित किया जा चुका है और यह चौथा चरण है। उन्होंने कहा कि लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए पुलिस अधिकारियों के साथ-साथ अंचल और प्रखंड अधिकारियों की भी उपस्थिति इस शिविर में रहेगी।

कला भवन धनबाद में शिविर के दौरान अपनी शिकायत दर्ज कराते लोग

इन जगहों पर आयोजित हुआ शिविर

धनबाद में कला भवन के अलावा निरसा पुलिस अनुमंडल अंतर्गत सभी थाना क्षेत्र के लिए शिविर नगर भवन चिरकुंडा, बाघमारा पुलिस अनुमंडल के लिए बीजीएम मैरेज हाल राजगंज, सिंदरी के लिए टाटा कम्युनिटी हॉल जामाडोबा, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय-1 के लिए हरदेव धर्मशाला गोविंदपुर और पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय-2 के लिए पूर्वी टुंडी के मेनरवाटांड स्थित पंचायत भवन में शिविर लगा है।

लोहरदगा में आईजी ने भी सुनी लोगों की समस्या, दिया भरोसा

शिविर में उपस्थित आईजी असीम विक्रांत मिंज व अन्य पदाधिकारी

LOHARDAGA : लोहरदगा शहरी क्षेत्र के पुराने नगर भवन में पुलिस विभाग की ओर से बुधवार को जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया । इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप पुलिस महानिरीक्षक असीम विक्रांत मिंज मौजूद थे। कार्यक्रम के विधिवत उद्घाटन के बाद आईजी असीम विक्रांत मिंज ने कहा कि लोहरदगा मे यह आयोजन पहले भी किया जा चुका है और जितनी भी समस्याएं आई थी उनमें से अधिकांश का समाधान किया जा चुका है। पुलिस के अधिकारी आपकी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और यदि आपको कोई समस्या होती है तो आप तत्काल पुलिस के अधिकारियों से संपर्क करें। मौके पर पुलिस अधीक्षक हारिश बिन जमा ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज चौथी बार जन शिकायत समाधान कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक इस कार्यक्रम में जितने भी मामले सामने आए उनमें से अधिकांश मामलों का निष्पादन कर दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर आपके मामलों को थाना स्तर पर नहीं सुना जाता है तो आप अपने मामले को यहां पर रख सकते हैं। पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए है ।आपकी परेशानियां दूर करने के लिए ही यह कार्यक्रम लगातार किया जा रहा है ।आप समस्याएं लेकर आएं हम उनका समाधान करेंगे।

पुलिस और जनता के बीच विश्वास को मजबूत करना जरूरी : डीआईजी

KHUNTI : नागरिकों की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी समाधान तथा पुलिस और आम जनता के बीच पारस्परिक विश्वास को मजबूत करने के उद्देश्य से झारखंड पुलिस द्वारा नगर भवन, खूंटी में बुधवार को जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अड़की, रनिया, तपकारा, तोरपा, कर्रा, जरियागढ़, मारंगहादा, सायको, खूंटी, मुरहू तथा महिला थाना द्वारा अलग-अलग स्टॉल लगाए गए, जहां बड़ी संख्या में नागरिकों ने अपनी समस्याएं औरा शिकायतें दर्ज कराई। मौके पर उपस्थित पुलिस उप महानिरीक्षक (एसआईबी), रांची चंदन कुमार झा, पुलिस अधीक्षक, खूंटी अमन कुमार और एसडीओ खूंटी दीपेश कुमारी ने नागरिकों की शिकायतों को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को शीघ्र समाधान का निर्देश दिया।

सीएसआईआर-एनएमएल ने जनजातीय गौरव वर्ष के तहत किया आयोजन

झारखंड में नेतरहाट की तरह 3 नए स्कूल खोले जाएंगे : मंत्री

PHOTON NEWS JSR: बर्मामाइंस स्थित सीएसआईआर-राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला (एनएमएल) में बुधवार को जनजातीय गौरव वर्ष के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एनएमएल के निदेशक डॉ. संदीप घोष चौधुरी, सीएसआईआर-सीएमईआरआई, दुगार्पुर के निदेशक डॉ. नरेश चंद्र मुर्मू, प्रमुख वैज्ञानिक एवं अनुसूचित जाति व जनजाति प्रतिनिधि डॉ. मनोज एम. हुमने तथा प्रशासनिक नियंत्रक आदित्य मैनाक भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कार्यक्रम में उपस्थित छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार नेतरहाट विद्यालय की तर्ज पर झारखंड में तीन और विद्यालय खोलेगी। इन स्कूलों में सीबीएसई करिकुलम अपनाया जाएगा, ताकि

कार्यक्रम का उद्घाटन करते मंत्री रामदास सोरेन • फोटोन न्यूज

बच्चे राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सक्षम हो सकें। सरकार की प्राथमिकता है कि इन स्कूलों की सुविधाएं निजी स्कूलों से भी बेहतर हों, चाहे वह पुस्तकें हों, प्रयोगशालाएं, पोषण या अन्य शैक्षणिक सामग्री। उन्होंने छात्रों को प्रेरित किया कि वे झारखंड के विकास में अपनी भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि झारखंड में रहने वालों को ही राज्य के प्रशासनिक पदों पर रहकर योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करना चाहिए, ताकि यहां के लोगों को उचित लाभ मिल सके। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि जैसे पूर्वजों ने स्वतंत्रता संग्राम और झारखंड आंदोलन में भाग लिया, वैसे ही अब इस पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि वह झारखंड को अन्य विकसित राज्यों की कतार में लाकर खड़ा करें। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विद्यालयों के छात्र-छात्राओं एवं उनके शिक्षक के साथ एनएमएल में कार्यरत सभी सदस्य उपस्थित थे।

सीएम स्कूल फॉर एक्सीलेंस की संख्या होगी दोगुनी : रामदास सोरेन

JAMSHEDPUR : राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि राज्य में चल रहे सीएम स्कूल फॉर एक्सीलेंस की संख्या दोगुनी की जाएगी। फिलहाल राज्य में 80 सीएम स्कूल फॉर एक्सीलेंस चल रहे हैं, इसे 160 किया जाएगा। एनएमएल में हुए कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सोरेन ने कहा कि सीएम स्कूल फॉर एक्सीलेंस में राज्य में 8 हजार सीटें थीं, जबकि नामांकन के लिए 35 हजार आवेदन आए। इससे समझा जा सकता है कि लोगों का इस स्कूल की शिक्षा गुणवत्ता पर कितना विश्वास है। मेरे पास भी नामांकन कराने के लिए पैरवी आई थी। मंत्री ने कहा कि जनजातीय विश्वविद्यालय शुरू करने का काम भी तेजी से जारी है। फिलहाल बारीडीह में अस्थायी भवन में इसे शुरू किया जाएगा। यहां जनजातीय भाषा, संस्कृति व विभिन्न विषयों की पढ़ाई होगी, रिसर्च होगा। इसमें देरी नहीं होगी।

आदित्यपुर या जमशेदपुर में तकनीकी कौशल संस्थान

रामदास सोरेन ने कहा कि युवाओं को तकनीकी कौशल से जोड़ने के लिए सरायकेला के आदित्यपुर या फिर जमशेदपुर में तकनीकी कौशल संस्थान खुलेगा। उन्होंने इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है। जमीन मिलते ही इसे शुरू किया जाएगा। इसमें राज्य के विद्यार्थियों को 75 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। वहीं औद्योगिक कंपनियों से समझौता कर इसमे पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए नौकरी सुनिश्चित की जाएगी।

घाटशिला के कृषि विश्वविद्यालय में होगी पढ़ाई

घाटशिला में कृषि विश्वविद्यालय की शाखा है। यहां फार्मिंग के विभिन्न विषयों की पढ़ाई शुरू की जाएगी। किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि किसान विभिन्न फसलों की खेती कर सकें।

बाल संरक्षण पर लोगों को किया गया जागरूक

KHUNTI : उपायुक्त लोकेश मिश्रा के निर्देश पर जिला बाल संरक्षण इकाई और संभव ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत बाल संरक्षण मुद्दों पर बुधवार को जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन तोरपा प्रखंड कार्यालय सभागार में किया गया। जागरूकता कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गांव और टोला के प्रत्येक बच्चे को संरक्षण एवं सुरक्षा प्रदान करना है। कार्यक्रम के तहत ग्राम बाल संरक्षण समिति की भूमिका को सशक्त बनाने, ग्राम सभाओं में बच्चों से संबंधित मुद्दों को प्रमुखता देने और बच्चों एवं किशोरों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया। कार्यक्रम में बाल विवाह से मुक्ति, नशा उन्मूलन, बाल तस्करी का निवारण, यौन शोषण से सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों पर संवाद हुआ। साथ ही सरकारी योजनाओं से बच्चों को जोड़ने, देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए स्पॉन्सरशिप योजना एवं फोस्टर केयर योजना के विषय में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई।

राशनकार्ड धारक 30 तक कराएं केवाईसी, वर्ना कटेगा नाम : डीसी

RAMGARH : रामगढ़ जिले में राशन कार्ड धारी का ई-केवाईसी लगातार जारी है। ई-केवाईसी के लिए 30 अप्रैल आखिरी तारीख तय की गई है। अगर इस दिन तक जो व्यक्ति अपना ई-केवाईसी नहीं करवाएंगे, उनका नाम राशन कार्ड से काट दिया जाएगा। इस संबंध में बुधवार को डीसी चंदन कुमार ने एक आदेश भी जारी किया है। उन्होंने कहा है कि रामगढ़ जिला अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना एवं झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित सभी राशन कार्डधारियों और सदस्यों का ई-केवाईसी किया जाना है। वर्तमान में रामगढ़ जिला अंतर्गत कुल कार्ड की संख्या 1,49,062 में कुल सदस्यों की संख्या 6,65,261 है। इनमे से अभी तक 5,13,722 सदस्यों का ही ई-केवाईसी हो पाया है। शेष 1,51,839 सदस्यों का 30 अप्रैल 2025 तक शत प्रतिशत ई-केवाईसी किया जाना अतिआवश्यक है। शेष सभी राशन कार्डधारी और सदस्यों को सूचित किया जाता है कि 30 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से अपने नजदीकी जन वितरण प्रणाली दुकानदारों से सम्पर्क कर ई-पोस मशीन से ई-केवाईसी करा लें। निर्धारित तिथि तक ई-केवाईसी नहीं कराया जाएगा, वैसी स्थिती में माह मई से उनका नाम राशन कार्ड से विलोपित हो जाएगा।

उपायुक्त चंदन कुमार

BRIEF NEWS

आपसी विवाद में पति ने कुदाल से वार कर पत्नी को किया घायल

RANCHI : बुधवार को बेड़ो थाना क्षेत्र के साईं मंदिर रोड स्थित एक घर में आपसी विवाद के बाद पति ने कुदाल से हमला कर अपनी पत्नी को गंभीर रूप से घायल कर दिया। आरोपी युवक संतोष गुप्ता ने पत्नी तनु गुप्ता पर कुदाल से वार किया, जिससे महिला के सिर और छाती पर गंभीर चोटें आई हैं। घटना के बाद घायल तनु को परिजनों ने आनन-फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सक ने गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार, घटना की वजह आपसी मामूली विवाद बताया जा रहा है।

ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बैठक की गई स्थगित

RANCHI : ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल (टीएसी) की बुधवार को होने वाली बैठक अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गयी है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी गई है। बताया गया है कि 16 अप्रैल को प्रोजेक्ट भवन, एनेक्सी भवन सभागार में जनजातीय परामर्शदात्री समिति की होने वाली बैठक अपरिहार्य कारण वश स्थगित कर दी गयी है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में यह बैठक होनी थी।

जयराम महतो ने अमित शाह को लिखी चिट्ठी

RANCHI : जेएलकेएम के अध्यक्ष और डुमरी विधायक जयराम महतो ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। गृह मंत्री को लिखी चिट्ठी में जयराम ने बोकारो में 3 अप्रैल को हुए विरोध प्रदर्शन और लाठीचार्ज के बाद विस्थापितों और रैयतों पर केस दर्ज करने के मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है। तीन और चार अप्रैल को बीएसएल गेट पर विस्थापितों और रैयतों ने नियोजन और मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। इस दौरान हुए लाठीचार्ज में प्रेम महतो नाम के युवक की मौत हो गई थी।

पूर्व सिविल सर्जन ने रातू में किया द एलायंस हॉस्पिटल का उद्घाटन

RANCHI : राजधानी के काठीटांड़, रातू के समीप द एलायंस हॉस्पिटल उद्घाटन डॉ. वाईके सिन्हा पूर्व सिविल सर्जन एवं पूर्व जिला परिषद सदस्य अकलीमा खातून ने किया। डॉ. वाईके सिन्हा ने बताया कि यह अपने आप में सबसे अलग हॉस्पिटल है, जिसे लोगों की स्वास्थ्य संबंधित जरूरतों को देखकर बनाया गया है। कई बार ऐसा होता है, जब घर के बुजुर्ग का स्वास्थ्य बहुत खराब हो जाता है, वे बेड से उठ नहीं पाते। लेकिन, घर पे उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं होता, ऐसे में उन लोगों की देखभाल इस अस्पताल में की जाएगी।

नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया-राहुल पर चार्जशीट का विरोध

कांग्रेस ने ईडी कार्यालय के सामने जमकर किया प्रदर्शन

ईडी कार्यालय के सामने प्रदर्शन करते कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता ● फोटोन न्यूज

PHOTON NEWS RANCHI : नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर चार्जशीट के विरोध में कांग्रेस पार्टी देशभर में ईडी दफ्तरों के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रही है। रांची में हिनू रोड स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय के बाहर प्रदेश कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन किया। नेताओं में कांग्रेस के झारखंड प्रभारी के राजू, सह प्रभारी डॉ सिरिवेला प्रसाद, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, उपनेता राजेश कच्छप, कार्यकारी अध्यक्ष बन्धु तिर्की, जलेश्वर महतो, मंत्री डॉ इरफान अंसारी, सुबोधकांत सहाय, विधायक सुरेश बैठा, रामचन्द्र सिंह, नमन विक्सल कोंगाडी, अम्बा प्रसाद, राजेश ठाकुर, डॉ प्रदीप बलमुचू, केएन त्रिपाठी, गुंजन सिंह सहित अन्य शामिल थे। मौके पर झारखंड प्रभारी के राजू ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा की ओर से लोकतंत्र और संविधान की हत्या बार-बार की जा रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने लगातार सदन में रोजगार, महंगाई, किसानों की समस्या और देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया है। इससे केंद्र सरकार विचलित हो गयी है और हमारी आवाज को दबाने के लिए ईडी का सहारा ले रही है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब-जब किसी राज्य में चुनाव आता है तो भाजपा ईडी को सक्रिय कर देती है ताकि जनता की आवाज दबाई जा सके। उन्होंने कहा कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं भाजपा ने ऐसे सभी लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। सह प्रभारी डॉ सिरिवेला प्रसाद ने कहा कि विपक्ष के नेताओं की आवाज दबाना लोकतांत्रिक व्यवस्था पर कुठाराघात है। भाजपा देश को गुमराह कर रही है। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करना भाजपा की राजनीति धमकी के अलावा कुछ नहीं है। हम चुप नहीं रहेंगे। हम कल भी लड़े थे अब भी लड़ेंगे। लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देंगे।

बारिश से तापमान में तीन डिग्री की कमी, 19 तक रहेगी गर्मी से राहत

RANCHI : राजधानी रांची और आसपास के इलाकों में पिछले 24 घंटों में हुई बारिश से तापमान में तीन डिग्री की कमी दर्ज की गई। बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया और न्यूनतम तापमान गिरकर 17.9 डिग्री हो गया। रांची में पिछले 24 घण्टों के दौरान 15 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। इससे लोगों को ठंड का एहसास हुआ। अप्रैल माह में नवम्बर-दिसम्बर जैसी स्थिति रही। मौसम विभाग ने 19 अप्रैल तक राज्य भर में गर्जन, वज्रपात और तेज हवा चलने की आशंका जतायी है। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। इस लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। उल्लेखनीय है कि काल बैसाखी के कारण मौसम का यह रुख देखने को मिल रहा है। वहीं बुधवार को रांची में तापमान 30.7, जमशेदपुर में 33 डिग्री, डालटेनगंज में 36.6 और बोकारो में अधिकतम तापमान 32.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

नेशनल हेराल्ड मामले में चोरी के साथ सीनाजोरी कर रही कांग्रेस : बाबूलाल

PHOTON NEWS RANCHI : भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की ओर से कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी चोरी भी करती है फिर धरना प्रदर्शन के रूप में लूट को छिपाने के लिए सीनाजोरी भी करती है। उन्होंने ईडी की कार्रवाई को उचित कार्रवाई बताया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन का अधिकार है। कांग्रेस पार्टी देश भर में धरना प्रदर्शन कर रही है लेकिन उन्हें जमीन और फंड लूटने का अधिकार नहीं है। बाबूलाल मरांडी बुधवार को पार्टी प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने ने कहा नेशनल हेराल्ड को शुरू किया गया था। शुरुआत में इसके पांच हजार शेयर होल्डर्स थे। यानी नेशनल हेराल्ड कभी नेहरू खानदान की जागीर नहीं रहा। इसमें उस समय के बड़े-बड़े क्रांतिकारियों का भी सहयोग था। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन आर्थिक विफलता के कारण 2008 में बंद हो गया। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ रुपये की राशि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को दी, जो इस अखबार को प्रकाशित करती थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है जिसे कई प्रकार की छूट मिलती है] लेकिन राजनीतिक पार्टी किसी निजी संस्था को पार्टी का फंड नहीं दे सकती। यह पूरी तरह से गैर कानूनी है। कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड की पूरी संपत्ति को गांधी परिवार के हाथों में लाने के लिए एक कॉर्पोरेट साजिश रची। यंग इंडिया नाम की एक कंपनी बनाई गई जिसमें 38 प्रतिशत हिस्सा सोनिया गांधी का और 38 प्रतिशत राहुल गांधी का रखा गया।

जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में कई मामलों का किया गया निपटारा

पिठोरिया : समस्याओं का हुआ त्वरित समाधान

RANCHI : बुधवार को पिठोरिया थाना परिसर में आयोजित जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। थाना प्रभारी अभय कुमार ने बताया कार्यक्रम में जनता की भागीदारी संतोषजनक रही। इसका मुख्य उद्देश्य पुलिस और जनता के बीच संवाद को बढ़ाना और शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है, ताकि ग्रामीण इलाकों के लोग अपनी समस्याएं सीधे पुलिस तक पहुंचा सकें। इस मौके पर लंबित केस, जमीन विवाद, पेयजल आदि से जुड़े समस्या भी जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में आए, जिनका समाधान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से थाना प्रभारी अभय कुमार, एसआई संतोष यादव, सुनील कुमार दास, संजय कुमार, मुंशी अजय कुमार मौजूद थे।

PHOTON NEWS RANCHI : बुधवार को बेड़ो थाना परिसर में एक दिवसीय जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ग्रामीणों की ओर से बड़ी संख्या में आवेदन प्रस्तुत किए गए। बेड़ो थाना क्षेत्र से कुल 10 और नरकोपी थाना क्षेत्र से 4 मामले सामने आए। कार्यक्रम के दौरान बेड़ो थाना में प्राप्त 10 आवेदनों में से 7 मामले भूमि विवाद से संबंधित पाए गए, जिन्हें संबंधित अंचल कार्यालय को अग्रसारित किया गया। मोबाइल से जुड़े 3 मामलों का समाधान मौके पर ही कर दिया गया। नरकोपी थाना से आए 4 मामलों में से 2 का निष्पादन मौके पर किया गया, जबकि शेष दो भूमि मामलों को भी अंचल कार्यालय भेजा गया। मौके पर डीएसपी अशोक कुमार राम, पुलिस सब इंस्पेक्टर अक्षय कुमार, बेड़ो थाना प्रभारी देव प्रताप प्रधान, नरकोपी के थाना प्रभारी नागेश्वर साव, अंचल निरीक्षक फिरोज खान सहित कई पुलिस के पदाधिकारी और जवान मौके पर मौजूद थे।

मारवाड़ी ब्राह्मण सभा 30 को मनाएगी भगवान परशुराम की जयंती

RANCHI : रांची मारवाड़ी ब्राह्मण सभा रांची की ओर से अक्षय तृतीया के दिन 30 अप्रैल को भगवान परशुराम की जयंती मनाई जाएगी। इस उपलक्ष्य में सभा की ओर से कई तरह की प्रतियोगिताएं कराई जाएगी। सभा के अध्यक्ष अशोक पुरोहित ने बुधवार को बताया कि इससे पहले समाज के बच्चों के लिए मारवाड़ी ब्राह्मण भवन में फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इसके अलावा चित्रांकन प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी, म्यूजिकल चेयर गेम और उसके बाद भाषण प्रतियोगिता होगी।

आर्मी ग्राउंड पहुंचे सेठ, एयर शो की तैयारियों का लिया जायजा

एयर शो की तैयारियों का जायजा लेते केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ● फोटोन न्यूज

PHOTON NEWS RANCHI : रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ तंजानिया के दौरे के बाद बुधवार को रांची पहुंचे। यहां रक्षा राज्य मंत्री सीधे नामकुम आर्मी ग्राउंड गए, जहां सूर्य किरण की टीम की ओर से 19 और 20 अप्रैल को एयर शो आयोजित किया जाएगा। रक्षा राज्य मंत्री ने मौके पर वायु सेवा के अधिकारियों के साथ कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की और इस एयर शो के रूपरेखा से संबंधित जानकारी प्राप्त की। उल्लेखनीय है कि रांची में विश्वस्तरीय एयर शो का आयोजन सूर्य किरण टीम कर रही है। भारतीय वायुसेना की यह टीम विमानों की कई रोमांचकारी करतब दिखाएगी। इस दौरान संजय सेठ ने कहा कि सेना के जवानों का शौर्य और कौशल को करीब से देखने का यह ऐतिहासिक और अविस्मरणीय अवसर होगा। इसे ऐतिहासिक और अविस्मरणीय बनाने के लिए वायुसेना अथक परिश्रम कर रही है। रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि उनका यह प्रयास रहा कि रांची की जनता सेना के शौर्य कौशल को करीब से देख सके और सेना में सेवा के लिए युवाओं की उत्सुकता बढ़े। इसी उद्देश्य के साथ उन्होंने पिछले वर्ष सेना को जानो कार्यक्रम का तीन दिवसीय आयोजन कराया था। यह कार्यक्रम भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है।

महिला की शिकायत पर डीआईजी ने किया ऑन द स्पॉट फैसला

PHOTON NEWS RANCHI : बुधवार को रांची पुलिस द्वारा जन शिकायत समाधान के दौरान डीआईजी सह एसएसपी ने कई मामलों में कड़े तेवर दिखाए। इस दौरान उन्होंने ऑन द स्पॉट फैसले किए। उन्होंने जन शिकायत केंद्र में एक जमीन दलाल को हवालात के पीछे भेज दिया। रांची के सुखदेव नगर की रहने वाली एक महिला जन शिकायत समाधान केंद्र में अपनी पीड़ा लेकर पहुंची थी। महिला ने डीआईजी सह एसएसपी को यह बताया कि कुछ आपराधिक तत्व उनके घर आकर उन्हें डरा धमका रहे हैं। मामले में तुरंत एक्शन लेते हुए एसपी ने महिला के घर जाकर धमकाने वाले व्यक्ति को सीधे फोन करके जन समाधान केंद्र तलब कर लिया। इमरान नाम का वह व्यक्ति जब जन समाधान केंद्र पहुंचा तो एसएसपी के सामने ही पीड़ित महिला ने उसकी पहचान करते हुए उसके द्वारा की गई सारी करतूत को उजागर कर दिया। जिसके बाद एसएसपी ने तुरंत इमरान को हिरासत में लेने का आदेश दिया। एसएसपी के आदेश के बाद इमरान को हिरासत में लेकर थाना भेज दिया गया है, जहां मामले को लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

झामुमो के कैंप कार्यालय पहुंचे हेमंत, हुआ स्वागत

झामुमो के कैंप कार्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व सुप्रियो भट्टाचार्य ● फोटोन न्यूज

PHOTON NEWS RANCHI : झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के नवनिर्वाचित केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन बुधवार को पार्टी के हरमू स्थित कैंप कार्यालय पहुंचे। यहां उनका स्वागत पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य और विनोद कुमार पांडेय ने बुके देकर किया। मौके पर उन्होंने कार्यालय का निरीक्षण किया और पार्टी के अन्य सदस्यों से मशविरा किया। मौके पर पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि पूरी पार्टी युवा अध्यक्ष के रूप में हेमंत सोरेन को पाकर गौरवान्वित है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन आने वाले दिनों में पार्टी के कार्यों का निर्धारण करेंगे और नई उर्जा से पार्टी को मजबूती देंगे। उन्होंने बताया कि अगले दो-तीन माह में बरियातू स्थित पार्टी का केंद्रीय कार्यालय भी बनकर तैयार हो जाएगा। इस नए कार्यालय का उद्घाटन पार्टी के संस्थापक संरक्षक शिबू सोरेन करेंगे। पार्टी का यह कार्यालय लगभग बनकर तैयार है।

मनरेगा घोटाला मामले में आईएएस पूजा सिंघल व अन्य ने कोर्ट में लगाई हाजिरी

PHOTON NEWS RANCHI : मनरेगा घोटाला मामले में आरोपित आईएएस पूजा सिंघल उनके पति अभिषेक झा और सीए सुमन कुमार सिंह ने पीएमएलए की विशेष कोर्ट में हाजिरी लगाई। कोर्ट ने जमानत की सुविधा देते हुए निर्धारित तिथि रखी थी, जिसे पूरा करते हुए तीनों आरोपी कोर्ट में उपस्थित हुए। उल्लेखनीय है कि पूजा सिंघल को 28 माह जेल में रहने के बाद जमानत मिली थी। इस मामले में ईडी ने मई 2022 में कार्रवाई की थी, जिसमें पूजा सिंघल, उनके पति और सीए सुमन कुमार सिंह के ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। इस छापेमारी में सुमन कुमार सिंह के यहां से 19 करोड़ 31 लाख रुपये नकद बरामद हुए थे। इस मामले में एसीबी ने पहले कार्रवाई करते हुए 16 केस दर्ज किए थे, जिसके बाद ईडी ने 2022 में मामला अपने हाथ में लिया था।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना : अंत्योदय के तहत मिलने वाली सहायता में भी कटौती

पड़ोसी राज्यों की तुलना में झारखंड को मिला कम अनाज

» गेहूं व चावल मिलाकर दिया गया है 1,45,999.45 मीट्रिक टन

» उत्तर प्रदेश व बिहार को किया गया सबसे ज्यादा आवंटन

अप्रैल से जून तक मिलेगी चीनी

राज्य के राशन कार्डधारियों को अप्रैल से जून तक चीनी मिलेगी। इसके लिए 27 हजार क्विंटल चीनी खरीदी जाएगी। इसका टेंडर जारी कर दिया गया है। पलामू प्रमंडल को 2701 क्विंटल, उत्तरी छोटानागपुर को 7527 क्विंटल, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल को 5959 क्विंटल, कोल्हान को 5557 क्विंटल और संथाल परगना को 5069 क्विंटल चीनी आवंटित किया जाएगा। प्रीबिड मीटिंग 21 अप्रैल को होगी। ई-केवाईसी नहीं कराने पर संबंधित व्यक्ति या परिवार को राशन मिलने की सुविधा से वंचित होना पड़ सकता है। ऐसे में कार्डधारकों को समय रहते यह प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है।

PHOTON NEWS RANCHI : केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत दिए जाने वाले अनाजों के आवंटन में झारखंड को नजर अंदाज किया गया है। राज्य को पड़ोसी राज्यों से कम अनाज मिला है। गेहूं और चावल मिलाकर कुल 1,45,999.45 मीट्रिक टन ही अनाज मिला है, जो बिहार, मध्यप्रदेश और उड़ीसा सहित अन्य राज्यों से कम है। पड़ोसी राज्य बिहार को 4,60,591.70 मीट्रिक टन, मध्यप्रदेश को 2,91,149.57 मीट्रिक टन और उड़ीसा को 1,87,651.95 मीट्रिक टन अनाज केंद्र सरकार की ओर से दिया गया है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश को 8,26,056.23 मीट्रिक टन अनाज दिया गया है। 460591.70 मीट्रिक टन अनाज आवंटन के साथ बिहार दूसरे नंबर पर है। इतना ही नहीं, अंत्योदय अन्न योजना में भी झारखंड को अन्य राज्यों की तुलना में कम अनाज मिला है। इस योजना के तहत झारखंड को सिर्फ 31,285.10 मीट्रिक टन अनाज मिला है। बिहार को 87,535.00, मध्यप्रदेश को 51,217.63 और ओडिशा को 43,849.57 मीट्रिक टन अनाज दिया गया है।

जायरीनों को उपलब्ध कराई जाएंगी सभी सुविधाएं : इरफान अंसारी

PHOTON NEWS RANCHI : बुधवार को स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि हज हाउस में हज कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते हज पर जाने वाले जायरीनों के लिए आयोजित एक दिवसीय हज प्रशिक्षण शिविर में शिरकत की। हमारे साथ मंत्री हफीजुल हसन अंसारी जी भी मौजूद रहे। हज को सुरक्षित और सुगम बनाने के उद्देश्य से झारखंड स्टेट हज कमेटी ने यात्रियों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान कर हज यात्रियों को एक साथ हज से जुड़ी प्रक्रियाएं, नियमावली, स्वास्थ्य सुरक्षा और यात्रा से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की है। जायरीन को वह सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिनकी उन्हें जरूरत है। सरकार आपको झारखंड से लेकर मक्का-मदीना तक आपके खिदमत में उपस्थित रहेगी। हज पर जा रहे आप सभी हज यात्रियों से दरख्वास्त है कि राज्य एवं मुल्क में अमन-चैन, आपसी भाईचारे को मजबूत करने को लेकर दुआएं करते हुए वापस लौटें।

शिक्षा विभाग के भ्रष्टाचार की जांच कराएं मुख्यमंत्री : डॉ. अटल

RANCHI : रांची विश्वविद्यालय के पूर्व सीनेट सह सिंडिकेट सदस्य डॉ अटल पाण्डेय और अर्जुन कुमार राम ने बुधवार को राजभवन और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उच्च शिक्षा विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार की जांच कराने की मांग की है। डॉ पाण्डेय ने कहा कि विभा पाण्डेय, जो नीलाम्बर - पीताम्बर विश्वविद्यालय की प्राध्यापिका हैं, उन्हें उच्च शिक्षा विभाग ने अपने ही नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए, बिना विश्वविद्यालय में योगदान कराए और बगैर कुलपति की अनुमति के सेवा विस्तार दे दिया। उन्होंने कहा कि विभा पाण्डेय पिछले पांच वर्षों से कार्यरत हैं, जबकि उच्च शिक्षा विभाग ने ही पत्र जारी कर कहा था कि जिनकी सेवा तीन वर्ष पूर्ण हो जायेगी वे स्वतः विरमित समझे जाएंगे।

समाचार सार

अनुमंडल पुलिस ने सुनी जनता की शिकायत

GHATSILA : प्रखंड कार्यालय सभागार में बुधवार को अनुमंडल पुलिस की ओर से जन शिकायत समाधान कार्यक्रम किया गया, जिसमें ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग, प्रशिक्षु आईपीएस ऋषभ त्रिवेदी व अनुमंडल पदाधिकारी सुनील चंद्र भी उपस्थित थे। इसमें अधिकांश मामले जमीन विवाद से जुड़े थे। ग्रामीण एसपी ने संबंधित विभाग से निष्पादन कराने का आश्वासन दिया। इसमें बहरागोड़ा प्रखंड के आनंद कुमार साव, मनोज कुमार बांसुरी सहित अन्य लोगों ने अपनी समस्या रखी। ग्रामीण एसपी ने कहा कि किसी भी तरह के मामले को जन शिकायत कार्यक्रम में रखा जा सकता है, उसका त्वरित निष्पादन किया जाएगा।

पश्चिमी सिंहभूम में निकला पोषण रथ

CHAIBASA : पश्चिमी सिंहभूम जिले में बुधवार से पोषण पखवाड़ा शुरू हुआ। समाहरणालय परिसर से उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने रथ और सेविका स्कूटी रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ 22 अप्रैल तक पूरे जिले में घूम-घूम कर लोगों को पौष्टिक खानपान के प्रति जागरूक करेगा। इस अवसर पर अपर उपायुक्त प्रवीण केरकेट्टा, नजारत उप समाहर्ता देवेंद्र कुमार, जिला पंचायत राज पदाधिकारी सबिता टोपनो, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी श्वेता भारती, जिला योजना पदाधिकारी फ्रांसिस कुजूर और सहायक निदेशक-सामाजिक सुरक्षा खुशेंद्र सोनकेशरी भी उपस्थित थे।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी के खिलाफ किया प्रदर्शन

JAMSHEDPUR : अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से बुधवार को बिष्टुपुर स्थित जीएसटी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया गया। इसके बाद जीएसटी कमिश्नर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इसमें कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी के मुखपत्र नेशनल हेराल्ड की संपत्ति को लेकर ईडी गलत तरीके से कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी व वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है। प्रदर्शन का नेतृत्व जिलाध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने किया।

नेशनल क्रिएटिविटी ओलंपियाड 19-20 को

JAMSHEDPUR : इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया, जमशेदपुर लोकल सेंटर की ओर से 19-20 अप्रैल को नेशनल क्रिएटिविटी ओलंपियाड का आयोजन किया जा रहा है। बिष्टुपुर स्थित एसएनटीआई ऑडिटोरियम में सुबह 11 से शाम 6 बजे तक होने वाली प्रतियोगिता में 8 राज्यों से करीब 32 छात्र भाग लेंगे। संस्थान के चेयरमैन सतीश कुमार तिवारी व ऑर्गनाइजिंग चेयरमैन एन राजेश कुमार ने बताया कि इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना आदि के स्कूलों से 9-12 के छात्र आ रहे हैं, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी थीम पर भूमि-संरक्षण पर आधारित मॉडल प्रदर्शित करेंगे। जमशेदपुर के 5 स्कूल भी इसमें भाग लेंगे। इस दौरान एसडी भट्टाचार्य व डॉ. एसके नारंग ने बताया कि संस्थान यह आयोजन 20 वर्ष से कर रहा है, जबकि पिछला आयोजन 2022 में हुआ था।

हरि संकीर्तन महोत्सव शुरू

CHAKRADHARPUR : चक्रधरपुर प्रखंड अंतर्गत चंदरी पंचायत के पनसुवां गांव में बुधवार को तीन दिवसीय श्रीश्री राधा गोविंद हरि संकीर्तन महोत्सव का आयोजन किया गया। गांव में भव्य कलश यात्रा निकालकर हरि संकीर्तन का शुभारंभ किया गया। कलश यात्रा गांव के नदी से निकालकर समूचे गांव में भ्रमण करते हुए कार्यक्रम स्थल पहुंची। संकीर्तन का आरंभ हरिनाम जाप से किया गया।

जमशेदपुर में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले अंतरराज्यीय चोर गिरोह के छह सदस्य धराए

चोरी का गहना खरीदने वाले आभूषण कारोबारी को भी भेजा गया जेल, 99 ग्राम सोना बरामद

- घोड़ाबांधा के गर्म पत्थर क्षेत्र में पहुंचे थे गिरोह के सदस्य
- गोविंदपुर के थाना प्रभारी को मिली थी गुप्त सूचना, एसएसपी ने भेजी टीम

PHOTON NEWS JSR: गोविंदपुर थाना की पुलिस ने घोड़ाबांधा हॉस्पिटल के सामने गर्म पत्थर इलाके से छह चोरों को गिरफ्तार किया है। इन चोरों की निशानदेही पर मानगो के गुरुद्वारा रोड के रहने वाले स्वर्ण आभूषण कारोबारी अजय कुमार बर्मन को भी पुलिस ने पकड़ा है। अजय कुमार बर्मन के पास से 99 ग्राम सोना बरामद हुआ है। यह सोना चोरों ने विभिन्न फ्लैटों में चोरी की घटना को अंजाम देकर एकत्र किए थे और इसे अजय कुमार बर्मन के पास बेच दिया था। पुलिस ने डकैतों के पास से एक देसी कट्टा, एक कारतूस, एक रिंच, एक पेचकस और एक टॉर्च भी बरामद किया है।

पुलिस गिरफ्त में चोरी के आरोपी व मामले की जानकारी देते सिटी एसपी कुमार शिवाशीष • फोटोन न्यूज

ओडिशा, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र के रहने वाले हैं आरोपी

पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है, उनमें ओडिशा के पुरी जिला के बसेली थाना क्षेत्र के लोकनाथ बस्ती का रहने वाला तारा सिंह चौहान, यहीं का राहुल चौहान, मध्य प्रदेश के कटनी के शहडोल का रहने वाला अजय चौहान, यहीं का आशीष चौहान, कटनी के बेला कला गांव का बाबू गोंदिया और महाराष्ट्र के औरंगाबाद के छावनी थाना क्षेत्र का रहने वाला संदीप सोलंकी गिरफ्तार हुआ है। यह जानकारी सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को दी।

दयाल सिटी व रॉक गार्डन में चोरी का हुआ खुलासा

सिटी एसपी ने बताया कि इन चोरों ने परसुडीह थाना क्षेत्र के दयाल सिटी में चार फ्लैट और गोविंदपुर के रॉक गार्डेन के 10 फ्लैटों में चोरी की घटना को अंजाम देने की बात कुबूल की है। उन्होंने बताया कि इन चोरों को अभी जेल भेजा जा रहा है। बाद में इन्हें रिमांड पर लेकर और पूछताछ की जाएगी।

एसएसपी के निर्देश पर बनी थी छापामारी टीम

उन्होंने बताया कि गोविंदपुर थाना प्रभारी को गुप्त सूचना मिली थी की छह बदमाश घोड़ाबांधा हॉस्पिटल के सामने गर्म पत्थर इलाके में टेंपो से उतरे हैं। यह अनजान चेहरे लग रहे हैं। उनके पास लोहे के औजार भी हैं। ये चोर हो सकते हैं। इसके बाद उन्होंने घटना की जानकारी एसएसपी को दी। एसएसपी ने सिटी डीएसपी के नेतृत्व में एक छापामारी दल गठित किया और जहां पर यह कर एकत्र होकर डकैती की घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे, वहां छापामारी कर दी और सभी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया।

जनशिकायत समाधान कार्यक्रम में भूमि विवाद की रही भरमार, आईं 296 शिकायतें

बिष्टुपुर स्थित माइकल जॉन ऑडिटोरियम में सुबह से शाम तक चला शिविर

PHOTON NEWS JSR: बिष्टुपुर के माइकल जॉन आडिटोरियम में बुधवार को जन शिकायत समाधान कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में भूमि विवाद की भरमार रही। सबसे अधिक जमीन विवाद के मामले आए। इसके अलावा, मारपीट करने, थानों में प्राथमिकी दर्ज नहीं किए जाने समेत कई अन्य मामले भी आए। कई मामले अन्य विभागों से संबंधित थे, जिन्हें ले लिया गया। आईजी अखिलेश झा ने बताया कि जो मामले जिस विभाग के हैं उन्हें निस्तारण के लिए संबंधित विभाग में भेज दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में कुल 296 शिकायतें आई हैं। राज्यभर में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। बिष्टुपुर स्थित माइकल जॉन ऑडिटोरियम में चौथी बार यह कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में दक्षिणी छोटानागपुर के जोनल आईजी अखिलेश झा, वरीय पुलिस अधीक्षक कौशल किशोर सहित जिले के अन्य प्रशासनिक और पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। आईजी अखिलेश झा ने बताया कि पुलिस से संबंधित शिकायतों का निवारण नियम के अनुरूप किया जा रहा है। वहीं, अन्य विभागों से संबंधित मामलों को उचित विभाग को हस्तांतरित कर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में इस शिविर का लाभ उठाएं और अपनी समस्याओं के समाधान हेतु आगे आएं।

लोगों की समस्या सुनते आईजी अखिलेश झा • फोटोन न्यूज

मेला से लौट रहे बच्चे को ट्रैक्टर ने कुचला

CHAIBASA : पश्चिमी सिंहभूम जिले के पांडरासाली थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर की चपेट में आकर बड़ा पताहातु गांव निवासी बोंज लेयांगी के बेटे 12 वर्षीय तुराम लेयांगी की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, तुराम मंगलवार रात को सिंदरी गांव में मेला देखने गया था। मेला देखकर देर रात घर लौटते समय एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने धक्का मार दिया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। बुधवार को सुबह पांडरासाली ओपी पुलिस को घटना की सूचना दी गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा कर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ट्रैक्टर का पता लगा रही है।

लाइसेंसी शराब दुकान में हुई लाखों की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुए चोर

शराब दुकान का निरीक्षण करते पुलिस पदाधिकारी • फोटोन न्यूज

CHAKRADHARPUR : चक्रधरपुर के पुराना रांची रोड स्थित एक लाइसेंसी विदेशी शराब दुकान में बीती रात लाखों की चोरी हो गई। चोर दुकान की छत काटकर भीतर घुसे और लाखों रुपये ले गए। घटना का खुलासा गुरुवार को सुबह में हुआ, जब दुकान के सेल्समैन राजमोहन प्रजापति ने दुकान का खोला। दुकान में सामान बिखरे पड़े थे और पैसा रखने वाला मुख्य लॉकर गायब था। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। एक फुटेज में तीन चोर नजर आ रहे हैं। सेल्समैन के अनुसार, लॉकर में करीब डेढ़ लाख रुपये थे। चोरों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।

बीएड में एडमिशन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 को

JAMSHEDPUR : झारखंड में बीएड, एमएड व बीपीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है उनके लिए महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद (जेसीईसीईबी) ने सत्र 2025-27 के लिए इन पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 20 अप्रैल निर्धारित की है। ऐसे में आवेदन में सिर्फ चार दिन शेष है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट jceceb.jharkhand.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 1000 रुपये, पिछड़ा वर्ग के लिए 750 रुपये, एससी-एसटी व महिला अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये निर्धारित किया गया है।

11 मई को होगी परीक्षा

यह परीक्षा 11 मई को ऑफलाइन मोड में ओएमआर शीट पर ली जाएगी। परीक्षा में कुल 100 अंकों के बहु विकल्पीय प्रश्न (एमसीक्यू) होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक अंक दिया जाएगा, जबकि गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटे जाएंगे। आवेदन के लिए अभ्यर्थी का 50 फीसदी अंक के साथ स्नातक (आरक्षित वर्ग के लिए 45 फीसदी) पास होना अनिवार्य है। इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में डिग्री धारकों के लिए अंक सीमा 55 फीसद है। इस प्रवेश परीक्षा के लिए सभी जिलों में परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा।

घाटशिला कॉलेज के प्राचार्य डॉ. आरके चौधरी को दी गई विदाई

GHATSILA : घाटशिला कॉलेज के प्राचार्य डॉ. आरके चौधरी कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा के सीसीडीसी बनाए गए हैं। इसे लेकर बुधवार को कालेज में समारोहपूर्वक विदाई दी गई। उन्होंने डॉ. पीके गुप्ता को प्रभार दिया। इस मौके पर प्रो. इंदल पासवान, कॉलेज के सेवानिवृत शिक्षक प्रो. मित्रेश्वर, प्रो. सुबोध कुमार सिंह, निर्मल झुनझुनवाला, राकेश कुमार शर्मा आदि भी उपस्थित थे।

निजी स्कूलों में फीस वसूली पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने लिया संज्ञान

PHOTON NEWS CHAIBASA : पश्चिमी सिंहभूम जिले में निजी विद्यालयों (सीबीएसई) के अभिभावकों से ली जा रही फीस के विरुद्ध मानवाधिकार कार्यकर्ता बैरम खान की शिकायत पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संज्ञान लिया है। मंत्रालय के अपर सचिव आनंद राव पाटेल, डिप्टी सेक्रेटरी (स्कूली बोर्ड) को संज्ञान लेने को कहा गया है। इसके बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी गुलजारी लाल ने झारखंड शिक्षा विभाग को इस मामले पर कार्रवाई के लिए कहा है। बैरम खान ने कहा कि यह मामला सिर्फ चक्रधरपुर का नहीं, पूरे राज्य का है। ये धंधा सबकी मिलीभगत से फल-फूल रहा है। शिकायत के बाद निजी स्कूल कुछ अभिभावकों को डराकर अब आवेदन जमा ले रहे हैं कि हम अपनी मर्जी से स्कूल को राशि दे रहे हैं। दूसरे चरण में हमलोग पूरे चक्रधरपुर के लोगों से हस्ताक्षर अभियान चलाकर झारखंड हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को पत्र भेजेंगे। जरूरत पड़ी तो न्यायालय की शरण में भी जाएंगे।

प्राइवेट स्कूलों में वसूली पर शिक्षा मंत्री को भेजा ज्ञापन

घाटशिला के अनुमंडल कार्यालय पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ता • फोटोन न्यूज

GHATSILA : झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव सह 20 सूत्री के जिला सदस्य सनत काल्टु चक्रवर्ती के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा मंत्री के नाम घाटशिला एसडीओ को ज्ञापन सौंपा। इसमें मांग की गई है कि अनुमंडल क्षेत्र के निजी स्कूलों में सरकारी नियमों का उल्लंघन कर छात्रों एवं अभिभावकों से मनमाना शुल्क वसूला जा रहा है, इस पर प्रतिबंध लगाया जाए। सरकार के सख्त आदेश के बाद भी निजी स्कूल री-एडमिशन सहित अन्य कई तरह के शुल्क मनमाने ढंग से वसूल रहे हैं। इस मौके पर प्रखंड अध्यक्ष सत्यजीत सीट, शमशाद खान, भुजंग भूषण, अजय देव, रविंद्र सिंह दानिश सिद्दीकी, कुंडल दत्ता आदि कार्यकर्ता भी उपस्थित थे।

पेंशन की आस में दफ्तर के चक्कर काट रहीं महिलाएं, सामाजिक सुरक्षा विभाग में लगा आवेदकों का जमावड़ा

दगा दे गई मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना की वेबसाइट

PHOTON NEWS JSR : मरम्मत के काम के लिए बंद की गई झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना की साइट महिलाओं को दगा दे गई। सरकार की तरफ से कहा गया था कि यह साइट 15 अप्रैल तक के लिए बंद की जा रही है। साइट को हर हाल में 16 अप्रैल यानी बुधवार को खोल दिया जाएगा। इसके बाद बुधवार को पूर्वी सिंहभूम जिले के सामाजिक सुरक्षा कोषांग के कार्यालय से लेकर प्रखंडों के अंचल कार्यालयों में महिलाएं जमा रहीं। मगर, क्लर्क उनको यही बताते रहे कि साइट अभी खुली नहीं है। इस वजह से इस योजना से जुड़ी कोई जानकारी उन्हें नहीं बताई जा सकी। इससे महिलाएं नाराज दिखीं। महिलाओं का कहना था कि विभाग उन्हें सिर्फ दौड़ा रहा है। हर बार कोई न कोई बहाना बनाता है।

पूनम देवी करनडीह से आई थीं। उन्होंने डीसी ऑफिस के ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद सामाजिक सुरक्षा कोषांग के कार्यालय में जाकर क्लर्क से पूछा कि उनकी झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना की पेंशन क्यों नहीं आ रही है। इस पर क्लर्क ने महिला को साइट बंद होने की बात बताई। पूनम की तरह दर्जनों महिलाएं कार्यालय में जमा थीं। सबको साइट नहीं खुलने की बात बताई जा रही थी।

जन शिकायत कोषांग पहुंचीं महिलाएं • फोटोन न्यूज

आज तक खाते में नहीं आया पैसा

सामाजिक सुरक्षा कोषांग आई महिलाओं का कहना है कि वह कई महीने से अंचल कार्यालय से लेकर डीसी दफ्ततर तक दौड़ रही हैं। मगर, उनकी पेंशन की रकम नहीं आई है। कोई भी अधिकारी सही बात नहीं बता रहे हैं। सब यही आश्वासन दे रहे हैं कि जल्द ही रकम आ जाएगी। अब तक पैसा क्यों नहीं आ रहा यह एक पहेली है। अंचल के अधिकारी डीसी दफ्तर जाने की बात कहते हैं। जबकि, डीसी ऑफिस से उन्हें अंचल कार्यालय भेजा जा रहा है।

कई महिलाओं को नहीं मिली जनवरी से मार्च तक की राशि

जनवरी से मार्च तक की राशि सरकार ने भेज दी है। जिन महिलाओं का खाता डीबीटी है, उनके खाते में यह राशि पहले ही चली गई है। 7500 रुपये एक खाते में भेजे गए हैं। मगर, जिन महिलाओं के बैंक खाते नॉन डीबीटी थे, सरकार ने उन खातों में रकम नहीं भेजने को कहा था। हालांकि, बाद में सरकार ने अपना आदेश पलट दिया और नॉन डीबीटी खाते में रकम भेजने के आदेश दिए। तब से यह रकम नॉन-डीबीटी खातों में भेजी जा रही है। बुधवार को ऐसी कई महिलाएं सामाजिक सुरक्षा कोषांग के कार्यालय पहुंचीं, जिनका खाता नॉन डीबीटी है। इन्हें बताया गया कि उनके खाते में रकम भेजी जा रही है। इन महिलाओं का कहना है कि वह कई दिनों से दौड़ रही हैं। सामाजिक सुरक्षा विभाग के कर्मचारी उन्हें हर बार यही जानकारी देते हैं। मगर, अब तक खाते में पैसा नहीं गया है।

देसी शराब व 200 किलो महुआ जब्त दो गिरफ्तार

CHAIBASA : पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग के अवर निरीक्षक निर्भय कुमार सिंह के नेतृत्व में छापेमारी की गई। इसमें शिव मंदिर टोला के पास भारी मात्रा में देसी शराब और 200 किलो जावा महुआ जब्त किया गया। इसी दौरान दो शराब विक्रेताओं को गिरफ्तार भी किया गया।

न्यूनतम मानदेय को लेकर 108 एंबुलेंस के चालकों ने की हड़ताल

चाईबासा स्थित सदर अस्पताल परिसर में नारेबाजी करते एंबुलेंस चालक

CHAIBASA : पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा सदर अस्पताल परिसर में बुधवार को आपातकालीन 108 एंबुलेंस के चालकों ने झारखंड सरकार से न्यूनतम मानदेय भुगतान कराने की मांग पर बैठक की, जिसके बाद वे अनिश्चतकालीन हड़ताल पर चले गए। बैठक की अध्यक्षता कर रहे शैलेंद्र महतो ने कहा कि सम्मान फाउंडेशन संस्था द्वारा 4 फरवरी 2025 से राज्य में 108 एंबुलेंस का संचालन किया जा रहा है, परंतु फरवरी और मार्च का न्यूनतम मानदेय अभी तक नहीं दिया गया है। जिले में आधे से ज्यादा एंबुलेंस बंद होने के कारण मरीजों को समय पर एंबुलेंस उपलब्ध कराने में असक्षम हो रहे है। जो एंबुलेंस चल रहे है, वह भी खराब स्थिति में हैं। एंबुलेंस में फर्स्टएड किट व ऑक्सीजन से संबंधित समस्या शुरू से ही है। एंबुलेंस चालकों ने उपायुक्त व सिविल सर्जन को मांगपत्र भी सौंपा है। धरना-प्रदर्शन में प्रद्युम्न महतो, शुभम प्रधान, रोहित चंद्र महतो, प्रेम सिंह ओरिया, कैलाश कुमार, संतोष कुमार महतो, अमर महतो, मुकेश महतो, हेमंत कुमार गोप, जितेंद्र नाथ महतो, निर्मल महतो, सचिन कुमार महतो आदि भी शामिल थे।

BRIEF NEWS

मवेशी लदी गाड़ी पलटी चार मवेशियों की मौत एक सवार घायल

ARARIA : बिहार में अररिया जिला ढोलबज्जा के निकट एनएच 27 फोरलेन सड़क पर बीती देर रात ट्रक के ठोकर से मवेशी लदा पिकअप गाड़ी पलट गई। जिससे पिकअप पर लोड चार मवेशी की मौत हो गई। जबकि दो मवेशी घायल हो गए। पिकअप पर सवार तीन लोग भी गंभीर रूप से जख्मी हो गया। जिसे इलाज के लिए देर रात फारबिसगंज अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया और उनका इलाज किया गया। घायलों में सिमरबनी पिपरा वार्ड संख्या दो के रहने वाले मुस्तफा पिता मो.फूल हसन,सिमरबनी सिमरिया वार्ड संख्या तीन के मनीष कुमार पिता वीरेन्द्र मंडल और सिमरबनी वार्ड संख्या दो के अब्दुल गफ्फार पिता मो.अब्दुल अंसारी है।

नालंदा में किसानों का यूनिक फार्मर आईडी बनाने का कार्य शुरू

NALANDA : नालंदा जिलान्तर्गत प्रखंड के माधोपुर पंचायत में किसानों के लिए यूनिक फार्मर आईडी बनाए जाने का कार्य 11 अप्रैल से प्रारंभ हो गया है। यह पहल आधार कार्ड की तर्ज पर की जा रही है, जिसका उद्देश्य किसानों को एक विशिष्ट डिजिटल पहचान प्रदान करना और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक सरलता से पहुंचाना है।अभी तक कुल 21 किसानों का सफलतापूर्वक पंजीकरण किया गया है। प्रखंड कृषि पदाधिकारी (प्रशिक्षु) अनीशा कुमारी ने बताया यूनिक फार्मर आईडी के माध्यम से किसानों का पूरा प्रोफाइल एक क्लिक पर उपलब्ध हो जाएगा। इससे उन्हें सस्ती दरों पर ऋण, कृषि इनपुट, तकनीकी सलाह और विपणन की सुविधा भी आसानी से मिलेगी। उन्होंने यह भी बताया कि चालू वित्तीय वर्ष से कृषि विभाग की सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए फार्मर आईडी अनिवार्य कर दिया गया है।

बाहुबली राजद विधायक रीतलाल पर कसा शिकंजा

PATNA : दानापुर से राजद के बाहुबली विधायक रीतलाल यादव पर पटना पुलिस ने शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) अवकाश कुमार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अपराधों में संलिप्त प्रभावशाली व्यक्तियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ी तो रीतलाल यादव की गिरफ्तारी की जाएगी। यदि वे फरार रहते हैं, तो न्यायालय से वारंट प्राप्त कर नोटिस जारी किया जाएगा और संपत्ति की कुर्की की जाएगी। अवकाश कुमार ने बताया कि बिल्डर द्वारा दिए गए आवेदन के साथ एक ऑडियो पेन ड्राइव भी मिली है, जिसमें रंगदारी और धमकी का उल्लेख है। ऑडियो की आवाज का मिलान फॉरेंसिक जांच से कराया जा रहा है।

विधानसभा चुनाव से पहले जनता दल (यूनाइटेड) कार्यालय में अब बदल गया पोस्टर, लिखा-

2025 से 30, फिर से नीतीश, सुशासन को बताया जीत का मंत्र

AGENCY PATNA : पटना में विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू ऑफिस में पोस्टर को बदला गया है। चुनाव को लेकर पार्टी कार्यालय को नए अंदाज में सजाया गया है। पुराने पोस्टरों को हटाकर सीएम नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ अब नई टैगलाइन और स्लोगन वाले पोस्टर लगाए गए हैं। इसके माध्यम से सरकार की योजनाओं, उपलब्धियों और नीतीश कुमार की छवि को जनता के सामने लाने की कोशिश की गई है। एक पोस्टर पर लिखा गया है, '2025 से 2030 फिर से नीतीश कुमार'

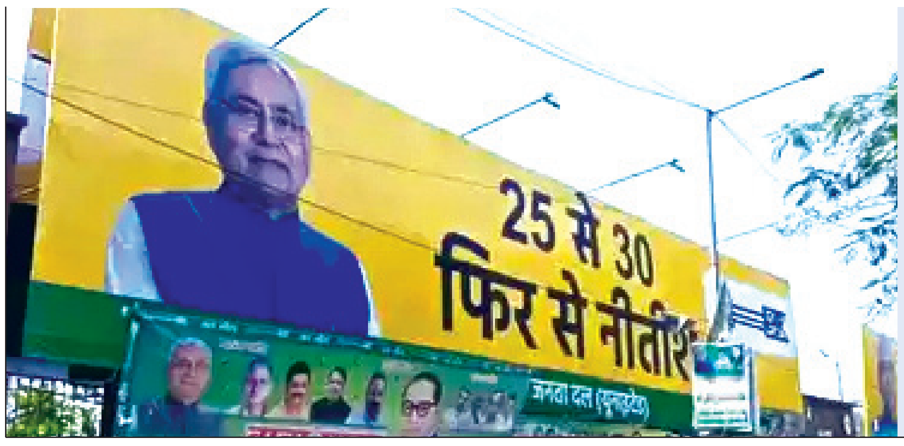

जो स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री के कार्यकाल को आगे बढ़ाने की मंशा को दशार्ता है। साथ ही इन पोस्टरों के जरिए जदयू ने यह संकेत भी दे दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही पार्टी का चेहरा बने रहेंगे।

सुशासन की रफ्तार, बिहार में बहार : अन्य पोस्टरों में रोजगार, महिला सशक्तिकरण और सुशासन की उपलब्धियों को दिखाया गया है। जिस पर लिखा है, 'रोजगार मतलब नीतीश सरकार।' बहन बेटियों के सपने साकार, धन्यवाद नीतीश सरकार और 'सुशासन की रफ्तार, बिहार में बहार' जैसे नारे लिखे गए हैं।

पिताजी ही होंगे बिहार के अगले सीएम : निशांत

वहीं, मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने कहा था, 'उनके पिता पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उनकी सेहत को लेकर किसी भी तरह की अफवाह निराधार है। वे पहले की तरह सक्रिय हैं। उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे।' दरअसल, नीतीश कुमार की तबीयत को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही थीं, जिनका निशांत ने खंडन किया है।

2010 की तरह समर्थन करने की जनता से अपील

निशांत ने जनता से अपील की कि वे एनडीए की सरकार बनाएं। 2010 की तरह इस बार भी भरपूर समर्थन दें। उन्होंने यह भी दोहराया कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। इसकी पुष्टि भाजपा नेता अमित शाह और सम्राट चौधरी ने भी की है। हालांकि, जब निशांत से खुद के राजनीति में आने के सवाल पर पूछा गया तो उन्होंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया।

सर्किल अधिकारी प्रिंस राज के दो ठिकानों पर एसवीयू की रेड

करोड़ों की अचल संपत्ति, संदिग्ध जमीन सौदों से जुड़े दस्तावेज भारी नकद व कई शेल कंपनियों से जुड़ी जानकारी लगी हाथ

AGENCY PATNA : विशेष निगरानी इकाई (एसवीयू) ने सर्किल अधिकारी (सीओ) प्रिंस राज के दो ठिकानों पर आज सुबह छापेमारी की है। यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति के मामले में की गई है। छापेमारी शेखपुरा और मधुबनी स्थित उनके ठिकानों पर एक साथ की गई, जिससे इलाके में हलचल मच गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सीओ प्रिंस राज पर उनके ज्ञात स्त्रोतों से कहीं अधिक संपत्ति रखने का आरोप है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उनके पास आय से लगभग 90 प्रतिशत अधिक संपत्ति पाई गई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए एसवीयू ने उनके ठिकानों पर एक संगठित तरीके से छापेमारी की।

छापेमारी की इस कार्रवाई में एसवीयू की एक विशेष टीम शामिल है, जिसका नेतृत्व डीएसपी स्तर के अधिकारी कर रहे हैं। टीम ने दोनों ठिकानों पर

सर्किल अधिकारी प्रिंस राज के ठिकानों पर छापेमारी करती एसवीयू की टीम

- शेखपुरा और मधुबनी स्थित उनके ठिकानों पर एक साथ की गई छापेमारी
- सीओ पर उनके ज्ञात स्त्रोतों से कहीं अधिक संपत्ति रखने का है आरोप

दस्तावेजों की जांच, नकदी और अन्य कीमती सामान की गिनती शुरू कर दी है। संभावना है कि कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और प्रमाण बरामद किए जा सकते हैं, जो इस मामले की गहराई को उजागर कर सकते हैं।

अभी तक एसवीयू की ओर से कोई आधिकारिक प्रेस रिलीज नहीं आई है, लेकिन सूत्रों की मानें तो छापेमारी के दौरान टीम को करोड़ों रुपये की अचल संपत्ति, संदिग्ध जमीन सौदों से जुड़े दस्तावेज, भारी नकदी और कई शेल कंपनियों से जुड़ी जानकारी हाथ लगी है। इसके अलावा कुछ डिजिटल डिवाइस भी जब्त किए गए हैं जिनका विश्लेषण विशेषज्ञों द्वारा किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि सीओ प्रिंस राज को हाल ही में सरकार ने निलंबित कर दिया था। हालांकि उस समय निलंबन के पीछे स्पष्ट कारण सार्वजनिक नहीं किया गया था, लेकिन अब यह छापेमारी यह संकेत दे रही है कि भ्रष्टाचार से जुड़े गंभीर आरोप पहले से ही उनके खिलाफ जांच एजेंसियों के पास थे।

निर्वाचन आयोग ने शुरू की बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां, बीएलए को दिया जा रहा प्रशिक्षण

AGENCY PATNA : भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने बिहार विधानसभा के आगामी चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आयोग ने इसके मद्देनजर बिहार के बूथ लेवल एजेंटों (बीएलए) का प्रशिक्षण शुरू कर दिया है। भारत अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनाव प्रबंधन संस्थान (आईआईआईडीईएम) नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में बिहार के मान्यता प्राप्त 10 राजनीतिक दलों से जुड़े लगभग 280 बीएलए हिस्सा ले रहे हैं।

प्रशिक्षण के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार व अन्य

प्रशिक्षण के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी ने बीएलए को संबोधित किया। बीएलए को उनकी नियुक्ति, भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी दी गई। बीएलए को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त किया जाता है और वे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के प्रावधानों के अनुसार त्रुटि-रहित मतदाता सूची सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

विपक्षी दलों का महागठबंधन स्वार्थ पर आधारित : श्रवण कुमार

PATNA : मंत्री श्रवण कुमार ने विपक्षी दलों के महागठबंधन को निहित स्वार्थों पर आधारित बताया है। उन्होंने कहा कि इस गठबंधन की वास्तविकता दिल्ली चुनाव में उजागर हो चुकी है, जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक-दूसरे के विरोध में खड़ी दिखीं। वह बुधवार को पार्टी कार्यालय में जनसुनवाई कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। श्रवण कुमार ने कहा कि प्रदेश की प्रगति में रुचि रखने वाले तथा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन के प्रति आस्था रखने वाले सभी लोगों का एनडीए में स्वागत है।

प्रकृति ने फिर दिखाया रौद्र रूप, लाखों की फसलें नष्ट

AGENCY NALANDA : पिछले सात दिनों से नालंदा जिले में तेज आंधी ने क्षेत्र के किसानों की कमर तोड़ दी है। मौसम की बेरुखी से प्याज, मक्का और गेहूं की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे किसानों की मेहनत और पूंजी दोनों पर पानी फिर गया है। सब्जी उत्पादकों की हालत भी खराब हो गई है। लगातार आंधी-पानी से बिगड़ा हाल शनिवार की रात आई तेज आंधी और बारिश से किसान अभी उबरे भी नहीं थे कि सोमवार की दोपहर और मंगलवार की रात एक बार फिर मौसम ने विकराल रूप धारण कर लिया दोपहर करीब 3 बजकर 10 मिनट पर आसमान में बादल छा गए और कुछ ही देर में अंधेरा घिर गया। तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी चली और फिर मूसलधार बारिश शुरू हो गई, जो शाम 5 बजे तक रुक-रुककर होती रही। इस दौरान खेतों में खड़ी फसलें या तो गिर गईं या पानी में डूब गईं। प्याज की तैयार फसल जलभराव में बर्बाद नगरनौसा प्रखंड में इस वर्ष रबी मौसम में लगभग 125 से 150 हेक्टेयर में प्याज की खेती की गई थी। फसल पूरी तरह से पक चुकी थी और कई किसान इसकी कटाई में जुटे थे। लेकिन लगातार बारिश के कारण खेतों में जल जमाव हो गया और तैयार प्याज की फसल सड़ने लगी। मोनियमपुर गांव के किसान बाल्मिकी प्रसाद ने बताया कि, बार-बार आ रही आंधी और पानी से खेतों में तैयार प्याज सड़ गया है। अब इसे उचित दाम पर बेचना असंभव है। भीगे प्याज का भंडारण नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह जल्दी खराब हो जाएगा। मक्का की फसल धराशायी, नुकसान अपार प्रेमन बिगहा गांव के किसान राजेश कुमार ने बताया कि तेज हवाओं और बारिश की वजह से अधिकतर खेतों में मक्के की फसल गिर चुकी है।फसल पर दाने भी आ चुके थे, लेकिन अब गिर चुकी फसल को बचा पाना संभव नहीं। कुछ किसान इसे पशुओं के चारे के रूप में उपयोग करने की सोच रहे हैं। हालांकि जिन खेतों में पौधे अभी छोटे थे, उन्हें अपेक्षाकृत कम नुकसान हुआ है। सब्जी उत्पादक भी परेशान, रोगों का खतरानगरनौसा प्रखंड फल और सब्जी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन हालिया खराब मौसम ने सब्जी उत्पादकों को भी नहीं बख्शा।

कांग्रेस ने की जेपी गंगा पथ पर दरारों व पुलों के ढहने की न्यायिक जांच की मांग

PATNA @ PTI : बिहार में विपक्षी दल कांग्रेस ने पटना के जेपी गंगा पथ के नये खंड में कथित रूप से आई दरारों और कई पुलों के ढहने की घटनाओं की न्यायिक जांच किए जाने की मंगलवार को मांग की। पार्टी ने कहा कि मामले की जांच पटना उच्च न्यायालय के किसी मौजूदा न्यायाशीध से कराई जानी चाहिए।

कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, बिहार में पुल नहीं बन रहे हैं, बल्कि भ्रष्टाचार की नींव रखी जा रही है। राज्य के विभिन्न जिलों में 2024 में छोटे-बड़े एक दर्जन पुल ढहने की घटनाएं हुईं।

खान ने कहा, राज्य सरकार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा उद्घाटन किए जाने के कुछ दिनों बाद पटना के जेपी गंगा पथ के एक हिस्से में आई दरारों तथा अन्य पुलों के निर्माण के संबंध में पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश द्वारा न्यायिक जांच का आदेश देना चाहिए।

कार्यशाला में बोले पीएचईडी के मुख्य सचिव- नल जल योजना सिर्फ स्कीम नहीं, राष्ट्रीय संकल्प

AGENCY PATNA : राज्य में गहराते पेयजल संकट और हर घर नल का जल योजना को जमीन पर प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रन विभाग, मनरेगा और दूसरे संबंधित विभाग के सीनियर अधिकारी और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यशाला को संबोधित करते हुए पंकज कुमार ने कहा- देश में पेयजल संकट सबसे बड़ी चुनौती है।

पंकज कुमार ने कहा कि नल जल योजना से राज्य के हर नागरिक को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा- यह सिर्फ एक योजना नहीं है। बल्कि हर

नागरिक को स्वच्छ और सुरक्षित जल उपलब्ध कराने का राष्ट्रीय संकल्प है। पंकज कुमार ने कहा- इसके लिए पीएचईडी, मनरेगा और अन्य विभागों को मिलकर कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि नल जल योजना सिर्फ योजना नहीं यह राष्ट्रीय संकल्प है।

आगा की ओर से आयोजित कार्यशाला में भू-जल स्तर में लगातार गिरावट को लेकर चर्चा हुई। गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा- देश के कई हिस्सों में भूजल पर ज्यादा निर्भरता की वजह से जलस्तर तेजी से गिरा है। उन्होंने वर्षा जल संचयन, भूजल रिचार्ज, जल संरक्षण उपायों को ग्रामीण योजनाओं से जोड़ना जैसे कुछ समाधान बताए। जबकि मुख्य सचिव पंकज कुमार ने सुझाव दिया कि मनरेगा के तहत तालाब, चेक डैम और जल संरचनाओं के निर्माण की गति बढ़ाई जाए।

सीएम हाउस में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने देखी डॉक्यूमेंट्री, लालू शासन काल व एनडीए की वर्तमान सरकार की हुई तुलना

नेशनल हेराल्ड मामले पर सम्राट चौधरी ने गांधी परिवार को घेरा

AGENCY PATNA : उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित बीजेपी के कई बड़े नेता बुधवार को सीएम हाउस पहुंचे। यहां एक बैठक हुई। बैठक में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई गई, जिसमें 2005 से पहले बिहार में लालू प्रसाद यादव के शासन काल की स्थिति और वर्तमान एनडीए सरकार के कार्यकाल की तुलना की गई।

फिल्म के जरिए राज्य की कानून-व्यवस्था, विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं को दशार्या गया, ताकि आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए एक मजबूत नैरेटिव तैयार किया जा सके। इस बैठक में केंद्रीय गृह

राज्य मंत्री नित्यानंद राय, मंत्री प्रेम कुमार और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी शामिल हुए। जानकारी के मुताबिक, बैठक के दौरान वीआईपी पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी को लेकर भी चर्चा हुई है। विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में उनकी वापसी को लेकर गहन विचार-विमर्श चल रहा है। सहनी, जो पहले एनडीए का हिस्सा रह चुके हैं, हाल के दिनों में फिर से सत्तारूढ़ गठबंधन के संपर्क में बताए जा रहे हैं।

इसके पहले उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पीसी की थी। इसमें नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर गांधी फैमिली पर जमकर बरसे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी की राज माता सोनिया गांधी ने भारत को लूटा है।

कांग्रेस पार्टी ने मनमोहन सिंह और अपने चेहरे पर कालिख पोती है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ही ईडी का गठन किया था। कांग्रेस ने लोकतंत्र का मजाक बनाया है।

कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने कैसे इस लोकतंत्र को मजाक बनाया, ये सब जानते हैं। उन पर सबसे गंभीर आरोप है कि स्वतंत्रता सेनानियों की चीजों को लूटा गया है। चार्जशीट में सोनिया गांधी राहुल गांधी का भी नाम है। नेशनल हेराल्ड का मामला पूरे देश को जानना चाहिए। पटना ईडी ऑफिस में कांग्रेस पार्टी ने जो किया, वहां भी कालिख पोती।

पुरानी रंजिश को ले गोलीबारी, 20 खोखा के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार

AGENCY NAVADA : नवादा जिले के काशीचक थाना क्षेत्र के लीला बिहार गांव में बुधवार को दो पक्षों के बीच हुई गोलीबारी की घटना में पुलिस ने दो अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने घटनास्थल से कारतूस के 20 खोखे भी बरामद किए। काशीचक के थाना अध्यक्ष बसंत कुमार ने बताया कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। वायरल वीडियो में कई लोग हथियार लहराते और फायरिंग करते हुए नजर आ रहे थे। यह वीडियो नवादा जिले के काशीचक थाना क्षेत्र भवानीपुर और लीला बीघा गांव का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में खुलेआम हथियार लहराकर कई राउंड फायरिंग करते लोग नजर आ रहे हैं।एसपी अभिनव ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए विशेष टीम का गठन किया, जिसके बाद इलाके में व्यापक छापेमारी अभियान चलाया गया। फायरिंग के संबंध में बताया जा रहा है कि यह मामला दो पक्षों के आपसी जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो लोगों को 20 गोली और खोखे के साथ गिरफ्तार किया है।

पुणे के व्यवसायी के अपहरण, हत्या मामले में महिला समेत सात लोग गिरफ्तार

PATNA @ PTI : बिहार पुलिस ने पुणे के एक व्यवसायी के अपहरण और हत्या के सिलसिले में एक महिला सहित सात लोगों को गिरफ्तार किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। लक्ष्मण साधु शिंदे का शव मंगलवार को बिहार के जहानाबाद जिले में मिला था। वह 11 अप्रैल को पटना हवाई अड्डे पर उतरे थे। अधिकारी ने बताया कि अपहरण और हत्या को अंजाम देने वाले गिरोह के सरगना को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि चार अन्य को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। गिरफ्तार लोगों की पहचान रंजीत पटेल उर्फ मुन्ना, विपतरा कुमार, लालबिहारी, विकास उर्फ मोहित, कुंदन कुमार, संगीता कुमारी और सचिन रंजन के रूप में हुई है।

सरदार पटेल को लेकर जो कहा गया, उससे अलग है सच

अहमदाबाद में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर कांग्रेस द्वारा किए जानेवाले कार्यक्रमों के बारे में बताते हुए जिस बात पर जोर दिया, वह था कि सरदार पटेल और नेहरूजी के बीच गहरे और मधुर संबंध थे, किंतु इतिहास तो कुछ और ही कह रहा है। अब कांग्रेस इस बात को कितना छिपाएगी कि जवाहरलाल नेहरू ने अपने समय में सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे श्रेष्ठ नेताओं के साथ कैसा व्यवहार किया है। आज कांग्रेस सरदार पटेल को लेकर कितना ही झूठा नैरेटिव गढ़ने का प्रयास करे, लेकिन इससे सच नहीं बदलने वाला है। इतिहास काल का वह पन्ना है, जिसमें एक बार जो कहानी लिख जाती है, वह फिर मिटाए नहीं मिटती, क्योंकि यह इतिहास फिर कभी अपनी वैसी ही पुनरावृत्ति नहीं करता, जैसा कि तत्कालीन समय में घटता है। कांग्रेस ने वास्तव में जो सरदार पटेल के साथ किया, उसे कभी माफ नहीं किया जा सकेगा। सरदार पटेल की जब मृत्यु हुई, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की एक घोषणा सामने आई और इस घोषणा के तुरंत बाद एक आदेश भी आया। उस आदेश में दो बातों का प्रमुखता से जिक्र था, पहला- सरदार पटेल को दी गई सरकारी कार उसी वक्त वापस ले ली जाए और दूसरा- गृह मंत्रालय के वे सचिव-अधिकारी जो सरदार-पटेल के अंतिम संस्कार में बंबई जाना चाहते हैं, वे अपने खर्चे पर जाएं। सरदार पटेल के प्रति नेहरू के अंदर का विद्वेष इतना करके भी रुक जाता, तब भी बहुत होता, किंतु वह कहां माननेवाले थे। उसके बाद नेहरू ने अपने मंत्रिमंडल की तरफ से तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद को कहलवाया कि वे सरदार पटेल के अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए नहीं जाएं, पर जब नेहरू को पता चला कि वे अंतिम संस्कार में जा रहे हैं,ज्ञतो तुरंत उन्होंने वहां सी. राजगोपालाचारी को भेजा और जो सरकारी श्रद्धांजलि (स्मारक) पत्र राष्ट्रपति के नाते डॉ. राजेंद्र प्रसाद द्वारा पढ़ा जाना था, वह उनसे न पढ़वाते हुए उसे सी. राजगोपालाचारी को सौंप दिया गया। इतना होने के बाद भी जवाहरलाल नेहरू के अंदर सरदार पटेल को लेकर जो गुस्सा भरा था, वह कम होने का नाम नहीं ले रहा था। यदि यह सच नहीं है, तो फिर क्यों बार-बार कांग्रेस के अंदर से पटेल का स्मारक बनाने की मांग उठ रही थी और कहा जा रहा था कि इतने बड़े नेता की याद में सरकार को कुछ करना चाहिए, पर नेहरू लगातार विरोध करते रहे, फिर जब नेहरू ने देखा कि पार्टी में उनके प्रति मनमुटाव पैदा हो रहा है, तब जाकर उन्होंने इस बारे में सोचे जाने और कुछ करने की हामी भरी थी। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में नेहरू के खिलाफ सरदार पटेल के नाम को रखने वाले वरिष्ठ कांग्रेसी पुरुषोत्तमदास टंडन को पार्टी से बाहर कर देने का उनका फरमान भी पटेल के प्रति नेहरू की अंदरूनी नफरत को प्रदर्शित करता है, जबकि होना ये चाहिए था कि समर्पण दोनों तरफ का होता, देश की स्वाधीनता में जो सरदार पटेल का योगदान रहा, वह अद्वितीय है, जो सरदार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे, उन्होंने महात्मा गांधी के कहने पर गृहमंत्री बनना स्वीकार किया। फिर भी हो क्या रहा था ये समर्पण एकतरफा दिखाई दे रहा था। नेहरू का रुख सरदार के प्रति उनके अंतिम समय तक नहीं बदला। दूसरी ओर सरदार वल्लभ भाई पटेल महात्मा गांधी से वचनबद्ध थे, वह पहले ही उनके सामने ये हामी भर चुके थे कि वे जवाहरलाल नेहरू को अकेला नहीं छोड़ेंगे, जब तक उनकी सासें चल रही हैं, उनका नेहरू के प्रति एकतरफा समर्पण रहेगा। जो उन्होंने महात्मा गांधी से कहा, उसे अपनी अंतिम सांस तक पूरी शिद्दत के साथ निभाया भी। किंतु, दूसरी तरफ जवाहरलाल थे, जिन्होंने सरदार पटेल को लेकर अपनी अंदर एक नकारात्मक ग्रंथी एक बार पाल ली तो वे कभी उससे बाहर ही नहीं निकले। विजन बुक्स द्वारा प्रकाशित पुस्तक इनसाइड स्टोरी ऑफ सरदार पटेल स्टोरी : द डायरी ऑफ मणिबेन पटेल 1936-50, जो सरदार पटेल की बेटी द्वारा अब तक अज्ञात डायरी का पहला प्रकाशन है, बहुत कुछ कह देती है। वस्तुतः मणिबेन आमतौर पर पटेल के साथ हर जगह जाती थीं और सरदार की ज्यादातर बैठकों में उनके साथ मौजूद रहती थीं। इसलिए वह इन बैठकों में होने वाली घटनाओं और सरदार के विचारों और विभिन्न ऐतिहासिक और संवेदनशील मुद्दों पर उनके अंतरतम विचारों से अवगत थीं, जिन्हें वह अक्सर अपने सबसे करीबी दोस्तों और सहकर्मियों के सामने भी व्यक्त नहीं कर पाते थे। इसके अलावा गांधीजी की देखभाल में कई साल बिताने और उच्च बुद्धि रखने के कारण मणिबेन उस समय की घटनाओं और नाटकीय पात्रों के संदर्भ और महत्व दोनों को समझती थीं। यह डायरी 8 जून 1936 से लेकर 15 दिसंबर 1950 को सरदार की मृत्यु तक की है। इसमें 1945 में पटेल की जेल से रिहाई के बाद का विस्तृत विवरण है। इसमें भारत के इतिहास के उस निर्णायक काल के बारे में अक्सर खुलासा करने वाले, कभी-कभी विस्फोटक विवरण और अंतर्दृष्टि का खजाना है, जिसमें देश की स्वतंत्रता, विभाजन, रियासतों का एकीकरण, गांधीजी की हत्या और फिर भारत के स्वशासन के प्रारंभिक, महत्वपूर्ण वर्ष शामिल हैं, जिनमें पटेल की एक अपरिहार्य महत्वपूर्ण भूमिका थी। अपनी इस डायरी में मणिबेन लिखती हैं, पटेल-नेहरू के मतभेदों में कई लोगों ने भूमिका निभाई थी, विशेष रूप से रफी अहमद किदवई, समाजवादियों और मौलाना आजाद ने भी। डायरी सरदार को मंत्रिमंडल से बाहर करने के लिए उनकी चालों का खुलासा करती है। मणिबेन ने लिखा है- सरदार पटेल नेहरू-लियाकत अली समझौते से खुश नहीं थे, क्योंकि इसने पूर्वी पाकिस्तान से हिंदुओं के पलायन को नहीं रोका जो बढ़ता ही गया और बड़ी संख्या में हिंदू भारत में पलायन करते रहे। सरदार पटेल ने देखा कि वे हत्याओं के बारे में इतने चिंतित नहीं थे, आखिरकार बंगाल के अकाल में 30 लाख लोग मारे गए थे, लेकिन वे महिलाओं पर हमले और उन्हें जबरन इस्लाम में धर्मांतरित किए जाने को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे।

सच का सामना करने को तैयार नहीं कांग्रेस

ANALYSIS

मनोज कुमार मिश्र

चुनाव हारने के बाद हर बार कांग्रेस और विपक्ष के नेता ईवीएम पर सवाल उठाते आए हैं। वे शायद भूल गए हैं कि लोकतंत्र को कुचलने के लिए आजादी के बाद एक ही बार आपातकाल लगा, वह भी कांग्रेस की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासन में। इसी तरह वक्फ संशोधन विधेयक पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर कथित रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आएसएस) के नियंत्रण के खिलाफ आंदोलन चलाने की बात कही। वे यह अफसोस जता रहे थे कि कांग्रेस ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम वोट को साथ रखने के प्रयास में अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) से दूरी बना ली और जातिगत गणना करवाने के लिए आंदोलन तेज करने के दावे किए। दो दिनों के अधिवेशन में अनेक भाषण हुए और प्रस्ताव पास हुए, लेकिन पूरी बैठक में पार्टी भ्रम में जीती दिखी। पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि जो सक्रिय नहीं रह सकता, वह पार्टी छोड़ दे। इस अधिवेशन में न तो इस पर ठीक से चर्चा हुई कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जिन बड़े राज्यों तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात इत्यादि से कांग्रेस एक बार पराजित हुई, तो वहां सालों-साल उसकी वापसी नहीं हो पाई। राष्ट्रीय स्तर पर भी वह लगातार तीन बार से सत्ता से बाहर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जितनी आलोचना वे करते हैं, पार्टी की राजनीतिक जमीन उतनी ही खिसकती जा रही है।

लगातार सिमटती जा रही कांग्रेस अभी भी सच का सामना करने को तैयार नहीं है। पिछले दिनों गुजरात में अहमदाबाद के साबरमती तट पर अपने दो दिवसीय अधिवेशन में कांग्रेस खोई जमीन पाने का सही रास्ता नहीं ढूंढ़ पाई। सालों बाद नेहरू-गांधी परिवार से बाहर के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष बने हैं। उनका कहना था कि कांग्रेस कार्यकर्ता लोकतंत्र के लिए आजादी की दूसरी लड़ाई में पूरी ताकत से जुटें। उन्होंने ईवीएम को धोखाधड़ी बताते हुए फिर से बैलट पेपर से चुनाव कराए जाने की मांग की। चुनाव हारने के बाद हर बार कांग्रेस और विपक्ष के नेता ईवीएम पर सवाल उठाते आए हैं। वे शायद भूल गए हैं कि लोकतंत्र को कुचलने के लिए आजादी के बाद एक ही बार आपातकाल लगा, वह भी कांग्रेस की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासन में। इसी तरह वक्फ संशोधन विधेयक पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर कथित रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आएसएस) के नियंत्रण के खिलाफ आंदोलन चलाने की बात कही। वे यह अफसोस जता रहे थे कि कांग्रेस ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम वोट को साथ रखने के प्रयास में अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) से दूरी बना ली और जातिगत गणना करवाने के लिए आंदोलन तेज करने के दावे किए। दो दिनों के अधिवेशन में अनेक भाषण हुए और प्रस्ताव पास हुए, लेकिन पूरी बैठक में पार्टी भ्रम में जीती दिखी। पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि जो सक्रिय नहीं रह सकता, वह पार्टी छोड़ दे। इस अधिवेशन में न तो इस पर ठीक से चर्चा हुई कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जिन बड़े राज्यों तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात इत्यादि से कांग्रेस एक बार पराजित हुई, तो वहां सालों-साल उसकी वापसी नहीं हो पाई। राष्ट्रीय स्तर पर भी वह लगातार तीन बार से सत्ता से बाहर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जितनी आलोचना वे करते हैं, पार्टी की राजनीतिक जमीन उतनी ही खिसकती जा रही है। कांग्रेस को आजादी के 77 साल बाद देश के पहले उप प्रधानमंत्री, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद आई। बावजूद इसके, जिस राज्य में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसी राज्य के केवड़िया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर बनी दुनिया की सबसे ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा को नमन करने कोई कांग्रेस नेता आज तक नहीं गया। अंग्रेजों ने 1947 में देश को आजाद करने के साथ-साथ पांच सौ से अधिक रियासतों को भारत या पाकिस्तान में विलय करने की स्वतंत्रता देकर नई मुसीबत खड़ी कर दी थी। सरदार पटेल के प्रयास से उन रियासतों का भारत में विलय हुआ। सरदार पटेल आजादी के बाद कम समय जीवित रह पाए, लेकिन उनकी कीर्ति का देश हजारों साल कर्जदार रहेगा। महात्मा गांधी से सलाह करके ही सरदार पटेल ने ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। इस मंदिर के प्रण-प्रतिष्ठा समारोह में देश के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद शामिल हुए। इसकी चर्चा करने से कांग्रेस के नेता बचते हैं। यह सर्वविदित है कि अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर मंदिर बनाने का निर्णायक आंदोलन आरएसएस के संरक्षण में विश्व हिंदू परिषद आदि ने चलाया और अदालत के फैसले के बाद भव्य मंदिर का निर्माण लगभग अंतिम चरण में है। 22 जनवरी 2024 को हुए प्राण-प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस का कोई बड़ा नेता शामिल नहीं हुआ, जबकि मंदिर का ताला केंद्र में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहने के दौरान खुला था। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में देश-दुनिया के लोग बड़ी तादाद में आए। इसी तरह प्रयागराज के महाकुंभ में लोगों के आने का नया रिकॉर्ड बना, लेकिन कांग्रेस का कोई चर्चित चेहरा उसमें नहीं दिखा। सबसे अजूबा यह है कि जिस कांग्रेस का पूरा ही नेतृत्व राष्ट्रवादी धारा के खिलाफ हर तरह का आचरण कर रहा है, वह पूरी तरह से राष्ट्रवादी विचार पर चले आजादी के आंदोलन जैसा आंदोलन चलाने की बात कह रही है। यह साबित हो गया है कि वक्फ संशोधन कानून का विरोध केवल पैसे वाले, प्रभावशाली या आम भाषा में कहें तो माफिया कर रहे हैं, उसी को आधार बना कर कांग्रेस आंदोलन चलाना चाहती है। इस समय राहुल गांधी, उनकी बहन प्रियंका गांधी और मां सोनिया गांधी, तीनों संसद के सदस्य हैं। संसद के दोनों सदनों में इस विधेयक पर हुई चर्चा में इनमें से कोई शामिल नहीं हुआ। यह सही है कि कभी कांग्रेस को ब्राह्मण, दलित और अल्पसंख्यकों का सर्वाधिक समर्थन मिलता रहा। कांग्रेस सौ साल से अधिक पुरानी पार्टी है और देश और अधिकतर राज्यों में सबसे ज्यादा समय तक कांग्रेस का ही राज रहा। सालों कांग्रेस देश की अकेली पार्टी थी, जिसका झंडा, चुनाव चिह्न और नेता गांव-गांव के लिए परिचित था। तब भी देश की आधे से ज्यादा आबादी ओबीसी की ही थी, यह आज भी है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल इस तरह के जातीय समीकरण से परे माना गया था। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस का विभाजन कराया और सत्ता में रहकर बांग्लादेश को आजाद कराया। गरीबी हटाओ नारा भले ज्यादा कारगर न हुआ, लेकिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण, प्रिवी पर्स की समाप्ति बड़े मुद्दे बने। यह अजब संयोग है कि जिस पार्टी में यह नारा लगता था- जात पर न पात पर इंदिरा जी की बात पर- उसी पार्टी के नेता जाति जनगणना करवाने के लिए हर सीमा पार किए हुए हैं। यह भी अजीब संयोग है कि जिन राज्यों- कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, वे ही जातिगत जनगणना नहीं करवा पाई। दूसरे, वे सरकारें कब तक हैं या दोबारा इनमें से किसमें फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी, कहा नहीं जा सकता। आज की भाजपा पहले वाली जनसंघ नहीं है। 11 साल से प्रधानमंत्री पद पर कायम नेता नरेंद्र मोदी ओबीसी बिरादरी से आते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद से लेकर भाजपा की राज्य सरकारों में बड़ी तादाद में पिछड़ी कही जाने वाली जातियों के मंत्री हैं। इतना ही नहीं, यह तीन बार लोकसभा चुनाव और अनेक राज्यों के चुनाव में साबित हो चुका है कि बड़ी तादाद में ओबीसी वोट भाजपा को मिलता है। दलित वोट भी हर राज्य में भाजपा को ही सर्वाधिक मिलता रहा है, केवल 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष के भाजपा के चार सौ सीटें आने पर आरक्षण खत्म करने के बेबुनियाद प्रचार ने भाजपा को नुकसान जरूर पहुंचाया। तब भी भाजपा की अगुवाई में लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार बनी। यह समझ से परे है कि सुप्रीम कोर्ट ने पचास फीसदी से ज्यादा आरक्षण की सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया है, ऐसे में जाति जनगणना करा कर कांग्रेस पार्टी क्या करेगी। क्या केवल जनगणना कराने से पिछड़ों का वोट मिल जाएगा। देश की आबादी में 56 फीसदी आबादी युवाओं की है। कांग्रेस में इस पर बहस नहीं चल रही है कि वह कितने युवाओं को जोड़ पाई है। जो माहौल दिख रहा है, उसमें नरेंद्र मोदी के रहते भाजपा समर्थक मतों में सेंध लगाना किसी के वश में नहीं है। अगर ऐसा होता तो 2024 के लोकसभा चुनाव में पिछली बार से कम सीटें पाने बावजूद भाजपा हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली विधानसभा का चुनाव भाजपा नहीं जीत पाती। अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि जो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए पार्टी में जगह नहीं है।

मुर्शिदाबाद में पलायन को मजबूर कानून का शासन

मुर्शिदाबाद में नए वक्फ कानून का संवैधानिक तरीके से विरोध का बहाना करते हुए हिंदुओं को चुन-चुनकर निशाना बनाने वाली हिंसक भीड़ के उत्पात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इसमें हिंसा की जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन करने और ममता सरकार की जवाबदेही तय करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, पता नहीं, लेकिन यह पता है कि जब मई 2021 में बंगाल में विधानसभा चुनाव बाद भीषण हिंसा की जांच के लिए ऐसी ही एक याचिका दायर की गई थी तो उसकी तत्काल सुनवाई नहीं हो पाई थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जिस दो सदस्यीय पीठ को इस याचिका की सुनवाई करनी थी, उसकी एक जज इंदिरा बनर्जी मामला सुनने से पीछे हट गई थीं। वह बंगाल से ही थीं। तब तृणमूल कांग्रेस समर्थकों की भीषण अराजकता के चलते बंगाल से कई लोग जान बचाकर असम में शरण लेने को मजबूर हुए थे। उन्हें महीनों तक वहीं रहना पड़ा था। कहना कठिन है कि वे सब अपने घरों को लौट पाए थे या नहीं। यह कहना तो और भी कठिन है कि मुर्शिदाबाद हिंसा के जो पीड़ित जान बचाने के लिए मालदा और अन्यत्र शरण लेने को मजबूर हुए हैं, वे अपने घरों को लौट सकेंगे या नहीं। यह कहना इसलिए अधिक कठिन है, क्योंकि एक तो खुद पलायन करने वाले अपनी वापसी को लेकर सुनिश्चित नहीं और दूसरे, तृणमूल कांग्रेस के नेता यह समझाने में लगे हुए हैं कि हिंसाग्रस्त इलाकों में सब ठीक है। कुछ तो मुर्शिदाबाद की अराजकता को सीमा सुरक्षा बल की साजिश बता रहे हैं। यह तो गनीमत रही कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बलों की तैनाती के आदेश दिए, अन्यथा वहां कुछ इलाके हिंदुओं से विहीन भी हो सकते थे। मुर्शिदाबाद बांग्लादेश से सटा वह जिला है, जहां हिंदू आबादी घटते-घटते 33 प्रतिशत रह गई है। अगली जनगणना में वह और घट जाए तो हैरानी नहीं। इसलिए और नहीं, क्योंकि आबादी के असंतुलन के मामले में बंगाल के कुछ इलाके बांग्लादेश की राह पर हैं। स्थिति तब तक नहीं बदलेगी, जब तक पीड़ित लोग आत्मरक्षा के लिए सक्रिय नहीं होते और अन्याय के प्रतिरोध के लिए खुद को सक्षम नहीं बनाते। अपना अस्तित्व बचाने के लिए उन्हें ऐसा करना ही होगा, क्योंकि मुर्शिदाबाद सरीखी आतंक भरी अराजकता में सुरक्षा बल जब तक दखल देते हैं, तब तक नुकसान हो चुका होता है और अक्सर वह स्थायी होता है। लोग अपने ही देश में शरणार्थी बन जाते हैं। कश्मीर घाटी से भगाए गए कश्मीरी हिंदू आज तक अपने घरों को नहीं लौट सके हैं। मुर्शिदाबाद की हिंसा के दौरान पुलिस जिस तरह मूकदर्शक बनी रही, वह कोई नई बात नहीं। वैसे तो हर राज्य की पुलिस वहां की सरकार के दबाव-प्रभाव में ही काम करती है, लेकिन बंगाल पुलिस ने खुद को एक तरह से तृणमूल की शाखा में तब्दील कर लिया है। वहां के डीजीपी वही राजीव कुमार हैं, जिनके घर जब सीबीआई ने सारदा घोटाले की जांच में हेराफेरी करने के आरोप में छापा डाला था तो ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई थीं। लोकसभा चुनाव के समय चुनाव आयोग ने उन्हें डीजीपी पद से हटा दिया था, पर चुनाव निपटते ही ममता ने उन्हें बहाल कर दिया। मुर्शिदाबाद में नए वक्फ कानून का विरोध कथित तौर पर वक्फ की जमीन बचाने के लिए किया गया, लेकिन वह दूसरों को उनकी जमीन से बेदखल करने में तब्दील हो गया। साफ है कि वक्फ कानून का विरोध अराजकता फैलाने का बहाना ही था। मुर्शिदाबाद इसका शर्मनाक उदाहरण है कि भारत का शासन तंत्र किस तरह भारत भूमि में ही घुटने टेकने को मजबूर हो जाता है। आखिर ऐसा असहाय-निरुपाय शासन तंत्र अपनी जान बचाकर भागे लोगों को फिर से अपने घरों को लौटने का साहस और संबल कैसे दे सकता है। बंगाल में कानून का शासन नहीं, बल्कि वहां शासन करने वालों का कानून है, यह निष्कर्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का था, जिसने 2021 के विधानसभा चुनाव बाद हुई हिंसा की छानबीन की थी। मुर्शिदाबाद की हिंसा इसकी पुष्टि करती है कि बंगाल में आज भी कानून का शासन नहीं है। वक्फ कानून विरोधियों का दुस्साहस किस तरह बढ़ा हुआ है, इसे इससे समझा जा सकता है कि वे राज्य के अन्य हिस्सों में भी उपद्रव कर रहे हैं और इस दौरान पुलिस को भी निशाना बना रहे हैं। यदि सुप्रीम कोर्ट बंगाल में दखल नहीं देता नहीं तो वक्फ कानून विरोधियों ने जैसा उत्पात मुर्शिदाबाद में मचाया, वैसा ही देश के दूसरे हिस्सों में देखने को मिल सकता है। इसकी अनदेखी न की जाए कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में आगजनी और तोड़फोड़ का सिलसिला सबसे पहले बंगाल से ही शुरू हुआ था। फिर ऐसा ही देश के दूसरे हिस्सों में भी देखने को मिला था। पता नहीं केंद्र सरकार बंगाल में किस तरह हस्तक्षेप कर सकती है, लेकिन कम से कम इतना तो हो ही सकता है कि प्रधानमंत्री मुर्शिदाबाद से जान बचाकर मालदा में शरणार्थी बन गए लोगों से मिलने जाएं। यदि गुजरात दंगों के पीड़ितों से मिलने अटल बिहारी वाजपेयी जा सकते हैं और मुजफ्फरनगर दंगा पीडितों के आंसू पोछने मनमोहन सिंह तो मुर्शिदाबाद की भयावह हिंसा के शिकार लोगों से मिलने प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं जा सकते। यह ध्यान रहे कि मुर्शिदाबाद की हिंसा दंगा नहीं है। यह अगस्त 1946 की डायरेक्ट एक्शन डे की याद दिलाने वाली बर्बरता है।

Social Media Corner

सच के हक में...

आज जब मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष पद का दायित्व संभाल रहा हूँ, तो मेरे मन में अनेक भावनाएं उमड़ रही हैं। यह कोई साधारण पद नहीं, बल्कि झारखंड की जनता के सपनों, संघर्षों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व है। आदरणीय बाबा, हमारे संरक्षक आदरणीय शिबू सोरेन जी ने जिन विचारधाराओं छांव तले झामुमो की नींव रखी थी, आज उसे आगे बढ़ाने का अवसर मिलना मेरे लिए गर्व का क्षण है। मैं विनम्रतापूर्वक इस जिम्मेदारी को स्वीकार करता हूँ और प्रण लेता हूं कि झारखंड के हर गांव, हर गरीब, हर वंचित और हर युवा की आवाज बनूंगा। हमारी पार्टी का इतिहास संघर्षों से भरा है, लेकिन हमारा संकल्प अडिग है। आज फिर से हमें एकजुट होकर झारखंड की अस्मिता, विकास और न्याय के लिए संघर्ष करना है। मैं सभी कार्यकर्ताओं, नेताओं और झारखंडवासियों से वादा करता हूं, आपका विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगा।

(सीएम हेमंत सोरेन का 'एक्स' पर पोस्ट)

नेशनल हेराल्ड घोटाले में जमानत पर बाहर राहुल गांधी और सोनिया गांधी को यह भ्रम नहीं पालना चाहिए कि अब वो धरना प्रदर्शन और केंद्र सरकार पर दबाव डालने का प्रयास कर अपने पापों को छुपा लेगी। झारखंड में हेमंत सोरेन भी भाड़े की भीड़ इकट्ठा करने और ईडी अधिकारियों पर फजी मुकदमें दायर कर जमीन घोटालों की जांच प्रभावित करने का विफल प्रयास कर चुके हैं।

(बाबूलाल मरांडी का 'एक्स' पर पोस्ट)

गांवों में आज भी मजबूत है सामाजिक रिश्तों की डोर

नाबार्ड की इस साल मार्च में जारी रिपोर्ट से जहां संतोष होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थागत ऋण प्रवाह का दायरा बढ़ा है, वहीं यह चिंता की बात है कि जरूरत के समय गैर संस्थागत स्त्रोतों से कर्ज लेने वाले ग्रामीणों में करीब साढ़े सात फीसद लोगों को 50 फीसद से भी अधिक ब्याज दर से कर्ज चुकाना पड़ रहा है। इससे साफ है कि एक बार गैर संस्थागत स्त्रोत से कर्जदार बने तो फिर कर्ज के मकड़जाल से निकलना असंभव नहीं तो बहुत मुश्किल जरूर है। नाबार्ड की रिपोर्ट को आधार मानकर चलें तो पिछले साल सितंबर में जुटाए गए आंकड़ों के अनुसार, 17.6 फीसद लोग अपनी तात्कालिक आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए गैर संस्थागत स्त्रोतों पर निर्भर हैं। हालांकि इसमें करीब साढ़े तीन फीसद का सुधार है। पहले 21.1 प्रतिशत ग्रामीण अपनी ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए गैर संस्थागत स्त्रोतों पर निर्भर थे। हमारी ग्रामीण संस्कृति की इस खूबी की सराहना करनी पड़ेगी कि आज भी 31.7 प्रतिशत रिश्तेदार या परिचित ऐसे हैं, जो दुख-दर्द में भागीदार बनते हैं और ऐसे समय में उपलब्ध कराए गए धन पर किसी तरह का ब्याज नहीं लेते। रिश्तेदारों या परिचितों से इस तरह की धन की आवश्यकता कुछ समय के लिए ही होती है और समय पर लौटा दिया जाता है। यह तथ्य भी नाबार्ड द्वारा जारी रिपोर्ट से ही उभर कर आया है। चाहे ग्रामीण हों या शहरी ऐसी आवश्यकताएं आ ही जाती हैं, जिनके लिए तत्काल धन की जरूरत होती है। अन्य कोई सहारा नहीं देखकर व्यक्ति इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रिश्तेदार, परिचित, साहूकार, दोस्त, कमीशन एजेंट या रुपये उधार देने वाले लोगों के सामने हाथ पसारते हैं। अब इनमें से बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है, जो व्यक्ति की मजबूरी का फायदा उठाने में किसी तरह का गुरेज नहीं करते और मजबूरी का फायदा उठाते हुए 50 से 60 प्रतिशत तक ब्याज लेने में भी हिचकिचाहट नहीं दिखाते। रिपोर्ट के अनुसार, ऋण लेने वाले करीब 40 फीसद ग्रामीणों को 15 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक का ब्याज देना पड़ता है। 0.9 प्रतिशत को 60 प्रतिशत या 6.6 फीसदी को 50 प्रतिशत से अधिक की ब्याज दर पर ऋण को चुकाना पड़ता है। साफ है कि आजादी के 75 साल बाद भी सूदखोरों का बोलबाला बना हुआ है। संस्थागत ऋणों में भी यदि हम पर्सनल लोन की बात करें तो वह भी करीब 15 से 20 प्रतिशत पर बैठता है और यदि किसी कारण से कोई किस्त बकाया रह गई तो पेनल्टी-दर-पेनल्टी का सिलसिला काफी गंभीर व कर्ज के मकड़जाल में फंसाने वाला हो जाता है। एक बात और, शहरों और ग्रामीण इलाकों में कुछ लोगों या संस्थाओं द्वारा दैनिक आधार पर पैसा कलेक्शन करने और दैनिक आधार पर ऋण देने का कार्य किया जाता है। इस तरह के लोगों या संस्थाओं द्वारा भले दैनिक आधार पर दस रुपये के ग्यारह रुपये शाम को देना आसान लगता हो, पर इस किस्त का चूकना और मासिक आधार पर गणना की जाए तो यह बहुत मंहगा होने के साथ जरूरतमंद लोगों की मजबूरी का फायदा उठाने से कम नहीं है। रोजमर्रा का काम करने वाले वेंडर्स इस तरह की श्रेणी में आते हैं। कहने को चाहे 40 प्रतिशत ही हो, पर इनके द्वारा 20 प्रतिशत से 60 प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज राशि वसूलना किसी भी तरह से सभ्य समाज के लिए उचित नहीं कहा जा सकता। देश में संस्थागत ऋण उपलब्धता बढ़ी है, पर ताजा रिपोर्ट के अनुसार, 17.6 प्रतिशत ग्रामीणों का साहूकारों या अन्य स्त्रोतों पर निर्भर रहना उचित नहीं माना जा सकता। यदि ब्याज दर 20, 30, 40 या 50 प्रतिशत होगी तो प्रेमचंद के गोदान या इसी तरह की साहूकारी व्यवस्था व आज की व्यवस्था में क्या अंतर रह जाएगा। इतना जरूर है कि रिश्तों की डोर आज भी मजबूत है और इसकी पुष्टि नाबार्ड की रिपोर्ट करती है कि ग्रामीण क्षेत्र में 31.7 प्रतिशत कर्जदार रिश्तेदारों और परिचितों पर निर्भर हैं। ये लोग रिश्तों का लिहाज करते हुए जरूरत के समय एक-दूसरे का आर्थिक सहयोग करते हैं और बदले में किसी तरह का ब्याज नहीं लेते।

निशाने से चूकना

भारत के औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर फरवरी में छह महीने के निचले स्तर 2.9 फीसद पर आ गई, जो जनवरी के 5.2 फीसद (संशोधित अनुमान) की वृद्धि दर से कम तथा पिछले फरवरी के 5.6 फीसद की वृद्धि दर से लगभग आधी रह गई है। सिवा बिजली उत्पादन में 3.6 फीसद की मामूली वृद्धि के, जो जनवरी के 3.4 फीसद की वृद्धि से तो ज्यादा है, लेकिन पिछले फरवरी के 7.6 फीसद की वृद्धि के आधे से भी कम है, यह गिरावट व्यापक है। इस फरवरी में वृद्धि दर में सबसे ज्यादा गिरावट खनन क्षेत्र में देखी गई, जो पिछले साल के 8.1 फीसद के मुकाबले 1.6 फीसद रह गई, जबकि मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र में वृद्धि दर पिछले साल के 4.9 फीसदी से लगभग आधी गिरकर 2.9 फीसदी रह गई। उपयोग आधारित वर्गीकरण के आधार पर उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के उत्पादन की वृद्धि दर में भारी गिरावट आई है और यह पिछले फरवरी के 12.6 फीसद से अब घटकर 3.8 फीसद रह गई है। साथ ही उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुओं के उत्पादन में लगातार तीसरे महीने गिरावट आई है और यह गिरावट 2.1 फीसद की है (जनवरी में 3.2 फीसद की गिरावट आई थी)। यह समग्र उपभोग मांग में उल्लेखनीय गिरावट को दशार्ता है। ऐसा खुदरा मुद्रास्फीति में तेज गिरावट के बावजूद हुआ है, जोकि एक साल पहले के 5.09 फीसद से घटकर फरवरी में 3.61 फीसदी रह गई है तथा खाद्य मुद्रास्फीति दर भी 3.75 फीसद रही, जो दो सालों में सबसे कम है। इससे यह लगभग तय हो गया है कि महाकुंभ की वजह से उपभोग में वृद्धि की सरकार की इच्छा पूरी नहीं हुई है, जिससे 2025 के वित्तीय वर्ष के दौरान जीडीपी में 6.5 फीसद की विकास दर के केंद्र के लक्ष्य के पूरा नहीं होने की आशंका है। फरवरी के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के आंकड़े एसएंडपी द्वारा किए गए मैन्यूफैक्चरिंग क्रय प्रबंधक सूचकांक सर्वेक्षण के 14 महीने के निचले स्तर 56.3 से मेल खाते हैं। इससे दो बातें उजागर होती हैं- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कदमों के बाद अभूतपूर्व वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता का सामना कर रहे निमार्ताओं की घबराहट और उपभोक्ताओं में रुचि की कमी।

Printed and Published by Fahim Akhtar on behalf of MAA MEDIA VENTURE and Printed at SHIVA SAI PUBLICATION PVT.LTD, Ratu, Kathitand, Near Tender Bagicha, H.P. Petrol Pump P.O.+P.S.- Ratu, Dist.-Ranchi, 835222, Jharkhand And Published at Roshpa Tower, 5th Floor, Main Road, Ranchi, Jharkhand-834001. R.N.I Number - JHABIL/2022/85899, Editor- Fahim Akhtar. Mob - 9431311669, E-mail : thephotonnewsjharkhand@gmail.com

India, Lanka no longer confined by bounds of bilateralism

Sri Lanka's aid of $1 million to earthquake-hit and impoverished Myanmar is the best news in a while that has come from India's neighbourhood, which is once again in ferment for the most part.

The relief cheque, which was handed over at the Presidential Secretariat in Colombo to Myanmar's Ambassador to Sri Lanka, is all the more laudable because the island nation is itself going through a long process of economic recovery, helped by India, among other countries, and multilateral financial institutions.Sri Lanka breaking the norm by its entrenched domestic elite, represented in the presidential election just over six months ago, is reflected in its aid to strife-torn Myanmar, additionally hit now by a devastating natural disaster.New and imaginative approaches by the new President Dissanayake were also evident during Prime Minister Narendra Modi's visit to Sri Lanka from April 4 to 6.India-Sri Lanka relations are moving beyond the limits of bilateralism. A Memorandum of Understanding (MoU) inked between the two countries, also bringing the United Arab Emirates (UAE) into its ambit, is the first step towards trilateral initiatives on the island at the level of the three governments. This MoU envisages developing Trincomalee as Sri Lanka's energy hub, eventually exporting power.

The UAE's private sector, which is closely aligned to its federated ruling structures, has long been keen on working with India in increasing its presence in Sri Lanka. The UAE's biggest investment was in Air Lanka in 1998, when Emirates airline purchased 43 per cent of the former's ownership. Sri Lanka's long-running ethnic conflict, however, eventually caused Emirates to divest. Private investors also pulled out of Sri Lanka. With peace returning to the island, the UAE wants to pick up the threads of its lost presence there. The trilateral MoU during Modi's visit marks a new beginning.

Manifest in seven other MoUs signed during Modi's visit were the same sensibilities which prompted Dissanayake to send relief aid to Myanmar. These MoUs were mostly drawn up with those at the bottom of Sri Lanka's social pyramid in mind. Goodbye to giant projects, ones like the Maho-Omanthai rail line inaugurated during Modi's trip.

Six months before Dissanayake won the presidential election, India proactively invited him on a six-day visit hosted by the Indian Council for Cultural Relations (ICCR) as its Distinguished Fellow. Kerala, ruled by Marxist comrades of Dissanayake's Janatha Vimukthi Peramuna (JVP), was one of the states included in his ICCR itinerary.In Thiruvananthapuram, the presidential hopeful was impressed by Kerala's government-run Technopark, which he visited. Dissanayake said immediately afterwards that he wanted Sri Lanka to adopt the "immaculate IT ecosystem in Kerala," the island's close neighbour.

One of the MoUs inked during Modi's visit was for "sharing successful digital solutions implemented at population scale for digital transformation". When this MoU is implemented, it is expected that Kerala's mass digital transformation will be emulated on the other side of the Palk Strait.

Another MoU on defence cooperation, the first of its kind, marked the culmination of Modi-Dissanayake talks since the President's December visit to India, when there was recognition that national security of both the countries was closely interlinked.The neighbourhood's importance in India's external affairs resurfaced because most of this country's backyard is now in various degrees of crisis. This transformed Modi's bilateral meetings with four leaders from neighbouring countries into much more than routine courtesy exchanges.There was much internal debate at Raisina Hill, the seat of power in the National Capital, on whether Modi should meet Muhammad Yunus, Chief Adviser of the interim government of Bangladesh, on the sidelines of a plurilateral summit in Bangkok or give him the cold shoulder.

Nostalgia, protest & beyond in Punjab's visual arts

Even though artists have moved to urban settings, their creativity flows from their memories of rural Punjab.

An exhibition on contemporary visual arts that concluded in Chandigarh on March 17 proved quite extraordinary and revealing. Called 'Contemplation: A Journey Within', the exhibition was organised by the Punjab Lalit Kala Akademi. It brought together six, mostly young, artists from Punjab: painters (Gurpreet Singh and Jaspreet Singh), sculptors (Narinder Singh and Parvesh Kumar) and printmakers and mix media artists (Ravinder Singh and Anita Kaur).While the quality and maturity of their work took many by surprise, it is quite another aspect of this exhibition which I wish to bring to the fore. What did these works reflect in socio-cultural terms? What could one see in them as a student of social sciences and cultural studies?One thing struck me immediately: The artists might have been picked up on the basis of individual merit alone, but they shared a lot in common, and put together, they seemed to complement one another. For one thing, they commonly affirmed that they are "deeply rooted" in their social and cultural background of rural Punjab. Even though they might have later moved to urban settings, their creativity flows from their memories of rural Punjab. That is where their motifs come from and appear as visual metaphors in their works. These are memories of a well-integrated agrarian community settled in a calm, rhythmic and idyllic cycle of life.These artists realise that things have changed, that the flow of life has been disrupted by winds of change. Green farmlands have been taken over by highways, factories, modern residential colonies consisting of high-rise flats.Individualism, competition and consumerism have shattered community solidarity. Pride in glorious traditions has been replaced by anomie and alienation. The love of motherland has been replaced by a mad urge to migrate abroad by hook or crook.Economists and sociologists will give you nth number of reasons and factors responsible for this drastic shift of the social and moral-cultural compass. Artists, however, are intuitive rather than analytical. Their responses are more immediate, emotive and intimate.

Three kinds of responses are evident from the works of these artists. First, there was an attempt at imaginative re-creation of the past and imaginary re-living of life in thaimagined past. There were roses, birds, nests, mud houses and traditional milch cattle. There were young lovers; there was the recurring theme of women doing embroidery. In other words, what has been lost in real life was recaptured in art. Art is not a mirror of life but a parallel dream.The second response was of lamentation and protest. There was depiction of empty lives of isolated individuals. Denuded of their human essence by needs and desires, they appeared as mere outlines. Or they appeared as splintered individuals where one side is of a nurturing mother, while the other shadowy side is of a menacing, consumerist figure. These artists seemed to create not merely aesthetic objects but works that provoked thought and protest.The third response could appear as exit and escape. More neutrally, it is an effort at cutting loose and walking away to examine other avenues of anchorage. This could take the form of an essentialist faith in the inherent goodness of life despite all changes and disruptions. Much of this is explained in terms of 'ups and downs' of life. Another form is of humanist universalism or existentialist philosophical belief that our identities are not destined to be imprisoned by our immediate geographic and cultural boundaries. Instead, our identities are shaped by our free choices.

While all these three kinds of responses were clearly visible to me in the works of these artists, what was equally visible was a certain unease with the dissonance the diversity of these responses created. As a result, some of these artists seemed to have chosen some kind of a 'middle path'. They spoke of 'narrowing the gap' or 'building a bridge' between the past and the present by fusing tradition with modernity. It is a moot question as to how exactly they did so, or how successful they were in doing so.Historically, Punjab has been considered to be a land of robust, hardworking and courageous people. But what is also historically true is that Punjab has remained a land of invasions, violence and looting. It has been a land of 'clash of civilisations'. Punjab has seen more social-cultural ruptures than perhaps any other part of the country.In modern history, Punjab has seen disruptions caused by the Partition in 1947 and the reorganisation in 1966. It has been a witness to violence during the Partition, the Naxal movement and the era of Sikh militancy. Then, there has been the lethal effect of the agrarian crisis in the form of income stagnation, rising debts, farmer suicides and ecological devastation.

Punjab's memory of these disruptions is complex and layered. There are those among us who have seen all the above mentioned. That generation is fast dwindling.

Tt hen there is the generation of 'senior citizens', born in the post-Partition years but witness to every other eventful turning of the wheel. Then, there is the youngest generation, to which most of these artists belong to. They may not have seen the violence, but they have heard about it from their elders in the family.Moreover, they are the only generation that has been born and brought up during a period of agrarian crisis. The 'green revolution' has faded, and the post-agrarian future is uncertain and directionless.If we accept that the art of each age is informed by its own present, then we should also accept that the art of periods that lie in between definable ages, is informed by the transitory character of its time. Could it be that, many years from now, these young artists would be remembered for depicting with remarkable empathy and density, the fickleness of our present?

Tussle over Ambedkar

One-upmanship does a disservice to his legacy

The 135th birth anniversary of Dr BR Ambedkar presented an opportunity to political parties to rise above their differences and reaffirm their allegiance to the Constitution, but they preferred to indulge in their trademark sport — one-upmanship. In his address after flagging off the Hisar-Ayodhya flight, Prime Minister Narendra Modi accused the Congress of betraying Ambedkar by turning Scheduled Castes, Scheduled Tribes and OBCs into "second-class citizens" while in power. Ironically, his allegation that the Congress is destroying the Constitution comes at a time when a law enacted by his own government, the Waqf (Amendment) Act, has been challenged in the Supreme Court and dubbed "unconstitutional" by Opposition parties.The grand old party was quick to hit back, saying that the Modi government was paying only lip service to Ambedkar's legacy and doing nothing to fulfil his wishes. Amid the unsavoury slanging match, the bottom line is that rival parties are vying to project themselves as the sole custodian of the Constitution as well as Ambedkar's vision of social and economic justice. However, vote bank politics continues to be their driving force. Caste, class and communal schisms persist because political leaders want it that way for the sake of electoral gais.Key stakeholders such as the executive, the legislature and the judiciary must ask themselves why inequality and discrimination prevail even 75 years after India became a republic. Can a nation in which free speech, democracy and federalism are often under threat stand tall in the global arena? Devil-may-care comedian Kunal Kamra was bang on target when he flashed a pocket version of the Constitution and wrote, "The only way forward." Indeed, following the Constitution in letter and spirit would be the best tribute to its principal architect, Ambedkar. It would require collective efforts, not an unhealthy tussle to appropriate his enduring legacy.

Bay of Bengal is emerging as geopolitical flashpoint

Two US generals had visited Bangladesh when Yunus went to China.

Not all is well on India's eastern seaboard. At the time of PM Sheikh Hasina's upstaging in last August, the script seemed to have the US signature all over. This perception was strengthened by the parachuting of Muhammad Yunus as Chief Adviser of Bangladesh's interim government. Yunus had been earlier under US patronage for a few years.However, the setting up of this governance model was unconstitutional since a caretaker government in Bangladesh is supposed to be headed by a Supreme Court judge. But, it had the backing of the army. Further, Yunus flew down to DC with the 'student leader' who had led the agitation before the regime change. He was introduced to Bill Clinton and, possibly, Joe Biden, giving legitimacy to the belief that the US deep state had steered the drama.Yunus' actions and the statements from his advisers have been adversarial to India. Foreign Secretary Vikram Misri visited Dhaka recently and met Yunus and, probably, conveyed India's concerns.Recently, Yunus called on General Secretary Xi Jinping in Beijing. He also addressed a business forum, where he said: "Seven sisters of India are landlocked -- they have no way to reach the ocean. We are the only guardian of the ocean for all of this region…. From Bangladesh, you can go anywhere you want. The ocean is in our backyard. So, this is the opportunity that you want to take."Either the Adviser is geopolitically naïve or he hasn't looked at the map. With a 580-km coastline, he considers Bangladesh to be the "guardian of the ocean for all of this region." On the east coast alone, India has a coastline of approximately 6,100 km and along with Andaman and Nicobar Islands, it is around 7,516 km.The size of the country, its trade, the combat naval arsenal, including two (soon to be three) Sub-Surface Ballistic Nuclear (SSBN) submarines, all in the east coast, speak for themselves. Clearly, his imagination that Bangladesh is the "guardian of the ocean" is misplaced.The armed forces of the two countries, particularly the navies, hold regular exercises, a

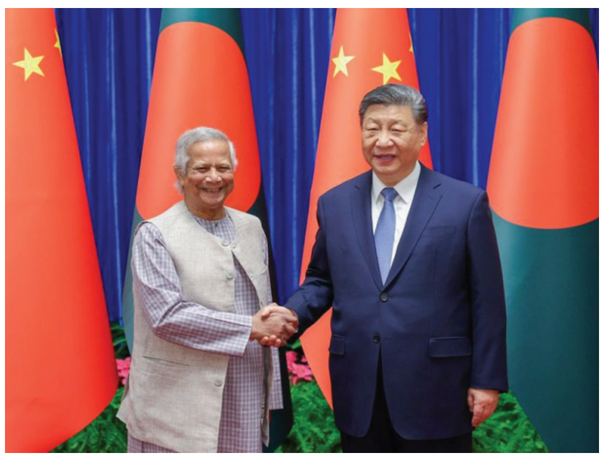

large number of personnel are trained in India and enjoy very cordial relations.Yunus must be naïve to invite Chinese businessmen, knowing well that the US would not expect this from its proxy. Incidentally, two US generals were visiting Bangladesh when the Adviser travelled to China. Also, soon after his return, the army chief, General Waker-Uz-Zaman, visited Beijing.Before her upstaging, Hasina had stated that the US was keen to use St Martin Island, located 9 km from the Cox's Bazar-Teknaf peninsula, but she had declined the request. St Martin is just about 8 km from the Myanmar coast, making it rather strategic.The US has been monitoring the worsening situation in Myanmar as also the growing influence of China in Bangladesh and Myanmar.The Bay of Bengal is the only section of the Indian Ocean where the US does not have a physical presence. The Biden administration had earmarked $167 million for Myanmar, including $75 million for cross-border aid, of which $25 million was for non-lethal support to ethnic armed organisations.China has been supporting both the military junta in Myanmar and several armed groups primarily to protect its port operations in Kyaukphyu, where oil from the Gulf is discharged and taken through pipelines to the Kunming refinery. This can be an alternative to the Malacca route, which exposes it to threats in times of tension with the US. China also supports some rebel groups near its border with Myanmar to not disturb the supply route. It developed Kyaukphyu port, which is used to offload Saudi and Iranian crude and taken to Kunming.To maintain the balance of power between the two friends (China and India), the Myanmar government awarded the development and operational contract of the Sittwe port to India's IPGL. It is key to the Kaladan Multimodal Transit Transport Project. This is also an alternative route to the Northeastern states, bypassing Bangladesh.It will open the possibility of connecting the NE states with Thailand, Laos, Cambodia and Vietnam, opening into the Pacific (South China Sea).China has many stakes in Bangladesh's infrastructure as well as weapon platforms for its armed forces. It has 11 projects in hand. It is also Bangladesh's top import partner. Bangladesh is also part of the BRI. All said, the Chinese projects provide 55,000 jobs to Bangladeshis. There were reports of discussion for PLAN ships to operate regularly from Bangladesh ports. This was declined by the Hasina government to avoid the Bay of Bengal becoming the new ocean of geopolitical contestation.The US, too, has been active in this area, given China's influence of the PRC and its stakes in both Myanmar and Bangladesh. And now, the Arakan army has gained control of Rakhine state and the border with Bangladesh, except the ports of Sittwe and Kyaukpyu. Rohingyas in Rakhine are facing the Arakan army's onslaught and alleged human rights violation.President Trump has suspended USAID, which was being used for basic food and medical care for thousands of Burmese refugees in Bangladesh, India and Thailand, raising the risk of malnutrition and death.Yunus has reportedly agreed to invite China for the development of Mongla port (the operation of which was awarded to India by the Sheikh Hasina government). Yunus has also reportedly invited Pakistan to build an airbase at Lalmonirhat, near Chicken's Neck. Both these could have adverse geopolitical consequences for Bangladesh.The narrow portion of Bangladesh just below Chicken's Neck is vulnerable to action by the Indian armed forces. There is a threat of retaliation from these new developments. Also, down south, the Arakan army has been giving hot pursuit to Rohingyas, right up to the Chittagong Hill Tracts. This narrow portion of Bangladesh has borders with Tripura, where ethnic Arakans are known to operate.

SEBI bans Gensol Engg, promoters from securities market in fund diversion case

New Delhi. Capital markets regulator SEBI on Tuesday barred Gensol Engineering and promoters — Anmol Singh Jaggi and Puneet Singh Jaggi — from the securities markets till further orders in a fund diversion and governance lapses case.

The regulator has also debarred Anmol and Puneet Singh Jaggi from holding the position of a director or key managerial personnel in Gensol until further orders.Further, the markets watchdog directed Gensol Engineering Ltd (GEL) to put on hold the stock split announced by it.The order came after the Securities and Exchange Board of India (SEBI) received a complaint in June 2024 relating to the manipulation of share price and diversion of funds from GEL and thereafter started examining the matter.

"The company has attempted to mislead SEBI, the CRAs (credit rating agencies), the lenders and the investors by submitting forged conduct letters purportedly issued by its lenders," the regulator said.The noticees 1, 2 and 3 (GEL, Anmol and Puneet Singh Jaggi) are alleged to have violated the provisions of PFUTP (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices) rules, it added.

SEBI noted that the promoters were running a listed public company as if it were a propriety firm. GEL's funds were routed to related parties and used for unconnected expenses as if the company's funds were promoters' piggy banks.The result of these transactions would mean that the diversions at some time need to be written off from Gensol's books, ultimately resulting in losses to the investors of the company.

"…prima facie evidence of a blatant violation of rules of corporate governance is writ large over the workings of the company. The diversion of funds of the company (GEL) by promoter entities reflects a culture of weak internal control, where even ring-fenced borrowings from institutional creditors were rerouted at the total discretion of the promoters," SEBI's whole-time member Ashwani Bhatia said in the order.

Sensex, Nifty trade flat after 2-day tariff relief rally; Gensol shares tumble 5%

NEW DELHI. Benchmark stock market indices opened slightly lower on Wednesday after registering strong gains in the past two trading sessions.

The S&P BSE Sensex was down 84.98 points to 76,649.91 at 9:23 am, while the NSE Nifty50 fell 26.25 points to trade at 23,302.30. However, broader market indices did not see any major dip, and it is likely to provide relief to retail investors.Another reason that will make investors happy is the fact that volatility has dipped further on Dalal Street.Most of the Nifty sectoral indices were trading mixed. Some of the top gainers on the Nifty50 were Jio Financial Services, Apollo Hospitals, HDFC Life, Trent and Eicher Motors. On the other hand, the top losers were Maruti, Eternal, Sun Pharma, Bajaj-Auto and Tata Consumer Products.

Meanwhile, shares of Gensol Engineering tumbled 5% after the Securities and Exchange Board of India (Sebi) barred its promoters fordiverting company funds for personal use.On the broader market outlook, Prashanth Tapse, Senior VP (Research), Mehta Equities Ltd, "Markets could see a gap down opening amid fall in other Asian gauges following sluggish close of US indices in overnight trades. The street continues to remain focused on escalating tensions between the US and China, as the US Commerce Department opened an investigation into semiconductor and pharmaceutical imports—raising the prospect of further tariffs."

Exports hit record $820 bn amid global challenges in Fy25

New Delhi. Defying global headwinds and World Trade Organisation's bleak projections, India's exports surged to a record $820.93 billion in FY25, marking a 5.5% increase over the previous year's $778.13 billion, the Ministry of Commerce announced on Monday.

Merchandise exports edged up marginally to $437.42 billion from $437.07 billion in FY24. Merchandise imports rose 6% to $720 billion during the year. Non-petroleum exports stood out, rising by 6% to reach an all-time high of $374.08 billion, compared to $352.92 billion last year.Services exports led the charge with a sharp 12.45% year-on-year increase. The sector, often under the radar in public discussions on trade, contributed significantly to overall trade expansion. Key segments included telecommunications, IT and business services, travel, and financial services.

"This past year was quite difficult. So many things happened globally— geopolitical tensions, disruptions in sea routes, and recessions in several countries. Despite the WTO's very pessimistic projections for global trade, India has done extremely well. In fact, we've performed better than the global average," said Sunil Barthwal, commerce secretary.The US, UAE, Netherlands, UK, and Japan emerged as India's top export destinations, while China, Russia, and Gulf nations remained major import sources.Smartphone exports to the US rose from $4.7 billion to $7.4 billion, and to the UK from $0.2 billion to $1.5 billion. Gold imports bill of the country grew by 29% in FY25 to $58 billion despite lower shipments in volume. This is due to sharp increase in average price ($/kg) to $76,612 per kg in FY25 compared to $57,263 per kg in FY25. India marked new territory in agri-exports, sending green papaya for the first time to Dublin and London.

PwC shuts down operations in more than a dozen countries: Report

PwC shuts operations in 12 countries due to business challenges

Faces business losses, cuts ties with risky clients globally

Under scrutiny after recent scandals and global client exodus

New Delhi. PwC has shut down operations in more than a dozen countries that are deemed too small, risky or unprofitable, as the Big Four accounting firm aims to prevent repeats of scandals that have affected it, the Financial Times reorted on Wednesday.The decision was taken due to mounting differences with local partners, the FT said, citing people familiar with the matter.Local leaders at the firm said they lost over a third of their business in recent years after pressure from PwC's global executives to drop risky clients, according to the report.PwC has faced an exodus of clientele and layoffs since last year.

PwC declined to comment on the report to FT. PwC did not immediately respond to a Reuters request for comment outside business hours.

The accounting giant has cut ties with its Sub-Saharan Francophone Africa firms after a strategic review, the company said last month.China hit PwC's mainland China unit with a six-month suspension and a $62 million fine for audit failures related to property developer China Evergrande's 3333.HK $78 billion fraud.Last month, Britain's Financial Reporting Council fined PwC 4.5 million pounds ($5.96 million) in relation to the audit of Wyelands Bank for its 2019 financial year.The firm is working with Saudi Arabia and its sovereign wealth fund to mend relations after the kingdom suspended activities between the $925 billion fund's holding company and PwC.

Investment advisor warns against inflation: 'By 2030, you'll own less, pay more'

New Delhi. Are we losing wealth by mistake or is it a sign of an economic shift system that is quietly working against the average Indian household? By 2030, expect smaller food portions and bigger bills, warns investment advisor Abhijit Chokshi.He wrote on X, "What's Coming By 2030? Digital inflation: Hidden charges on UPI and subscription services. Home prices are sky-high. Renting becomes your only option. Food shrink: Smaller portions, higher bills. By 2030, you'll own less, pay more, and wonder where your life went."He added that salaries have gone up, but so have everyday costs. From Rs 10 Maggi to Rs 1 crore for a basic 1BHK, it's not that you're earning less, it's that your money is losing value quietly.He wrote, "Why your salary feels useless (even with a raise) from Rs 10 maggie to Rs 1 crore 1BHKs you're not earning less you're just being robbed silently. Is inflation only about economics, or is it about control?"People aren't necessarily earning less, they're just losing more without noticing. Inflation, once seen as an economic trend, may now be a silent force of control, he added.

Chokshi stated in his post that most people think inflation means things getting expensive. But he explains that inflation has two faces. One is visible inflation, which we all notice. For instance, milk going from Rs 60 to Rs 75, and petrol jumping from Rs 90 to Rs 105, while EMIs are becoming steeper.The other is invisible inflation, which is trickier. That's when prices stay the same, but you get less—fewer biscuits in the same packet, smaller portions in the same meal. This is called shrinkflation, and it quietly cuts your spending power without you even realising it, mentioned Chokshi.

WHAT'S REALLY CAUSING THIS ?

Chokshi in his post pointed to a few reasons, like central banks printing more money, which weakens the value of the currency, corporates cutting quality, not prices, along with global sanctions and oil prices, which impacts fuel costs and transport, which then increase the price of everything else.

He wrote, "You're busy blaming the sabziwala for the tomato price. But you don't ask why your savings aren't keeping up. What Causes It? Central banks are printing money, more rupees are chasing the same goods. Global politics: One oil sanction abroad, your fuel price at home spikes."

IREDA share price jumps 6% after strong Q4 results. All you need to know

New Delhi. Shares of Indian Renewable Energy Development Agency (IREDA) surged nearly 6% in early trade on Wednesday, buoyed by a strong set of Q4FY25 results that beat market expectations.

At 9:55 am, the stock was trading at Rs 177.05 on the Bombay Stock Exchange (BSE), up 5.95% from the previous close.The state-run renewable energy financier reported a 48.66% year-on-year jump in consolidated net profit for the March quarter, coming in at Rs 501.55 crore compared to Rs 337.39 crore in Q4FY24. Revenue from operations also rose 36.93% to Rs 1,905.06 crore from Rs 1,391.26 crore in the same period last year.That said, asset quality showed some signs of strain on a year-on-year basis. IREDA's net NPA ratio rose to 1.35% in Q4FY25, up from 0.99% in the same quarter last year. However,

there was a modest improvement sequentially, as net NPAs had stood at 1.5% in Q3FY25. The gross NPA ratio for the March quarter came in at 2.45%, reflecting pressure in some parts of the loan book despite the company's strong topline performance.Backing the strong Q4 performance is a 28% YoY growth in the company's loan book, which stood at Rs 76,250 crore at the end of FY25, ompared to Rs 59,698 crore a year earlier.Last month, the board approved a borrowing programme of up to Rs 30,800 crore for FY26. It also revised the borrowing limit for FY25, raising it by Rs 5,000 crore to Rs 29,200 crore.IREDA, a Navratna public sector enterprise under the Ministry of New and Renewable Energy, continues to play a key role in financing India's clean energy transition. The government currently holds a 75% stake in the company.With growing interest in renewable energy investments and a solid Q4 performance, the stock may remain in focus among investors looking at green energy plays with PSU backing.

As Trump considers auto tariffs pause, parts exemptions could be key for US industry

DETROIT. President Donald Trump hinted that he might temporarily relieve the auto industry from "permanent" tariffs he previously imposed on the business. The president didn't specify how long the potential pause would be or what it would entail, but the auto sector is awaiting how rules might change on 25% tariffs based on U.S. parts, if duties remain on assembled vehicles.Experts have said short pauses aren't likely to give carmakers enough of an opportunity to adjust their vast global supply chains, though parts exemptions would certainly bolster the industry amid Trump's trade war whiplash.

Trump told reporters Monday that automakers "need a little bit of time because they're going to make them here, but they need a little bit of time. So I'm talking about things like that," referring to relocating production from Canada, Mexico and elsewhere. The news drove global auto stocks up Tuesday.Matt Blunt, president of the American Automotive Policy Council, which represents domestic auto companies Ford, General Motors and Stellantis, said in a statement: "There is increasing awareness that broad tariffs

on parts could undermine our shared goal of building a thriving and growing American auto industry, and that many of these supply chain transitions will take time."Trump first announced 25% automotive tariffs late March; the tariffs for completed vehicles took effect on April 3, while the parts tariffs were set to start 30 days later.

"The one-month delay is intended to give the U.S. government time to work out rules to exempt the value of automotive parts that contains U.S.-made materials, which will not be subject to the tariffs," according to insights from law firm Foley & Lardner, noting a "carveout" for parts certified under regional trade pact, the U.S.-Mexico-Canada Agreement. The Department of Commerce is expected to determine "a system to calculate non-U.S. content" by May 3.At the same time, automakers are navigating steel and aluminum imports levies of at least 25%; 25% duties on all goods from Canada and Mexico; 10% global tariffs and reciprocal tariffs around the world — paused for 90 days, and both of which automotive is exempt from; and tariffs on China at 145%.Autos Drive America, which represents foreign automakers, said in a statement that "hitting pause on auto tariffs would be a step in the right direction and would allow automakers to deliver more choices at better prices for consumers."

How Gensol promoter used company funds to buy ultra-luxury DLF Camellias

DLF Camellias is a luxury housing project located in Sector 42, Gurgaon. It comprises 4 BHK, 5 BHK, and 6 BHK luxury apartments. Prices for these upscale homes begin at Rs 70 crore.

New Delhi. The DLF Camellias apartment, one of Gurgaon's and possibly India's most elite addresses, is now at the centre of a Sebi investigation that has exposed serious cracks in corporate governance at Gensol Engineering.The market regulator's interim order reveals that Anmol Singh Jaggi, one of Gensol's promoters, allegedly used company funds, including loans meant for electric vehicle purchases, to quietly finance a high-end apartment in the ultra-luxury project in Gurgaon.DLF Camellias is a luxury housing project located in Sector 42, Gurgaon. It features 429 high-end residences, available in 4 BHK, 5 BHK, and 6 BHK layouts. According to the official website, prices for these upscale homes begin at Rs 70 crore.

MONEY MEANT FOR EVs USED TO BUY LUXURY FLAT

Gensol had taken a loan of Rs 71.41 crore from the Indian Renewable Energy Development Agency (IREDA), and added another Rs 26 crore from its own account. This brought the total to nearly Rs 97 crore. A few days later, this money was sent to Go-Auto, a car dealer with links to the company and its promoters.

On the very same day, Go-Auto transferred Rs 50 crore to another entity, Capbridge Ventures, which is run by the Jaggi brothers who are promoters of Gensol. Capbridge Ventures then used Rs 42.94 crore to pay DLF towards the purchase of an apartment in The Camellias project.

Sebi said this was a clear case of fund diversion. The loans taken for EV leasing were being rerouted to a real estate deal by passing the money through related parties. The apartment, according to Sebi, was bought in the name of a firm where Anmol Singh Jaggi and his brother Puneet Singh Jaggi are both designated partners.

BOOKING ADVANCE ALSO LINKED TO GENSOL FUNDS

The chain of transactions did not end there. Sebi also found that Rs 5 crore was paid as an initial booking advance for the apartment by Jasminder Kaur, the mother of Anmol Singh Jaggi. This money, too, came from Gensol.Later, when DLF returned the advance amount to her, the money did not go back to Gensol. Instead, it was transferred to another related company, Matrix Gas and Renewables.

Sebi's investigation shows that there was no intention to return the company's money.In a written response to Sebi, DLF confirmed that a payment of Rs 42.94 crore was made on October 6, 2022, towards the purchase of an apartment. This apartment was originally booked in the name of Jasminder Kaur.

SEBI TAKES ACTION

After completing its investigation, Sebi has passed an interim order against Gensol Engineering and its promoters — Anmol Singh Jaggi and Puneet Singh Jaggi. The regulator has barred all three from trading in the capital markets until further notice.

It has also banned the two brothers from serving as directors or holding any senior roles at Gensol. In its order, Sebi said, "The promoters were running a listed public company as if it were a proprietary firm." The regulator added that there was a complete breakdown of internal financial checks and proper governance in the company.

BACKGROUND OF THE CASE

Sebi had started its investigation after getting complaints about Gensol. These included concerns over sharp movements in share prices and defaults in loan payments. During the probe, Sebi found that Gensol's promoters had moved large amounts of borrowed money through related companies and used it for personal gain.The misuse was not limited to the DLF apartment purchase. Sebi said there were several examples of fund diversion, which included fake documents, misreporting to credit agencies, and lack of financial discipline.

Delhi government's new air quality monitors face backlash over placement in low-pollution zones

NEW DELHI. air quality monitoring stations has drawn criticism from environmental activists, who allege that the strategic placement of these stations in green, low-density areas amounts to "greenwashing" the capital's pollution data.Environment Minister Manjinder Singh Sirsa recently announced that the new stations will be set up at Jawaharlal Nehru University (JNU), Indira Gandhi National Open University (IGNOU), Delhi Cantonment, Netaji Subhash University (West Campus), and the Commonwealth Games Sports Complex. At least two of these — JNU and IGNOU — lie within the South-Central Ridge, a designated forest area while the remaining stations are located in areas with relatively low pollution density

"The new monitors are being placed in areas with relatively low-density, green, and institutionally controlled environments. These are not areas grappling with the thick of Delhi's pollution crisis. Instead, they are among the city's better-performing pockets when it comes to air quality," said Bhavreen Kandhari, founder of Warrior Moms, a citizen-led collective advocating for clean air.

"It is understandable that some stations are placed in universities to facilitate research, but more and more are being installed in areas with better air quality, instead of industrial or high-density residential zones."Delhi currently has 40 air quality monitoring stations that feed data into the city's overall AQI calculations. However, many high-pollution zones — including dense residential and industrial areas — remain unmonitored. Several existing monitors are similarly located in low-exposure zones.

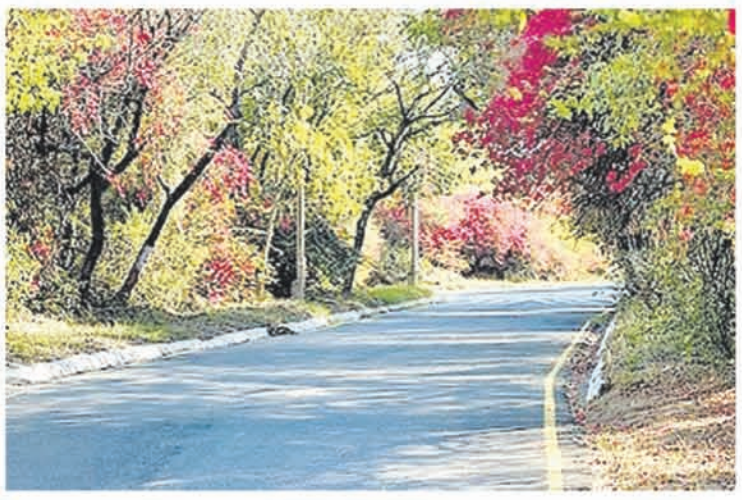

For instance, the station on Shri Aurobindo Marg is inside the National Institute of Tuberculosis and Respiratory Diseases within the Mehrauli forest range, despite being near congested localities like Lado Sarai and Saidulajaib. Others — like the Karni Singh Shooting Range (Asola Bhatti Forest) and Siri Fort (Hauz Khas Forest) — are also situated far from dense urban settlements.According to activist Varun Gulati, these stations have a radius of just 1 to 1.5 kilometres. "Many of these are located in areas where they will not be exposed to the most common pollutants like fumes from vehicles and dust from construction activities," he said.Kandhari also pointed out the high cost of these installations, "A single CAAQMS setup can cost upwards of Rs 1 crore in installation and operational expenses. These are taxpayer-funded investments that should be strategically deployed where they are most needed: high-density residential areas, congested intersections, industrial belts, and construction-heavy zones. These are the locations where residents, especially children and the elderly, suffer the worst health impacts due to sustained exposure to polluted air.".

Man claiming to be Mughal descendant seeks UN help to protect Aurangzeb's tomb

NEW DELHI.A man claiming to be a descendant of the last Mughal emperor, Bahadur Shah Zafar, has appealed to United Nations Secretary-General Antnio Guterres for the protection of Mughal emperor Aurangzeb's tomb in Maharashtra's Chhatrapati Sambhajinagar (formerly Aurangabad).Yakub Habeebuddin Tucy, who asserts that he is the caretaker of the Waqf property where the tomb is located, said that the grave has been declared a 'Monument of National Importance' and is protected under the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958.

In his letter, he raised concerns over growing hostility toward the site following recent unrest in Nagpur, news agency ANI reported.

The demand comes nearly a month after violence erupted in Nagpur during a rally which demanded the removal of Aurangzeb's Tomb."As per the provisions of the said Act, no unauthorised construction, alteration, destruction, or excavation can be undertaken at or near the protected monument, and any such activity would be deemed illegal and punishable under law," the letter to the UN Secretary-General read.

In the letter, he criticised what he called the distortion of historical facts in films, media, and social platforms, which he said has fueled public sentiment and led to hate campaigns and acts of symbolic aggression like effigy burning.He added that security personnel must be deployed to protect it.

He also underlined that international law imposes an obligation to "safeguard and conserve cultural heritage for the benefit of present and future generations."The letter cited India's signing of the UNESCO Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, 1972, and added, "Any act of destruction, neglect, or unlawful alteration of such monuments would amount to a violation of international obligations."

Rajasthan man held for Rs 19 lakh online Ponzi scam promising 28% monthly return in Delhi

NEW DELHI. A 31-year-old man from Rajasthan has been arrested for allegedly defrauding a couple by promising a 28% monthly return on their investment, police said on Tuesday.The accused, Vinod Kumar, hailing from Sri Ganganagar, ran an online Ponzi scheme named "Dollar Win Exchange."

According to police, in November 2024, the victim's wife came across video promoting high-return investment plans. After clicking a link, the couple joined a social media group and was lured to invest starting from Rs 1,000. Initially, they received small returns, but were later convinced to invest larger sums. Eventually, the payments stopped, and they realised they had been cheated of Rs 19 lakh.

"An investigation traced the defrauded amount to two bank accounts in Kumar's name. He was located in Sri Ganganagar through technical surveillance and arrested," DCP (central) M Harsha Vardhan said."Kumar, who previously worked in a cooperative society, used his experience in multi-level marketing to deceive people," the DCP added.

Congress workers rally outside ED offices across states over action on Gandhis

NEW DELHI. Hundreds of Congress workers and leaders converged outside the offices of the Enforcement Directorate (ED) across several states and held protests over the chargesheet filed against Sonia Gandhi and Rahul in the National Herald money laundering case. Central government offices at the district level also saw widespread demonstrations by Congress workers.

A massive agitation was held at the Congress's 24 Akbar Road party office in Delhi, with senior leaders like Sachin Pilot and Imran Pratapgarhi joining hundreds of workers in shouting slogans against the Centre and terming the action a "political vendetta".A huge contingent of police was deployed near the Congress office in Delhi and barricades were installed to prevent a law and order situation. Several workers were also detained.

"This is a politically motivated case. There is no transaction, transfer of property, asset transaction, there is no case. We will fight it out legally... Rahul Gandhi and Sonia Gandhi have been purposefully targeted. This has been done to suppress the voice of the opposition," senior leader Sachin Pilot said.

Rajya Sabha MP Imran Pratapgarhi said action was being taken after the Central Working Committee, the highest decision-making body of the Congress, met in Gujarat - the home state of Prime Minister Narendra Modi.In Mumbai, a poster was put outside the AJL House in Bandra demanding demolition of the property. The poster, which stated "Deva Bhau Bulldozer Chalao", carried pictures of Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis and his Uttar Pradesh counterpart Yogi Adityanath.

WHAT IS THE ED CASE?

The protests come as the ED filed a chargesheet against Sonia and Rahul before a special PMLA court in connection with its money laundering probe in the National Herald case.

In its chargesheet, the ED has alleged that the Gandhis and other accused acquired assets of Associated Journals Ltd (AJL), the publisher of the National Herald newspaper, at an undervalued rate of Rs 50 lakh, compared to the actual market value of assets worth Rs 2,000 crore.The AJL was founded by India's first prime minister, Jawaharlal Nehru. The assets were acquired by a "not-for-profit" company, Young Indian, which is controlled by Sonia and Rahul Gandhi, the ED alleged. Both Sonia and Rahul are out on bail in the case.

Veer Savarkar College to reserve seats for Roshanpura villagers as DU expands after 30 years

The college is set to begin admissions for the academic session 2025-26, marking a major milestone in the university's expansion after nearly 30 years.

NEW DELHI. In a significant move, Delhi University's Veer Savarkar College will reserve two seats in each course for applicants from Najafgarh's Roshanpura village, which donated land for the establishment of the new institution. One of these reserved seats will be for female students to promote gender inclusion.The college is set to begin admissions for the academic session 2025-26, marking a major milestone in the university's expansion after nearly 30 years. Located just five minutes from DU's West Campus, Veer Savarkar College is being built at an estimated cost of Rs 140 crore, covering a built-up area of 18,816.56 square metres.In an announcement, DU Vice Chancellor Yogesh Singh said, "In a positive and progressive step, the university has decided to

reserve two seats per course for the children of those who donated land for the college. Out of the two, one seat will be reserved for a girl student." The new campus will feature 24 classrooms, eight tutorial rooms, 40 faculty rooms, department libraries, conference rooms, and a canteen.

"We are starting two four-year undergraduate programs — B.Sc Computer Science and Bachelor of Business Administration (BBA) — at Veer Savarkar College for this academic session. In both programs, two seats will be reserved for students from Roshanpura village," Singh added.Each course will have 60 seats in total. The college, which is built on land donated by Roshanpura's residents, will maintain this reservation policy even as more courses are introduced. Veer Savarkar College is part of a larger initiative by Delhi University to expand its infrastructure.This is the first major expansion in nearly three decades, with two additional campuses under development — the East Campus in Surajmal Vihar and the West Campus in Dwarka Sector 22. Prime Minister Narendra Modi laid the foundation stone for these campuses.

JNUSU election process begins after delays; ABVP, AISA, SFI file nominations ahead of April 25 polls

NEW DELHI. After a prolonged delay caused by administrative and legal hurdles, the election process for the Jawaharlal Nehru University Students' Union (JNUSU) finally commenced on Tuesday, with various organizations filing their nominations.The Election Committee also released the voter list, confirming that 7,906 students are eligible to vote in this year's elections. Notably, 43% of registered voters are women.

On the same day, the Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP) announced its probable candidates for the JNUSU elections. The list includes Thite Shambhavi Pramod, Anuj Damara, Kunal Rai, Vikas Patel, Rajeshwar Kant Dubey, Shikha Swaraj, Nittu Goutham, Arun Srivastava, and Akash Kumar Ravani.These candidates have submitted their nominations, and after scrutiny, the final list of four candidates for the JNUSU Central Panel posts—president, vice-president, general secretary and joint secretary—will be confirmed. ABVP activists have already begun intensive

campaigns across hostels and classrooms, highlighting the organisation's constructive contributions over the past six years. Similarly, members of the All India Students Association (AISA) and Students' Federation of India (SFI) also filed their nominations.

The nomination correction window opened on Tuesday, with withdrawals set to take place on Wednesday. In addition to the central panel elections, voting will be held for 42 councillor positions representing 16 schools and a special combined centre at the university. The JNUSU elections will take place on April 25.

ABVP's Central Election Coordinator for JNUSU elections, Arjun Anand, said, "We are fully prepared for the elections and committed to promoting responsible leadership by selecting dedicated, aware and active student leaders.

Vellore waqf shocker shows why law didn't trigger CAA-like protests

NEW DELHI. A fortnight since Parliament passed the Waqf Amendment (2025) Bill, the protests predicted by the Opposition and Muslim organisations during the debate have been missing from the ground. Many naysayers and opponents of the Bill had warned of widespread protests by Muslims, saying they would resemble the unrest that followed the Citizenship Amendment Act and the proposed National Register of Citizenship. But, apart from the concentrated violence in some parts of Bengal and scattered protests in the southern states, the response to the amendments has been muted.

So, why have the predictions of gloom and doom among Muslims been proven wrong? One reason is the arbitrary manner in which properties are claimed as waqf assets.Last week, a notice from a local mosque and dargah shocked around 150 families of Kattukollai village in Tamil Nadu's Vellore district. The notice, from the Kilandai Masjid and the Hazarath Syed Ali Sultan Shah Dargah, declared that the land these families owned for generations was now Waqf property. It demanded that they either vacate their homes or pay rent to the dargah management.

The notice triggered panic among villagers, who marched to the Vellore District Collector's office with valid title documents, pleading for intervention to protect the homes and lands they had occupied for generations.This wasn't an isolated incident. In 2022, a similar case jolted Tamil Nadu's Tiruchendurai village, where the local waqf committee claimed 480 acres of land, including a vast stretch belonging to a 1500-year-old Chola-era temple.

Both these districts have around 15% of Muslim population. The arbitrary manner in which the ancestral land belonging was claimed -- a flaw in the pre-amendment waqf laws the government aims to address -- shows that the waqf boards spare none, not even members of their own community, for whose benefit these assets are purportedly donated.

Plea in Delhi HC seeks revival of contempt case over axing of ad-hoc Law Officers in jails

Despite the Delhi Prisons Act mandating a Law Officer in every jail, only one currently serves all 16 jails.

NEW DELHI. A fresh petition has been filed before the Delhi High Court, seeking the revival of a contempt case in connection with the alleged abrupt termination of ad-hoc Law Officers across Delhi's prison system. The plea argues that this act amounts to willful disobedience of the Court's specific directives issued on September 27, 2019.

The petitioner contends that the discontinuation of these temporary appointments, without the creation of corresponding regular posts, demonstrates clear contempt of court.

The Director General of Tihar Jail and other senior prison officials have been named as respondents for allegedly failing to comply with judicial instructions. The origins of the case lie in a petition filed by Advocate Amit Sahni, a social activist, which was disposed of by a High Court order directing the authorities to complete the recruitment of Law Officers for Delhi's jails, preferably within twelve weeks of receiving the order.

When these directions were not acted upon within the stipulated period, Advocate Sahni initiated contempt proceedings. During the hearings, the respondents informed the court that 16 Law Officers had been appointed on an ad-hoc basis. On the basis of this assurance, the Court disposed of the contempt case December 21, 2021.

However, the current plea states that

despite the passage of more than five years since the initial order, and over three years since the contempt case was closed, no genuine steps have been taken to regularise the posts of Law Officers. On the contrary, the ad-hoc appointments themselves have now been withdrawn.

The plea highlights an order dated April 2, 2025, issued by the Office of the Director General (Prisons), Government of NCT of Delhi, which abruptly ends even the temporary engagement of law graduates fulfilling the role of Law Officers. The petitioner argues that this latest development is yet another instance of wilful disobedience of the Division Bench's directions.

The earlier petition had already underscored the glaring inadequacy in prison legal staffing. Despite the statutory requirement under the Delhi Prisons Act, 2000, which mandates the presence of a designated Law Officer in every jail, only one Law Officer currently serves all 16 jails in the capital, stationed at the Tihar headquarters. It had further been revealed that between August 2016 and February 2019, no Law Officer was appointed at the prison headquarters at all.According to Section 6 of the Delhi Prisons Act, each prison must have essential personnel, including a superintendent, deputy superintendent, medical officer, Law Officer, welfare officer, and other staff.

NEWS BOX

KFC worker killed in Pak as Islamist party activists ransack outlet, open fire

world. An employee of American fast-food chain KFC was killed in an attack carried out by members of the radical Islamist group Tehreek-i-Labbaik Pakistan (TLP) during an anti-Israel demonstration in Pakistan's Punjab province, police said on Tuesday.

The incident took place in Sheikhupura, some 50 kilometers from the capital Lahore.

According to police, a large group of TLP activists stormed the KFC outlet early morning.While vandalising the restaurant, the attackers opened fire on staff members. One employee, identified as Asif Nawaz and believed to be in his 40s, was fatally shot, while others managed to flee.

"When police reached the spot, the miscreants had fled," an official said, adding that over three dozen suspects have been detained, and an investigation is ongoing.Just a day prior, TLP supporters had also targeted a KFC outlet in Rawalpindi, damaging the property.Similar attacks were reported last week in Karachi and Lahore, where parts of KFC outlets were set on fire. Punjab police have since arrested 17 TLP members linked to those incidents.

The Pakistani government and security agencies appear to be struggling to contain the wave of TLP-led violence against foreign fast-food chains under the guise of religious protests.

Major Solar storm could bring Aurora Borealis to New York, Kentucky

world. A strong geomagnetic storm caused by a series of solar outbursts could illuminate the skies over much of the northern U.S., with the potential for the Northern Lights to reach as far south as Kentucky on Tuesday evening into early Wednesday morning.

The storm, rated a G3 on the National Oceanic and Atmospheric Administration's (NOAA) five-point geomagnetic scale, is considered "strong." The Space Weather Prediction Center has issued a geomagnetic storm warning. These storms occur when charged particles from the Sun collide with Earth's magnetic field, creating breathtaking aurora displays and occasionally disrupting communication systems.The most dramatic aurora displays are expected over the Rocky Mountains and Western states around sunrise on Wednesday, according to the FOX Forecast Center. Chicago and Frankfort, Kentucky, may enjoy better views due to clearer sky conditions. However, much of the Northeast, including most of Pennsylvania, might experience cloud cover that could block visibility.For best viewing, experts recommend heading away from city lights to areas with minimal light pollution and an unobstructed view toward the northern horizon. While auroras often appear more vivid in long-exposure photographs, strong displays can also be seen with the naked eye.

While the Northern Lights may dazzle skywatchers, geomagnetic storms can have broader impacts. The G3-level event could disrupt radio communications and interfere with GPS navigation. NOAA forecasts that the storm's strength will decrease to a G1 level by Thursday and fall below G1 by Friday.The unusual opportunity to view the aurora borealis at lower latitudes has created a buzz among star-gazers throughout the U.S. The people wanting to view the performance should check forecasts and sky conditions at local levels Tuesday evening through early Wednesday morning.

Bahamas Suspends SpaceX Rocket Landings Pending Post-Launch Probe

Washington. The Bahamas' government said on Tuesday it is suspending all SpaceX Falcon 9 rocket landings in the country, pending a full post-launch investigation."No further clearances will be granted until a full environmental assessment is reviewed," Bahamian Director of Communications Latrae Rahming said in a post on X.SpaceX did not immediately respond to a request for comment.

The Bahamian government said in February after SpaceX's first landing in the country that it had approved 19 more throughout 2025, subject to regulatory approval.The Bahamas' post-launch investigation comes after a SpaceX Starship spacecraft exploded in space last month, minutes

after lifting off from Texas.Social media videos showed fiery debris streaking through the skies near South Florida and the Bahamas after the spacecraft broke up in space shortly after it began to spin uncontrollably with its engines cut off.

Following the incident, the Bahamas said debris from the spacecraft fell into its airspace. The country said the debris contained no toxic materials and added it was not expected to have a significant impact on marine life or water quality.

The Starship explosion was not connected to the Bahamas' Falcon 9 landing program with SpaceX.

Chinese Economy Grew 5.4% In First Quarter Amid New US Tariffs

Beijing and Washington are locked in a fast-moving, high-stakes game of brinkmanship since US President Donald Trump launched a global tariff assault that has particularly targeted Chinese imports.

Beijing, China. China on Wednesday said its economy grew a forecast-beating 5.4 percent in the first quarter as exporters rushed to get goods out of factory gates ahead of swingeing new US tariffs.

Beijing and Washington are locked in a fast-moving, high-stakes game of brinkmanship since US President Donald Trump launched a global tariff assault that has particularly targeted Chinese imports.

Tit-for-tat exchanges have seen US levies imposed on China rise to 145 percent, and Beijing setting a Official data Wednesday offered a first glimpse into how those trade war fears are affecting the Asian giant's fragile recovery, which was already feeling the pressure of persistently low consumption and a property market debt crisis.Beijing's National Bureau of Statistics (NBS) said that "according to preliminary estimates, the gross domestic product in the first quarter... (was) up by 5.4 percent year on year at constant prices".

That was above the 5.1 percent predicted by analysts polled by AFP ahead of the data release.Industrial output also soared 6.5 percent in the first quarter of the year, up from 5.7 percent in the final three months of 2024.And retail sales, a key gauge of consumer demand, climbed 4.6 percent year-on-year, the NBS said.But Beijing warned the global economic environment was becoming more "complex and severe" and that more was needed to boost growth and consumption."The foundation for sustained economic recovery and growth is yet to be consolidated," the NBS said, adding there was a need for "more proactive and effective macro policies".

US judge stops Trump admin from deporting Indian student weeks before graduation

world. A US federal judge on Tuesday temporarily halted the removal of a University of Wisconsin-Madison student from India whose visa was terminated from the Student and Exchange Visitor Program (SEVIS) database.Judge William Conley ruled to block the Department of Homeland Security (DHS) from immediately deporting 21-year-old Krish Lal Isserdasani, who claimed his F-1 student visa was wrongfully terminated. Krish, who is an engineering student, is set to graduate in May."He was given no warning, no opportunity to explain or defend himself, and no chance to correct any potential misunderstanding before his F-1 student visa record was terminated in SEVIS," the order said.The April 15 order prevents the Department of Homeland Security from revoking the student visa or detaining Isserdasani.

According to the order, Isserdasani was arrested on November 22, 2024, on suspicion of misdemeanour disorderly conduct after he and his friends got into an argument with another group of people after leaving a bar.

His student visa was cancelled on April 4. Judge William Conley of the Western District of Wisconsin handed down the order, saying Isserdasani was not

convicted of a crime, and his claim of wrongful visa termination had a "reasonable likelihood of success" in the courts. He set a preliminary injunction hearing for April 28.Lotfi said that the order is believed to be one of the first national victories for international student visa holders whose records were terminated. About 1,300 students nationwide have seen their SEVIS records terminated abruptly.Several US colleges have reported an increase in visa cancellations among international students, including some from India.

In many cases, the students had no known connection to recent pro-Palestinian protests on campus. Instead, officials have cited past traffic infractions as reasons for revoking their visa.Indian students are among those affected, even if they had not participated in physical demonstrations that invited the wrath of the Trump administration. Indian students in the US have had their visas revoked despite being innocent or over minor infractions that do not merit visa cancellation. This includes cases involving minor traffic violations, like speeding. In several of the cases, visas have been cancelled despite courts having found the Indian students not guilty.

Melinda French Gates opens up about divorce: 'I had to leave'

Melinda French Gates opened up about her split from Bill Gates, citing lack of honesty. She's healing through therapy, embracing new love, and inspiring others through her memoir and personal transformation.

world. Philanthropist Melinda French Gates has opened up about her split from Microsoft co-founder Bill Gates. In an interview on The Late Show with Stephen Colbert on April 14, Melinda shared how she came to the painful decision to end their 27-year marriage.

"To have a trusted relationship, both partners must be honest," she told Colbert. "And if you don't have honesty, you can't have intimacy or trust. Ultimately, I had to leave."Melinda revealed that therapy helped her navigate the emotional challenges of the divorce. In her memoir, she discusses staying true to herself while dealing with "betrayals" in the marriage, all while keeping the separation private for over a year.

In an interview with PEOPLE magazine, Melinda emphasized the importance of authenticity: "You have to stay true to yourself always." She added that sharing her story was a way to connect with others going through similar transitions.During her appearance on Colbert's show, Melinda also confirmed that she is now in a "pretty great" relationship. While she didn't name

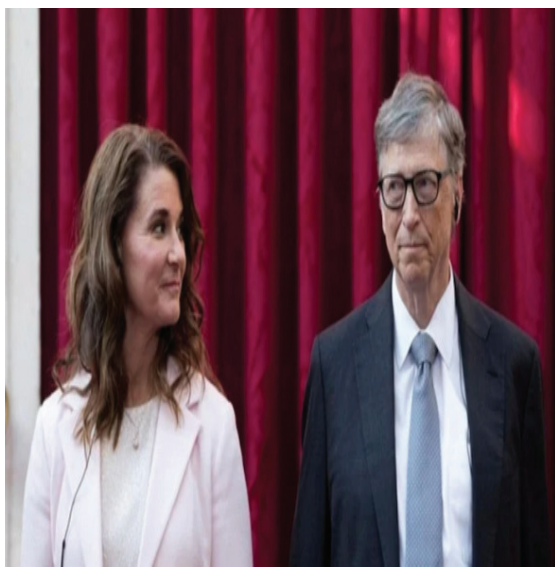

her partner, she has previously been photographed with businessman Philip Vaughn. In her PEOPLE interview, she said she was "very, very happy" and open to this new chapter in her life.Following the divorce, Melinda focused on reconnecting with herself—going on a "freedom tour" with friends to Mexico. "Transitions can be scary, exhilarating, or both," she said.

Bill Gates has also spoken publicly, calling the divorce "tough" and his "biggest regret" during a January interview. He added that despite the outcome, he would still choose the marriage for all the positives they created together.

France expels 12 Algerian diplomats over Paris kidnappinag scandal

France expelled 12 Algerian diplomats and recalled its ambassador over the kidnapping of activist Amir Boukhors. Alleged consular involvement has reignited diplomatic tensions, further straining France – Algeria relations already weakened by past disputes.

world. France has expelled 12 Algerian diplomatic and consular officials and recalled its ambassador from Algiers, intensifying an already strained diplomatic row between the two countries. The move follows accusations by Paris that Algerian authorities are to blame for the worsening of bilateral ties.

The tensions center on the kidnapping of Amir Boukhors, a prominent Algerian activist and social media personality known online as Amir DZ. A vocal critic of Algerian President Abdelmadjid Tebboune, Boukhors has lived in France since 2016 and was granted political asylum in 2023.In April 2024, Boukhors was abducted outside his home in Val-de-Marne, near Paris. Speaking to France 2 television, he claimed that four men wearing police armbands kidnapped him, drugged him, and held him in a container for more than 24 hours. "I fell into a trap," he said.Three suspects have since been arrested and charged with kidnapping and arbitrary detention. French prosecutors revealed that one of the suspects worked at the Algerian consulate in Crteil, intensifying the diplomatic fallout.

Algeria has denied any official involvement, rejecting the claim that its consular staff were implicated. In

retaliation, Algiers expelled 12 French diplomats, prompting Paris to respond in kind by ejecting an equal number of Algerian officials and recalling its envoy.Franco-Algerian relations, long marked by historical tensions, have remained delicate. Relations further soured in 2023 after President Emmanuel Macron expressed support for Morocco's claim over Western Sahara—at odds with Algeria's stance.Although French Foreign Minister Jean-Nol Barrot had recently suggested a thaw in relations, this incident has reignited hostilities.

Adding to the strain, Macron has called on Algeria to release celebrated author Boualem Sansal, 75, who was sentenced to five years in prison for allegedly "undermining the integrity" of the Algerian state.

Amid Trump's tariff war, China issues over 85,000 visas to 'Indian friends'

The Chinese Embassy in India has issued more than 85,000 visas to Indian citizens between January 1 and April 9, 2025, highlighting a major effort to enhance people-to-people connections between the two countries.Chinese Ambassador to India Xu Feihong invited more Indians to visit China and experience its "open, safe, and friendly environment"."As of April 9, 2025, the Chinese Embassy and Consulates in India have issued more than 85,000 visas to Indian citizens traveling to China this year. Welcome more Indian friends to visit China, experience an open, safe, vibrant, sincere and friendly China," Xu said in a post on X.Visa numbers are showing a marked increase, with 85,000 issued in just the first four months of 2025, compared to 180,000 throughout 2023. Last year, the Chinese embassy updated its visa application requirements, introducing several key relaxations.Indian applicants no longer need to book an online

appointment before submitting their visa applications. Instead they can directly submit them at visa centres during working days. Additionally, individuals applying for short-term, single or double-entry visas for stays under 180 days are exempt from providing biometric data, such as fingerprints.Along with these changes, the Chinese Embassy has also reduced visa application fees, introducing new, lower charges for applicants.

TRUMP'S TARIFF WAR

China announced the updated figures at a time when US President Donald Trump rammed up warnings of potential trade tariffs on almost every country, zeroing in on China, which is Washington's prime trading partner and economic adversary.Trump has raised US tariffs on Chinese imports to 145 per cent while halting new tariffs on goods from other countries. In retaliation, China has imposed a 125 per cent tariff on American products.

China has also urged India and other countries to stand with it in opposing what it called the "US tariff abuse".Yu Jing, spokesperson for the Chinese embassy in India, last week, said India and China, as the two largest developing countries, should unite against the US tariff actions.

NEWS BOX

Making Riyan Parag RR stand-in captain over me was the correct call: Nitish Rana

New Delhi . Rajasthan Royals batter Nitish Rana has supported the decision to make Riyan Parag the stand-in skipper of the team ahead of him when Sanju Samson was recovering from his injury. Riyan was the skipper for three games, as Samson was used as an impact sub by the Royals during the same timeframe. The Assam star guided RR to one win during his time as skipper against CSK.

While Nitish was the skipper of KKR in the 2023 season and had experience, he had no issues with RR overlooking him for Riyan. Speaking at the pre-match press conference before the Delhi game, the southpaw said that he was with KKR for 6 to 7 years before he was made skipper, as he understood the team environment betterNitish felt with Riyan, it was the right call as he has been

with the setup since 2019. Nitish also said he would have been open to the captaincy if it was offered to him.When I was made captain of KKR, I had been with the team for 6-7 years. That helped a lot because I understood the team culture and environment. Now, with RR, I think Riyan knows the team's setup better than me. And I think it was absolutely the right decision by the management.""If they had asked me, of course, I would've happily accepted the captaincy. But what matters most is what's right for the team. And I think they made the correct call," said Nitish.

Trying to fulfil the team's demands

Speaking about his low scores this season, Nitish said that he didn't get a few chances in game as the emphasis was on the left-right combination. The 31-year-old said that his aim is to fulfil the demands set forward by the team."Things are very different on the ground. Sometimes the match situation demands something else. Often, a left-right combination becomes very important in a format like the IPL. In a couple of matches, I didn't get much chance to bat."

Ajinkya Rahane blames lack of clarity with Angkrish for review horror in PBKS vs KKR

New Delhi . KKR captain Ajinkya Rahane blamed a lack of clarity in communication with Angkrish Raghuvanshi for the review horror during the loss to PBKS. Rahane and Angkrish were in cruise control of the run chase when Yuzvendra Chahal was able to trap the KKR skipper in front of the stumps. Instead of going for a review, Rahane decieed to walk off and it proved to be the turning point in the game.KKR went from 62 for 2 to 95 all-out as PBKS defended 111 runs to record a historic win on the night in Mullanpur. Speaking at the post-match press conference, Rahane said that he was thinking about saving the review for later and the communication with Angkrish wasn't clear in the end.Yes, it happened. As a batter, I

thought maybe I should save the review for later. You don't want to waste a review early and regret it later. Also, the communication between me and the non-striker wasn't very clear. If someone clearly tells you the impact might be outside or the ball might be missing, then as a batter you're more confident in taking the review. But that clarity was missing. Still, no complaints. Regardless of the review, our batting performance was poor, and that's the reason we lost the match," said Rahane.

'Weren't complacent'However, the KKR captain said that his side's batting was poor in the end and that was the reason why they lost the game.Rahane said that his side wasn't complacent in the loss against PBKS and it was down to the fact that they didn't play well in the end. The KKR skipper felt that his side didn't show game awareness in the end.

"Not really. All the boys are confident and experienced enough to handle situations. I wouldn't say we were complacent. We just didn't play well. That's the honest truth. It wasn't about taking things lightly. We didn't show the game awareness needed for the situation. When we lost those 3–4 wickets, it was about taking your time, rotating strike, and playing smart cricket. That was missing," said Rahane.

Champions League: Barcelona, PSG into semis after surviving Villa, Dortmund comeback

FC Barcelona and PSG narrowly escaped Champions League heartbreak as Dortmund and Aston Villa threatened major comebacks in two dramatic second-leg encounters. A Guirassy hat-trick and a Villa fightback made it close, but the giants held on—just.

New Delhi . Champions League football at its best came very close to causing quarter-final nightmares for both FC Barcelona and Paris Saint-Germain yet again, but Borussia Dortmund and Aston Villa's fire just fell short. April 16 served up two end-to-end thrillers, which saw both PSG and Barcelona lose their second-leg clashes to Dortmund and Aston Villa respectively, but narrowly win on aggregate to secure their places in the semi-finals.While the Champions League quarter-finals are often known for historic "remontada" or comeback specials, both Dortmund and Villa came into Wednesday's ties chasing exactly that. A Guirassy hat-trick in Dortmund's 3-1 win over Barcelona couldn't secure a semi-final spot, as an own goal saw the German side lose on aggregate by 3-5.Meanwhile, PSG also suffered a 3-2 loss to Aston Villa but ultimately ended up winning on aggregate 5-4.

Barcelona's Guirassy Scare

Borussia Dortmund's "remontada" looked increasingly possible—and so did yet another heartbreak for FC Barcelona—and it was all because of Serhou Guirassy's brilliance. From the very beginning at Signal Iduna Park, Guirassy became the Dortmund danger man Barcelona simply couldn't get a hold of.

Starting with a converted penalty in the 11th minute, the Guinean striker made it 2-0 (and 4-2 on aggregate) just four minutes into the second half, heading in a well-placed corner. The assist provider behind that goal, Ramy Bensebaini, later faced a nightmare moment when a strike from Fermin Lopez ricocheted off his shin and into his own net.Despite Guirassy completing his hat-trick with a sharp finish in the 76th minute, Barcelona held on to win 5-3 on aggregate and secure a semi-final berth.

Donnarumma Carries PSG to Semis

In what could have been a far worse outing for PSG, it was goalkeeper Gianluigi Donnarumma's heroics that pushed them into the semi-fina stage despite a 3-2 loss to Aston Villa.

After Achraf Hakimi's 11th-minute goal and Nuno Mendes' strike in the 27th gave PSG a comfortable 5-1 aggregate lead, Villa's late resurgence put the game in the balance. Youri Tielemans scored in the 34th minute, followed by second-half goals from John McGinn and Ezri Konsa that set up a tense finish.However, Donnarumma stepped up with key saves to deny Villa multiple golden chances to complete a sensational comeback.

NBA Play-in tournament: Warriors defeat Grizzlies in 121-116 thriller behind Curry, Butler

New Delhi . The Golden State Warriors edged out the Memphis Grizzlies in a thriller 121-116 victory in NBA Play-in tournament showdown on Tuesday, April 15 at Chase Center. Stephen Curry and Jimmy Butler III powered the Warriors to the win, combining for 75 points as Golden State advanced to face the Houston Rockets in the first round of the NBA Playoffs.

Butler's strong start, Warriors' defence set the tone

Golden State jumped to a 31-25 lead at the end of the first quarter, thanks to a late 28-29 run over the final 7:47. Jimmy Butler III led the way with 10 points on perfect shooting from beyond the arc, tying his season-high for threes in a first quarter. The Warriors also recorded five steals, matching their best single-quarter mark of the season.Memphis, meanwhile, struggled early, shooting 38.1% from the field and committing seven turnovers. Jaren Jackson Jr. added eight points for the Grizzlies with two three-pointers, while rookie Zach Edey grabbed six rebounds.By halftime, the Warriors extended their lead to 67-55. Butler paced Golden State with 21 points, tying his season-high last achieved against Detroit on December 16, 2024. Curry added 15 points while shooting 50% from the field and a perfect 9-for-9 from the free-throw line.The Warriors shot 50% overall and 40% from three. Despite a quiet offensive start, Edey recorded a career-high nine rebounds

by halftime for the Grizzlies, who continued to struggle with turnovers, committing 10 by the break.

Grizzlies respond in third quarter despite Morant injury

Memphis responded in the third quarter with renewed energy, outscoring the Warriors 36-27 to close the gap to 94-91. The comeback came even after Ja Morant appeared to sprain his ankle at the 4:25 mark, landing on Buddy Hield's foot. Morant stayed down for several minutes before heading to the bench in visible pain but returned in the fourth quarter, limping but determined.The Grizzlies bench stepped up, with Post shooting 3-of-4 from deep. Desmond Bane matched Curry with 22 points by the end of the third, shooting 3-of-4 from beyond the arc.The Grizzlies tied the game early in the fourth quarter after trailing by 20, making it 94-94 with 11:29 left. But Golden State responded down the stretch. Jimmy Butler III delivered a season-high 38 points, while Curry finished with 37. Butler's performance surpassed Curry's previous single-game high of 28 points for the season.

Memphis kept pushing behind Bane's 30 points and Edey's 17 rebounds, despite his early foul trouble and a tough first half that drew criticism from NBA analyst Charles Barkley."[Edey's] only got five points... If you're gonna get abused on defense, you better make up for it on the offensive end," Barkley said during the halftime broadcast.Key fouls, clutch free throws seal win for WarriorsGolden State capitalised on key fouls in the closing minutes.

LA 2028 Olympics: South California city of Pomona to host cricket

New Delhi . The LA28 Organising Committee has announced that the Fairgrounds in Pomona, Southern California, will host cricket at the Los Angeles 2028 (LA28) Olympic Games.

Cricket will return to the Olympic Games from July 14 to 30, marking its first appearance since 1900. Back then, Great Britain faced France in a two-day match."Cricket (T20), a globally renowned sport that was added to the 2028 Olympic sport programme in 2023, will make its Southern California debut at the Fairgrounds in Pomona in a temporary, purpose-built structure," the Games organisers announced.Pomona is approximately 50 kilometers east of Los Angeles, and the Fairgrounds, formally known as Fairplex, is a 500-acre site that has hosted the Los Angeles County Fair since 1922.The International Cricket Council (ICC) has welcomed the announcement.ICC Chairman Jay Shah said in a release, "We welcome the announcement of the venue for cricket in Los Angeles 2028, as it is a significant step towards the preparation for

our sport's return to the Olympics.""Although cricket is already a hugely popular sport, featuring it at the Olympics in the fast-paced, exciting T20 format presents a fantastic opportunity to expand its traditional boundaries and attract new audiences."Cricket was officially added to the Los Angeles Olympics programme during the IOC's 141st Session in Mumbai in October 2023. It joins five other new sports at LA28: baseball/softball, flag football, lacrosse (six-a-side), and squash.Six cricket teams will compete in the men's and women's competitions at the LA28 Olympic Games.

The sport has been allocated 90 athlete quotas, allowing for six-team competitions in both the men's and women's events, with each team comprising 15 players. The qualification criteria for these teams are yet to be finalised.

The T20 format, recognised by the ICC as a key driver of the sport's global expansion, has been featured in other multi-sport events in recent years.

Moving Shreyas Iyer from No.3 for Glenn Maxwell Ricky Ponting has hilarious response

New Delhi . PBKS coach Ricky Ponting had a hilarious response to the suggestion to move Shreyas Iyer from number three and use Glenn Maxwell there. Shreyas has been a revelation at No.3 for Punjab this season and has scored 250 runs in 6 matches while Maxwell has scored just 41 coming in the middle order.The Australian has done well in the IPL coming up the order and Robin Uthappa suggested it to Ponting after the win over KKR. The PBKS coach joked that if he wanted to remain in the job, he shouldn't be moving the captain around. Ponting also said that the idea of the Punjab batting order isn't about the numbers and it is about injecting them into the game at the right moment."Yeah, we've got a guy called Shreyas Iyer at number 3. If I want to stay in my job, I'm probably not going to move the captain. So as we all know, the captain sets

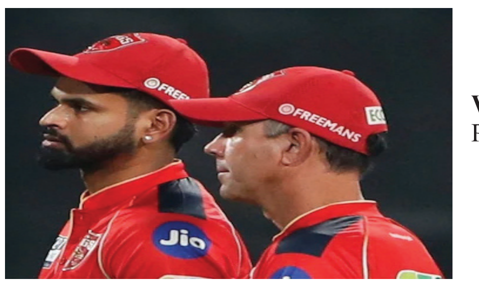

the batting order. He's pretty happy at number 3 and he's been outstanding in the tournament. So you know we're always trying to find the right time in the game. It's not about numbers that these guys bat. It's about the right time that you can inject them into the game. So we've got good flexibility with our batting order. We've moved a few guys around already this season. As things go on, and we come up with a more settled side, there probably won't be guys moving around too much," said Ponting.

Why Stoinis missed KKR game

Ponting also commented on the decision to drop Marcus Stoinis for the game and said it was a tactical one to bring in Josh Inglis into the side as he was better against spin and they wanted to keep Marco Jansen and Glenn Maxwell in the side for the matchups with the ball."Yeah, a tough decision to leave Stoinis out, you know, we wanted to bring Inglis into the side. Inglis is a noted player of spin that doesn't look that good way tonight, but he is a very, very good player of spin. His keeping is as good as anyone's in the world as well, and we wanted the matchups with the ball with Marco.

PSG, Villa players hold back laughs as Europa anthem played before CL clash

- Europa League anthem blunder left players stifling pre-match laughs
- Youri Tielemans couldn't hide reaction as anthem error played
- Villa scare PSG with late surge despite awkward start

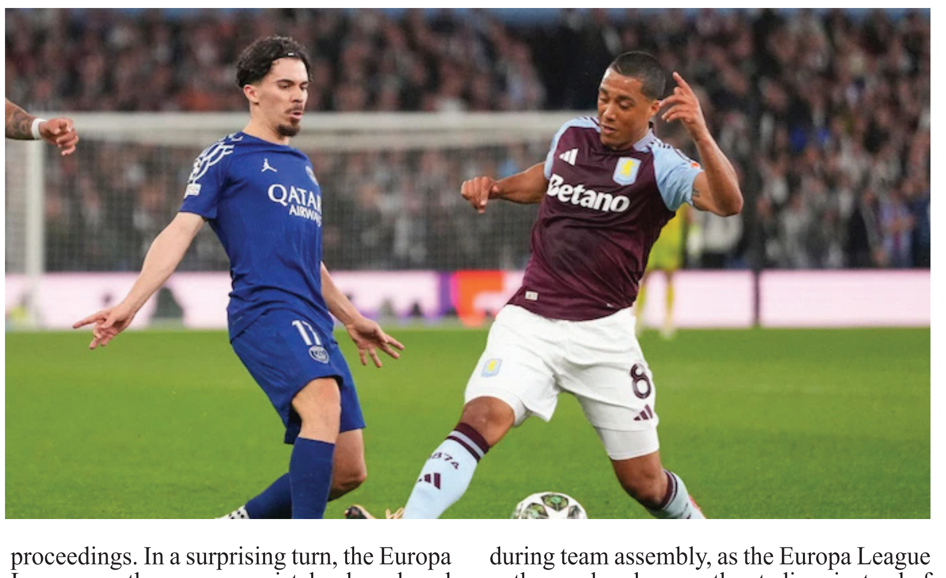

Birmingham With Aston Villa all set to take on Paris Saint-Germain in their UEFA Champions League quarter-final second leg at home, a moment of confusion and some light-hearted chuckles marked the pre-match proceedings. In a surprising turn, the Europa League anthem was mistakenly played ahead of kickoff.The high-stakes clash at Villa Park began with muffled laughter during team assembly, as the Europa League anthem echoed across the stadium instead of the iconic Champions League choir. The mix-up caused visible amusement among players from both sides, with Villa's Youri Tielemans notably struggling to hold back his laughter.Ahead of what eventually turned into a dramatic clash between PSG and Aston Villa—where the hosts were eyeing a comeback—the anthem confusion sparked a buzz among the fans too. Supporters in the stands could be seen reacting to the mistake as the wrong anthem played over the sound system.Despite the technical blunder, Villa's performance on the pitch was no joke. After PSG's Achraf Hakimi opened the scoring in the 11th minute and Nuno Mendes followed with a goal in the 27th to give the visitors a 5-1 aggregate lead, Villa mounted a spirited comeback. Tielemans kicked things off with a goal in the 34th minute, followed by second-half strikes from John McGinn and Ezri Konsa that threw the game wide open.

However, PSG goalkeeper Gianluigi Donnarumma came to the rescue with a series of crucial saves, denying Villa a full comeback and ensuring the Parisians advanced to the semi-finals despite a 3-2 defeat on the night.

THE PHOTON NEWS

www.thephotonnews.com
Thursday, 17 April 2025

Years After Kidney Failure,

Sherlyn Chopra

Launches NGO For Underprivileged Patients

Beyond her professional endeavours, Sherlyn Chopra has embarked on a journey to become a philanthropist. In a noble mission, she launched an NGO Prakasham earlier this month. Her new venture aims at providing support and care for underprivileged children who lack basic necessities like education and healthcare. Furthermore, it also extends helping hands to underprivileged kidney patients in the country, as the actress mentioned in her new post on Instagram to share the good news.The post features a video of Sherlyn as she talked about the reason behind launching her NGO. Recalling her battle with kidney failure, the actress shared that she decided to take a step towards the progress of underprivileged children during the tough phase of her life. Further, she said that launching the organisation is nothing short of a dream come true. Alongside the clip, Sherlyn wrote, "Prakasham foundation is a small step towards helping and caring for underprivileged children & underprivileged kidney patients in our country. Huge thanks to the team of volunteers, doctors and specialists associated with prakasham foundation."

Earlier, in a chat with Siddharth Kannan, Sherlyn Chopra reflected on her battle with kidney failure. She shared, "I had kidney failure in 2021, and I thought I would die. Then I realised that I had so much more work to do with Ekta ji (Ekta Kapoor) and that I had to clinch some great works. I made the decision not to give up. The doctor presented two options: either dialysis or a kidney transplant. However, my family doesn't love me enough to donate a kidney. For dialysis, I would have had to go to the hospital thrice a week, and I didn't want that in my life."

In terms of work, Sherlyn Chopra was last seen in the third season Paurashpur 2, released in 2024 on ALTT. The show, set in a fictitious realm of Paurashpur, delves into themes of authority, politics and intense emotions.

Its cast also includes Deepak Qazir, Mahi Kamla, Ananya Samarth, Amit Pachori, Dinesh Kanwar Mehta, Aryan Harnot, Priom Gujjar, Kaushiki Rathore and Shivangi Roy.

Sherlyn Chopra began her career in Bollywood in the early 2000s. The actress went on to feature in films like Time Pass (2005), Dosti: Friends Forever (2005) and Raqeeb (2007). She also participated in several reality shows, including Bigg Boss Season 3 in 2009.

Jasmin Bhasin

Recreates Kajol's K3G Look As She Joins Laughter Chefs 2 To Support Aly Goni

Television actress Jasmin Bhasin made heads turn as she arrived on the sets of Laughter Chefs 2 in Mumbai. While Aly Goni joined the show recently, his ladylove Jasmin will also appear as a guest, and will be seen supporting him. What's interesting is that Jasmin was dressed as Kajol from the film 'Kabhi Khushi Kabhie Gham', and it piqued fans' excitement for the upcoming episode.Jasmin Bhasin was spotted by the paparazzi as she arrived on the sets of Laughter Chefs season 2 to shoot for the upcoming episode. She was seen recreating Kajol's look from K3G, and donned a similar ethnic blue suit which consisted of a short kurti, Patiala salwar, and a matching dupatta. Her hair was tied back in a long braid, and she wore beautiful jhumkas, and matching bangles. She asked the paparazzi to guess who she is dressed as. When the paps correctly guessed Kajol, she playfully told them, "Aap jeette hain 5 crore! (You win Rs 5 crore)." Check out the video below!

Fans went gaga over Jasmin Bhasin's look. One fan commented, "She literally slayyeddd," while another one wrote, 'Wow lgta h ab dekhna padega purne contestants aa rhe h." A third netizen commented, "Kajol vibes."

Aly Goni, who was part of Laughter Chefs' season 1, recently returned for its second season. The makers are bringing back several familiar faces from the first season, leaving fans super-excited for the upcoming episodes. Reem Shaikh and Nia Sharma also joined the show. Meanwhile, Jasmin Bhasin will reportedly appear as a guest on Laughter Chefs 2.

Apart from Jasmin, many other celebs were seen with

Bollywood-inspired looks as they arrived for Laughter Chefs 2 shoot. While Vicky Jain dressed up as Kartik Aaryan's Rooh Baba from Bhool Bhulaiyaa 2, Rubina Dilaik channelled Sridevi from Mr India. Nia Sharma was seen as Deepika Padukone from Chennai Express, while Reem recreated Kangana Ranaut's character from Queen.

Ibrahim Ali Khan Confesses He Was 'Obsessed' With Deepika Padukone As A Kid: 'My First Crush Ever'

Saif Ali Khan and Amrita Singh's son, Ibrahim Ali Khan, recently sat down with Filmfare for a candid interview, where he opened up about his childhood, growing up in a famous family, and his relationship with his parents. When asked about the moment he first realised his parents were celebrities, Ibrahim shared a vivid memory from his early years.He recalled being around seven or eight years old when it first truly hit him. At the time, his father, Saif Ali Khan, was shooting in the UK for Imtiaz Ali's Love Aaj Kal alongside Deepika Padukone. That's when young Ibrahim began to understand the scale of his parents' stardom — not just as actors, but as public figures whose lives were always under the spotlight. He said, "I don't know. I was quite young when I realised that they're famous. I remember I was like seven or eight years old. My dad was shooting for Imtiaz Ali's Love Aaj Kal in the UK. What a movie!"

Ibrahim also let slip a sweet confession from that time — he had a huge crush on Deepika Padukone! In fact, she was his very first crush. He admitted that as a young boy, he was completely obsessed with her and would eagerly look for chances just to catch a glimpse of her while she was shooting with his father. He said, "I was like, wow. Deepika Padukone. That's when I had my first crush ever. I was so small and I was obsessed with her. I was like I want to see Deepika. And that's when I realised my dad is a big actor. Deepika Padukone is doing a movie with him."

Ibrahim says his dad always made it clear that they're famous. He added, "And my mom always made me feel like she's just a sweet, urban Punjabi mother. My mother is a Punjabi mom. So I'm actually quite Punjabi also. Or maybe not. I don't know. Whatever I am. I'm crazy. That's because of her. She's raised two crazy people. Me and my sister, Sara Ali Khan. She's also quite crazy. It's not like we pretend that we're crazy. We're pretty crazy."

Shilpa Shetty's Red Carpet-Worthy Look Is A Masterclass In Fusion Fashion

Shilpa Shetty is one of the B-town actresses who never fails to inspire with her impressive fitness and fashion choices. Recently, the actress served up some serious style goals in an Indo-western ensemble. She shared a video of herself striking stunning poses on her Instagram Stories.She donned a two-piece red-hued set that included a tulle jacket with intricate cutdana hand embroidery, a V-neckline, and full sleeves. The jacket was paired with a satin organza draped skirt, featuring a gorgeous pleated design. Shilpa completed her look with statement jewellery, including dangler earrings, bold rings, and peach-hued heels that added a perfect finishing touch to her glamorous appearance.

Coming to her makeup and hair, the star opted for freshly blushed and highlighted cheeks and bold red lipstick. Kohl-rimmed eyes with winged eyeliner and mascara-laden lashes added an oomph factor to her face. Finally, to seal the deal, she opted for middle-parted wavy tresses that perfectly cascaded down her shoulders.The 49-year-old actress has already impressed her millions of fans with her acting spree in multiple films like Dhadkan, Life in a Metro, Baazigar, Main Khiladi Tu Anari, Phir Milenge, Rishtey, Azaad, and many others. She was last seen in the 2023-released movie Sukhee and the 2024-released web series Indian Police Force. Next, she will be seen in a Kannada film titled KD – The Devil, in the role of Satyavathi Agnihotri. The movie, scheduled for a release in 2025, is currently undergoing post-production.

Apart from her acting and fashion prowess, Shilpa Shetty is also a successful entrepreneur and the proud owner of the popular Mumbai-based restaurant, Bastian. The upscale eatery has become a celebrity hotspot over the years.

Recently, rapper Honey Singh paid a visit to Bastian and appeared completely mesmerised by its opulent interiors. The singer shared a short video clip from inside the restaurant on his Instagram Stories, expressing his admiration for the stunning decor and overall vibe of the place.

Alongside the picture, he wrote that the restaurant "feels like pyramids."